6 | संपादकीय
जनसत्ता | 7 फरवरी, 2026

कल्पमेधा

कुछ लोग उन चीजों को देखते हैं, जो हैं और पूछते हैं कि वे ऐसी क्यों हैं। मैं उन चीजों के स्वप्न देखता हूं, जो कभी नहीं थीं और कहता हूं कि वे क्यों नहीं हो सकती हैं।
– जार्ज बर्नार्ड शा

कसौटी पर चुनाव

देश में चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों की ओर से मतदाताओं को रिझाने के लिए जिस तरह मुफ्त तोहफों या उपहारों की राजनीति की जा रही है, उसने एक तरह से नतीजों की शुचिता को कसौटी पर रख दिया है। भारतीय राजनीति में पिछले कई वर्षों से यह प्रवृत्ति जटिल होती गई है। हालांकि इस मसले पर सवाल भी उठे हैं और मुफ्त तोहफों के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने को लोकतंत्र के लिए एक घातक चलन बताया गया है। विडंबना यह है कि लगभग सभी राजनीतिक दल इस प्रवृत्ति पर सवाल उठाते हैं, लेकिन मौका मिलने पर वे भी इसी तरीके को एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं। खासतौर पर जो दल या गठबंधन सत्ता में होते हैं, वे वादों या घोषणाओं के साथ-साथ चुनावों के ठीक पहले कोई योजना या कार्यक्रम लागू करने के जरिए भी मतदाताओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुफ्त उपहारों को भारतीय राजनीति में एक घातक प्रवृत्ति बताया है, लेकिन इस पर रोक को लेकर अब तक कोई ठोस नियमन सामने नहीं आ सका है।

यही वजह है कि आज राजनीतिक दलों के बीच एक तरह की होड़ देखी जाती है कि वोट हासिल करने के लिए मतदाताओं को कौन कितना ज्यादा लाभ पहुंचाने की घोषणा करता है। नतीजतन, स्वच्छ चुनाव और विवादरहित नतीजे आज एक सदिच्छा की तरह लगने लगे हैं। राजनीतिक दलों से यह उम्मीद करना मुश्किल हो गया लगता है कि इस दिशा में वे अपनी ओर से कोई ऐसी पहल करेंगे, जो चुनावी जीत के लिए मुफ्त की रेवड़ियों के चलन पर रोक लगाएं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मसले पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी है, तो इससे एक बार फिर मुफ्त की चुनावी रेवड़ियों पर लगाम लगने की उम्मीद जगी है। गौरतलब है कि करीब चार साल पहले सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने केंद्र और निर्वाचन आयोग से उस याचिका पर जवाब मांगा था, जिसमें चुनाव से पहले 'अतार्किक मुफ्त उपहार की घोषणा' या इसे वितरित करने वाली राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिह्न जब्त या उसका पंजीकरण रद्द करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। उस समय पीठ ने इसे गंभीर मुद्दा करार दिया था और कहा था कि कभी-कभी मुफ्त उपहार योजना का बजट नियमित बजट से अधिक हो जाता है।

सवाल है कि अगर कोई मतदाता मुफ्त की सौगात दिए जाने के असर में किसी उम्मीदवार को वोट देता है, तो क्या यह एक तरह की सौदेबाजी नहीं कही जाएगी? अगर कोई सत्ताधारी पार्टी चुनावों के ठीक पहले किसी योजना या कार्यक्रम के जरिए मतदाताओं को आर्थिक लाभ पहुंचाती है, तो उसकी जीत को कितना निष्पक्ष माना जाएगा? दिनोंदिन बढ़ती मुफ्त उपहारों की राजनीति के बीच होने वाले चुनाव को किस हद तक स्वच्छ और स्वतंत्र कहा जाएगा? अफसोस की बात यह है कि लंबे समय से इस पर सवाल उठने के बावजूद अब तक इस दिशा में ऐसा कानून जमीन पर नहीं दिखता है, जो राजनीतिक दलों को मतदाताओं के सामने मुफ्त उपहारों का लोभ परोसने और इसके जरिए उनका वोट हासिल करने की कोशिश करने से रोक सके। यह स्पष्ट होना चाहिए कि 'अतार्किक मुफ्त उपहार' के चुनावी वादे मतदाताओं को गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश हैं और इससे न केवल राजनीतिक दलों के बीच स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा बुरी तरह प्रभावित होती है, बल्कि निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता भी दूषित होती है।

जवाबदेही के बजाय

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस वर्ष जनवरी के पहले पखवाड़े में आठ सौ से अधिक लोगों के लापता होने की खबरों से जहां लोग भय और चिंता के साथ खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं, वहीं कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली जैसा शहर, जहां सुरक्षा के तमाम आधुनिक इंतजाम होने के दावे किए जाते हैं, वहां अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग लापता हो रहे हैं, तो यह वास्तव में गहरी चिंता का विषय है। सवाल है कि इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेने, उन पर अंकुश लगाने और लोगों के मन में सुरक्षा का भाव एवं भरोसा बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? स्थानीय पुलिस का तो कहना है कि गुमशुदा मामलों के आंकड़ों से लोगों को घबराने या दहशत में आने की जरूरत नहीं है। दलील दी जा रही है कि पिछले वर्ष इसी अवधि के मुकाबले इस बार लापता लोगों की संख्या में कमी आई है। यानी गत वर्ष जनवरी के शुरुआती दो सप्ताह में इससे भी कहीं ज्यादा लोग लापता हुए थे! इससे पुलिस की लापरवाही और असंवेदनशीलता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।

दिल्ली पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, एक से 15 जनवरी के बीच कुल 807 लोगों की गुमशुदगी के मामले सामने आए। यानी इस दौरान प्रतिदिन औसतन 54 लोग देश की राजधानी से लापता हुए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि लापता व्यक्तियों से संबंधित सभी शिकायतों को तुरंत दर्ज किया जाता है और उनकी जांच की जाती है। अगर इन दावों को सच मान भी लिया जाए, तो सवाल यह है कि पुलिस का काम क्या सिर्फ किसी अपराध के बाद अपराधी को पकड़ने का ही है? किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस आत्ममुग्ध होकर अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन क्या अपराध होने से पहले ही उसे रोक देने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है! पुलिस का यह कहना कि कुछ लोग पैसों के लिए इस तरह की खबरों को बढ़ा-चढ़ा कर प्रचारित एवं प्रसारित कर रहे हैं, वास्तव में उसकी व्यवस्थागत खामियों और नाकामियों को ही उजागर करता है, जिसे दुरुस्त किया जाना बेहद जरूरी है।

अरावली की दरारें बड़े खतरे का संकेत

उपग्रह आधारित अध्ययनों में अरावली पर्वतमाला में बारह दरारें देखी गई हैं। इस कारण रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने की इसकी क्षमता कमजोर हो रही है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो परिणाम भयावह हो सकते हैं।

प्रमोद भार्गव

अरावली की पहाड़ियों में उत्खनन से बढ़ रहे खतरे का संकेत पर्यावरण के संरक्षक यों ही नहीं दे रहे थे। इन अनुमानों का सत्य इस पर्वतमाला में पड़ी बारह दरारों से सामने आ गया है। इस कारण अरावली पर्वत शृंखलाएं न केवल लगातार कमजोर हुई हैं, बल्कि माना जा रहा है कि ये थार रेगिस्तान से पूर्व की ओर खिसकना शुरू हो गई हैं। इस कारण राजस्थान के जयपुर सहित हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र तथा गंगा-यमुना के मैदानी इलाकों के पर्यावरण पर गंभीर एवं विपरीत असर पड़ने का खतरा बढ़ गया है। यह जानकारी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पिछले दिनों जारी एक रपट में दी गई है। इसमें वर्ष 1972-75, 1982-84, 1994-96 और विशेष रूप से 2005-2007 के कालखंड में किए गए क्रमिक उपग्रह आधारित अध्ययनों का हवाला दिया गया है।

इस रपट के अनुसार, अरावली पर्वतमाला पर बनी बारह बड़ी दरारों के माध्यम से रेगिस्तानी रेत पूर्व की ओर बढ़ रही है। वर्ष 2005-07 के बाद अरावली की रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली क्षमता में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि इसी दौर में गुड़गांव समेत दिल्ली-आसपास के क्षेत्र में शहरीकरण के साथ औद्योगिक और प्रौद्योगिकी विस्तार के लिए वनों की कटाई के साथ व्यापक स्तर पर पत्थर उत्खनन हुआ है। इसके नतीजतन पर्वतमाला की बारह प्रमुख दरारें अजमेर की मगरा पहाड़ियों से निकलकर झुंझूनूं के खेतड़ी और माधोगढ़ होते हुए हरियाणा के महेंद्रगढ़ तक फैल गई हैं। इन्हीं कमजोर हिस्सों से थार रेगिस्तान की रेत पूर्व की ओर बढ़ रही है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने भी अपने अध्ययन से चेताया था कि आने वाले वर्षों में रेगिस्तान से उठने वाले रेत के तूफान दिल्ली और एनसीआर तक पहुंचकर इनके पर्यावरण को गंभीर रूप से बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। मगर इन सर्वेक्षणों और अध्ययनों को संबंधित राज्यों एवं केंद्र सरकार ने शायद गंभीरता से नहीं लिया है।

अरावली की पहाड़ियां दुनिया की प्राचीनतम पर्वत शृंखलाओं में से एक हैं। लगभग 692 किलोमीटर के दायरे में फैली ये पहाड़ियां गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक पसरी हैं। इन पहाड़ियों का मानव समुदाय के लिए गहरा प्राकृतिक महत्त्व है। इस क्षेत्र में रहने वाले जीव-जगत की सांसें इन पर्वतमालाओं से गुजरने वाली शुद्ध हवा पर निर्भर है। इन्हीं पहाड़ियों की ओट पश्चिमी रेगिस्तान को फैलने से रोके हुए है, अन्यथा हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जो उपजाऊ भूमि है, उसे रेगिस्तान में तब्दील होने में समय नहीं लगेगा। इन पहाड़ियों की हरियाली नष्ट होने से आसपास के क्षेत्र में शुष्कता का विस्तार हो रहा है और गर्मी बढ़ रही है। इसके परिणामस्वरूप भू-जल स्तर भी आशंका से कहीं ज्यादा नीचे जा रहा है। लोगों में सांस और दमा की बीमारियां बढ़ रही हैं।

रपट में कहा गया है कि अरावली पर्वत शृंखला सामान्य परिस्थितियों में तापमान को डेढ़ से ढाई डिग्री तक नियंत्रित रखने और भू-जल के पुनर्भरण में अहम भूमिका निभाती है। इनमें प्रति हेक्टेयर बीस लाख लीटर भू-जल पुनर्भरण की अद्वितीय क्षमता है। इन पहाड़ियों के लगातार क्षरण एवं मरुस्थलीकरण के खतरे से दिल्ली और आसपास के भू-भागों का तापमान

बढ़ा है और धूल से भरी आंधियों की अवधि बढ़ने के साथ इनकी तीव्रता में भी तेजी आई है। पर्यावरण विशेषज्ञों का अनुमान है कि हरियाणा की 8.2 फीसद भूमि मरुस्थलीकरण के दायरे में है, क्योंकि वर्ष 2019 तक ही अरावली का लगभग 5.77 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र उत्खनन से तबाह

> पारिस्थितिकीय रूप से अरावली पर्वतमाला बेहद महत्त्वपूर्व है। इसीलिए इसके व्यापक पुनर्स्थापन और संरक्षण की जरूरत है, न कि पहाड़ियों को पुनर्भाषित करके इनके दोहन को बढ़ावा देने की? ये पर्वतमाला मैदानी क्षेत्रों को रेगिस्तान में बदलने से तो रोकती ही है, इन्हीं पहाड़ियों में कई छोटी-बड़ी नदियों के उद्‌गम स्थल हैं। अनेक झील, झरने और तालाब इस पर्वत शृंखला के बीच में प्राकृतिक रूप से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, जो न केवल क्षेत्र के जीव-जगत को पानी उपलब्ध कराते हैं, बल्कि भूजल पुनर्भरण का काम भी करते हैं।

हो चुका था। इससे स्पष्ट है कि विकास की प्रक्रिया में अवैज्ञानिक तरीकों की जानकारी होने के बावजूद अरावली संकट को नजरअंदाज किया गया है।

पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर अरावली पहाड़ियों को नए सिरे से परिभाषित किया गया। इस परिभाषा से संरचनात्मक विरोधाभास की स्थिति निर्मित हुई और लगा कि इससे अनियंत्रित खनन को बढ़ावा मिल सकता है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी रपट में न्यायालय को बताया था कि सौ मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पर्वतमाला माना जाएगा। अर्थात निन्यानबे मीटर तक की ऊंची पहाड़ियां अरावली के हिस्से से बाहर हो जातीं। इससे अरावली के बड़े क्षेत्र में उत्खनन का रास्ता खुल जाता। इससे यह आशंका भी पैदा हुई कि आखिर सरकार इन पहाड़ियों को इस तरह से परिभाषित करके किसके हित साधना चाहती है? जबकि इन पहाड़ियों की ऊंचाई के कारण ही ये प्राकृतिक रूप से उड़ने वाली धूल को रोकने का काम करती हैं। इसके साथ ही सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि अरावली के कुल 1.44 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में से फिलहाल 0.19 फीसद भू-भाग में ही उत्खनन के पट्टे दिए जा रहे हैं। हालांकि बाद में तर्कों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली की परिभाषा से संबंधित अपने निर्देशों पर रोक लगा दी।

अरावली पर्वतमाला पारिस्थितिकी रूप से बेहद महत्त्वपूर्ण हैं। इसीलिए इसके व्यापक पुनर्स्थापन और ठोस संरक्षण की जरूरत है, न कि पहाड़ियों को पुनर्भाषित करके इनके दोहन को बढ़ावा देने की? ये पर्वतमाला मैदानी क्षेत्रों को रेगिस्तान में बदलने से तो रोकती ही है, इन्हीं पहाड़ियों में कई छोटी-बड़ी नदियों के उद्‌गम स्थल हैं। अनेक झील, झरने और तालाब इस पर्वतमाला के बीच में प्राकृतिक रूप से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, जो न केवल क्षेत्र के जीव-जगत को पानी उपलब्ध कराते हैं, बल्कि भूजल पुनर्भरण का काम भी करते हैं। यही नहीं, इन पहाड़ियों के गर्भ में इमारती पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट और चूना बड़ी मात्रा में समाया हुआ है। साथ ही जस्ता, तांबा, लेड और टंगस्टन जैसे दुर्लभ खनिज भी इनकी कोख में मौजूद हैं। मगर इस खनिज संपदा के दोहन के लिए पहले यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पर्यावरण को किसी तरह की क्षति न पहुंचे।

इसे वर्तमान विकास की विडंबना ही कहा जाएगा कि अधिकतम प्राकृतिक संपदाओं के दोहन को आधुनिक एवं आर्थिक विकास का नीतिगत आधार बना दिया गया है। इस बात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि हमारे यहां जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, उस लिहाज से मौजूदा आर्थिक विकास की निरंतरता कैसे बनी रह सकती है। यह सवाल भी अनुत्तरित है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर विकास को आगे बढ़ाना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। दीर्घकालिक दृष्टि से देखें, तो विकास की यह अवधारणा उस बहुसंख्यक आबादी के लिए जीने का भयावह संकट खड़ा कर सकती है, जिसकी रोजी-रोटी की निर्भरता प्रकृति पर ही अवलंबित है। हालांकि अरावली पर्वतमाला में पड़ी कई दरारों को लेकर उपग्रह सर्वेक्षणों के खुलासे और पर्यावरणविदों की राय के बाद शीर्ष न्यायालय ने इस मसले पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है। इसलिए यह उम्मीद बंधी है कि अरावली संकट से जुड़े तमाम पहलुओं पर अब नए सिरे से बहस होगी और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी चिंता का समाधान औद्योगिक विकास एवं वाणिज्यिक लाभ-हानि के गुणा-भाग से परे जल, जंगल और जमीन के रख-रखाव के पैमाने पर होगा।

दुनिया मेरे आगे

सुविधा का पाठ

राजेंद्र जोशी

सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली एक जीवंत लोकतांत्रिक समाज का मजबूत आधार है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) ने इसे परिवर्तित, सुधारे गए और अधिक सक्षम बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए हैं। चाहे सरकार द्वारा संचालित स्कूल हों या निजी संस्थान, शिक्षा सब तक समान रूप से पहुंचनी चाहिए। शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से काम करने की संस्कृति एक जैसी होनी चाहिए। अगर शिक्षा प्रणाली और प्रबंधन में एकरूपता आ जाए, तो वर्ग-भेद मिट जाएंगे। शिक्षा के मंदिरों का स्वरूप भी लगभग एक समान होना चाहिए। निजी विद्यालयों पर नियमों की भरमार हो और सरकारी स्कूलों में उनकी अनदेखी हो, यह स्वीकार्य नहीं। अगर निजी स्कूल संसाधनों या नियमों के अभाव में कमजोर पड़ते हैं, तो उनकी मान्यता रद्द हो सकती है। उसी प्रकार, सरकारी विद्यालयों में नियमों की अवहेलना पर उनकी मान्यता रद्द करने का प्रावधान अनिवार्य होना चाहिए।

एनईपी-2020 शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक और योजनाबद्ध तरीके का भरोसा दिलाती है। पांच वर्ष बीतने के बावजूद इसके उज्ज्वल परिणाम अभी देखना शेष है, लेकिन यह स्कूलों, संस्थानों, शिक्षकों, अधिकारियों, समुदायों और हितधारकों को सशक्त बनाने तथा संसाधनों से परिपूर्ण रखने वाली संस्कृति विकसित करने का वादा करती है। साथ ही, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण पर जोर दिया गया है। शिक्षा संस्थानों में उपयोगी संसाधनों का समुचित उपयोग सभी को लाभान्वित करता है। स्कूल प्रबंधन में खेलकूद के साधन, कक्षाओं की उपलब्धता और स्थानीय नागरिकों का जुड़ाव शिक्षा व्यवस्था को ऊर्जावान बनाता है। मगर बच्चों के लिए आवश्यक संसाधनों के अभाव में बीच में पढ़ाई छोड़ने की समस्या बनी रहती है। विशेष रूप से छात्राओं के लिए स्कूल समय के दौरान निजी जरूरतों की व्यवस्था पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है।

> भारत जैसे विकासशील देश में अधिकांश स्कूलों में- चाहे वे केंद्र या राज्य सरकार के हों या निजी- छात्राओं के लिए पर्याप्त शौचालयों का अभाव है। मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता की मूलभूत सुविधाओं का न होना छात्राओं को शिक्षा से दूर कर देता है।

भारत जैसे विकासशील देश के अधिकांश स्कूलों में- चाहे वे केंद्र या राज्य सरकार के हों या निजी- छात्राओं के लिए पर्याप्त शौचालयों का अभाव है। मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता की मूलभूत सुविधाओं का न होना छात्राओं को शिक्षा से दूर कर देता है। अगर शौचालयों के साथ-साथ सैनिटरी पैड और माहवारी स्वच्छता के मौलिक अधिकार पर ध्यान न दिया जाए, तो छात्राओं की स्कूल से दूरी बढ़ती जाएगी। आमतौर पर देखा जाता है कि सरकारी स्कूलों में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा सैनिटरी पैड मशीनें लगाई जाती हैं, लेकिन कुछ समय बाद खराब होने पर ये सरकार की प्राथमिकता सूची से बाहर हो जाती हैं। अनेक मामलों में शौचालय ताले में बंद रहते हैं, जिससे छात्राओं को खुले में शौच के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि सामाजिक कुप्रथा को भी बढ़ावा देता है।

विचित्र है कि भारत में ऐसे जरूरी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट या अन्य न्यायालयों को सक्रिय होना पड़ता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रबंधन शिक्षा-शास्त्रियों और उच्च वेतनभोगी नौकरशाहों की सोच का हिस्सा क्यों नहीं बन पाता? सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में स्कूलों में छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालयों का निर्माण अनिवार्य किया है, ताकि छात्राएं अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग कर सकें। यह सुविधा मध्य, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। फिर भी, जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन कमजोर है। सरकार को प्रत्येक स्कूल में छात्राओं को जैविक रूप से अपघटनीय सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने चाहिए। स्कूल प्रबंधन सरकारी हो या गैर-सरकारी, अगर शौचालय या स्वच्छता संबंधी सुविधाएं प्रदान करने में असफल रहता है, तो उनकी जवाबदेही तय करते हुए मान्यता रद्द की जानी चाहिए। नई शिक्षा नीति केवल पढ़ने-लिखने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। प्रबंधन के दृष्टिकोण से इसके मसविदे पर पुनर्विचार आवश्यक है। छात्राओं के लिए माहवारी स्वच्छता को नीति का प्रभावी हिस्सा बनाना होगा।

नई शिक्षा नीति- 2020 ने स्कूलों को संसाधन-संपन्न बनाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का वादा किया है, लेकिन छात्राओं की इन बुनियादी जरूरतों पर ठोस प्रावधानों का अभाव है। अगर इस संवेदनशील विषय पर ध्यान न दिया गया, तो बीच में पढ़ाई छोड़ने की समस्या तो बढ़ेगी ही, साथ ही लिंग भेदभाव गहरा जाएगा। छात्राएं शिक्षा से वंचित रहेंगी, जो राष्ट्र निर्माण के लिए घातक होगा। सरकार, शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन को जरूरी कदम उठाने चाहिए। प्रत्येक स्कूल में छात्राओं के लिए अलग, स्वच्छ और कार्यशील शौचालय अनिवार्य किए जाने की जरूरत है। अनेक अध्ययनों में यह तथ्य उजागर हो चुका है कि स्वच्छ शौचालय और पेयजल के अभाव के कारण बहुत सारी लड़कियां अपनी स्कूली पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं। इसके अलावा, माहवारी से जुड़ी परेशानियों को लेकर भी समाज में लोग सहज नहीं होते और इसका खमियाजा महिलाओं और लड़कियों को उठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जैविक रूप से अपघटनीय सैनिटरी पैड स्कूल प्रबंधन द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मशीनों के रखरखाव के लिए नियमित निगरानी और कोष सुनिश्चित करने की जरूरत है। मान्यता रद्द करने जैसे सख्त प्रावधान लागू किए जाने चाहिए। जागरूकता अभियान चलाकर मासिक धर्म को संकीर्ण सोच से मुक्त किए जाने की जरूरत है। यदि एनईपी को इन मुद्दों से समृद्ध किया जाए, तो यह वास्तव में समावेशी और सशक्तीकरण लाने वाली बनेगी। आधी आबादी को शिक्षा का पूर्ण अधिकार दिलाने के लिए अब ठोस कार्रवाई जरूरी है।

जोखिम में जिंदगी

सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति के नए अवसर दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही दिखने और छा जाने की एक नई होड़ पैदा हुई है। बीते कुछ समय में देश के अलग-अलग हिस्सों से सामने आई घटनाएं बताती हैं कि रील बनाने का जुनून कितना जानलेवा साबित हुआ है। रेल पटरियों, ऊंचे पुल और पहाड़ी रास्ते अब केवल आने-जाने के मार्ग नहीं रहे, बल्कि 'कंटेंट' बनाने के मंच बनते जा रहे हैं। कुछ सेकंड के वीडियो के लिए जीवन को जोखिम में डालना एक खतरनाक प्रवृत्ति का संकेत है। पहले जरूरत पड़ने पर जोखिम उठाया जाता था, आज यह मनोरंजन बन गया है। मोबाइल कैमरा चालू होते ही खतरा रोमांच में बदल जाता है। शायद यह वह दौर है, जहां पहचान मेहनत या कौशल से नहीं, बल्कि चर्चित होने से तय होने लगी है। जब 'लाइक' और दर्शक संख्या सफलता का पैमाना बन जाएं, तो विवेक पीछे छूटना स्वाभाविक है। यह पीढ़ी ऐसे डिजिटल माहौल में बड़ी हो रही है, जहां हर समय तुलना, प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन का दबाव है। परिवार, विद्यालय और समाज कई बार इसे 'आजकल का चलन' मान कर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जब कोई हादसा होता है, तब वही समाज शोक में डूब जाता है।

– राकेश खुडिया, श्रीगंगानगर

संकट में पक्षी

'बढ़ते शोर से संकट में पक्षियों का जीवन' (आलेख, 2 फरवरी) पढ़ा। एक ओर पहले ही शहरी विकास ने इन पक्षियों के रहने की जगह खत्म कर दी है, दूसरी ओर ध्वनि प्रदूषण ने उनके अस्तित्व के लिए संकट पैदा कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार, दुनिया में अनेक पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। एक समय था जब आंख खुलते ही पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई पड़ता था। वह मनमोहक सुबह पूरे दिन हमें तरोताजा बनाए रखती थी, लेकिन समय के साथ आज हम उन पक्षियों से दूर होते चले गए हैं और कुछ का तो अस्तित्व ही खतरे में है। खुद के घर आबाद करने के फेर में हमने उन खूबसूरत पक्षियों के घरों यानी पेड़ों का सफाया कर दिया। गांवों में तो फिर भी ये देखने को मिल जाएंगे। इनके संरक्षण के लिए सरकारों के साथ स्थानीय स्तर पर समाज को भी आगे आना पड़ेगा। पक्षियों का हमारे बीच रहना स्वस्थ पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है।

– साजिद अली, इंदौर

प्रदूषण और कैंसर

एक समय था जब कैंसर के रोगी इक्का-दुक्का सुनने में आते थे। इसे अब तक लाइलाज बीमारी माना जाता रहा है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने इस धारणा को काफी हद तक बदल दिया है। आज कैंसर का इलाज संभव है, बशर्ते उसकी समय पर पहचान और सही उपचार हो। समाज में आज भी कैंसर को लेकर भय और भ्रांतियां बनी हुई हैं। कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे प्रदूषण और नशीली सामग्री का बड़ा योगदान है। पंजाब में बढ़ते नशे और औद्योगिक प्रदूषण जैसे कारणों से कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ी है। वहां से कैंसर अस्पताल जाने वाली ट्रेन को लोग 'कैंसर एक्सप्रेस' कहने लगे हैं। आज चिकित्सा विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि प्रारंभिक अवस्था में कैंसर की पहचान होने पर इसका सफल इलाज संभव है। आवश्यकता केवल जागरूकता और नियमित स्वास्थ्य जांच की है। प्रदूषण से बचाव, नशे से दूरी और खानपान में सावधानी ही इस बीमारी से लड़ने के सबसे प्रभावी हथियार हैं।

– हिमांशु शेखर, गयाजी

हवा में जहर

वायु प्रदूषण अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल हो चुका है। आज हमें एक साथ मिल कर इस विषय पर गंभीर योजना बनाने की जरूरत है। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इस समस्या से निपटने के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि भी हो। काफी समय से यह देखा जा रहा है कि प्रदूषण के कारण लोगों के जीवन पर काफी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। कह सकते हैं कि यह एक चिंताजनक स्थिति है। आज देश भर में वायु प्रदूषण फैल गया है। इसके साथ ही नदियों में भी कल-कारखानों से निकला गंदा पानी चला जाता है। फिर यही पानी कुओं और बोरिंग के माध्यम से हमें भी पीने को मिल रहा है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस समस्या को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

– एमएम राजावतराज, शाजापुर

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को धोखाधड़ी वाले लेनदेन पर कहा

गलती से 'ओटीपी' साझा होने पर 25 हजार की क्षतिपूर्ति

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 फरवरी।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने शुक्रवार को ग्राहकों को धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए 25,000 रुपए तक की क्षतिपूर्ति देने की घोषणा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मुंबई में संवाददाताओं को बताया कि ग्राहकों को यह क्षतिपूर्ति उन मामलों में भी दी जाएगी जहां ग्राहक गलती से अपना 'वन-टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) धोखेबाजों के साथ साझा कर देते हैं।

केंद्रीय बैंक के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह राशि 85,000 करोड़ रुपए के जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष से ग्राहकों को दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राहक को जीवन में केवल एक बार ही क्षतिपूर्ति मिलेगी और वह भी तब जब धोखाधड़ी का कोई गलत इरादा न पाया जाए। आरबीआइ के अधिकारियों ने कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों में दो-तिहाई मामले 50,000 रुपए

मल्होत्रा ने कहा कि जब तक उनके साथ धोखाधड़ी होती है, चाहे वह स्वयं की गलती से हो या किसी और की, बिना सवाल पूछे 25,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा।

से कम के हैं। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी से प्रभावित लोगों में से ज्यादातर को इस सुविधा से लाभ होगा। मल्होत्रा ने कहा कि जब तक उनके साथ धोखाधड़ी होती है, चाहे वह स्वयं की गलती से हो या किसी और की गलती से, बिना कोई सवाल पूछे 25,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। हम उन्हें तभी क्षतिपूर्ति देंगे जब लेनदेन अनजाने में हुआ हो और उन्होंने अपना पैसा गंवाया हो। उन्होंने कहा कि ग्राहकों की भागीदारी सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है और धोखाधड़ी की राशि का 15 फीसद खाताधारक को वहन करना होगा, भले ही धोखाधड़ी 25,000 रुपए की सीमा से कम हो। उच्च मूल्य की धोखाधड़ी के मामलों में, क्षतिपूर्ति 25,000 रुपए तक सीमित रहेगी। मल्होत्रा ने कहा कि क्षतिपूर्ति की रूपरेखा का मसविदा जल्द ही सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया जाएगा। डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने कहा कि यह राशि जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष (डीईए) से दी जाएगी। इसमें 10 साल से अधिक समय से बिना दावे वाली जमा राशि भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य उस विशेष वर्ग को कवर करना है, जो अनजाने में इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। इसलिए, क्षतिपूर्ति का वित्तीय बोझ बहुत अधिक नहीं होगा। मल्होत्रा ने यह भी घोषणा की कि आरबीआइ धोखाधड़ी को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लेकर आएगा। इसमें विलंब से क्रेडिट और वरिष्ठ नागरिकों जैसे विशिष्ट वर्ग के उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण शामिल हो सकते हैं।

मौद्रिक नीति से शेयर बाजार में तेजी, सूचकांक 266 अंक मजबूत

भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से नीतिगत ब्याज दरों को स्थिर रखने और 'रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट' (रीट) को कर्ज देने की मंजूरी के प्रस्ताव के बाद घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को चढ़कर बंद हुए। सूचकांक में 266 अंक की बढ़त रही जबकि निफ्टी 51 अंक की तेजी में रहा। कारोबारी सत्र के अंतिम चरण में हुई लिवाली से बीएसई का 30 शेयर वाला मानक सूचकांक 266.47 अंक यानी 0.32 फीसद चढ़कर 83,580.40 अंक पर बंद हुआ।

छोटी एनबीएफसी को मिली राहत

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अनिवार्य पंजीकरण से छूट देने का प्रस्ताव दिया। इसके लिए एनबीएफसी की संपत्ति 1,000 करोड़ रुपए से कम होनी चाहिए और उनमें सार्वजनिक धन नहीं लगा होना चाहिए।

यूपीआइ को टिकाऊ बनाने, बुनियादी ढांचे में सुधार के तरीके खोजेगा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय बैंक लोकप्रिय भुगतान मंच यूपीआइ को हितधारकों के लिए टिकाऊ बनाने और इसके बुनियादी ढांचे में सुधार सुनिश्चित करने के तरीके खोजेगा। उन्होंने फरवरी की मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद यहां संवाददाताओं से कहा कि हम निश्चित रूप से न केवल इस बहुत महत्वपूर्ण भुगतान बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए, बल्कि इसमें सुधार करने का एक रास्ता खोजने में सक्षम होंगे। यह पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में बहुत ही अनूठा रहा है। इससे ग्राहकों के लिए भुगतान बुनियादी ढांचे से जुड़ी चिंताओं को दूर करने में मदद मिलेगी।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे 2027 तक तैयार होगा

केवल बारह घंटे में ही पूरा हो जाएगा सफर, दिल्ली को भी जाम मुक्त बनाने की तैयारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 6 फरवरी।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे 2027 तक पूरा होगा। इस मार्ग से मुंबई का सफर केवल 12 घंटे में पूर्ण किया जा सकेगा। अभी इस यात्रा में करीब 33 घंटे का समय लगता है।

शुक्रवार को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मार्ग की मदद से आर्थिक एकीकरण में जबरदस्त सुधार होगा। इसके अतिरिक्त केंद्र

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि इसकी मदद से आर्थिक एकीकरण में सुधार होगा। बजट में मार्ग परियोजनाओं के लिए केंद्रीय बजट में सड़क बुनियादी ढांचे के लिए लगभग तीन लाख करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

सरकार द्वारा दिल्ली को भी जाम मुक्त बनाने की कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि इस बार बजट में देश के मार्ग परियोजनाओं के लिए केंद्रीय बजट में सड़क बुनियादी ढांचे के लिए लगभग तीन लाख करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। इस आवंटन से देश में सड़कों का जाल बिछाने के कार्य में मदद मिलेगी। ज्ञात हो कि दिल्ली मुंबई योजना केंद्र सरकार की अहम योजनाओं में से एक है और इसके तहत 1350 किलोमीटर लम्बे मार्ग के जरिये दिल्ली- मुंबई को जोड़ने की तैयारी है।

इस कार्य को कई चरण में किया जा रहा है और यह सरकार के हरित राजमार्ग गलियारों में से एक है। यह मार्ग पूर्ण होने से हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को लाभ होगा।

विदेशी मुद्रा भंडार 723.77 अरब डालर के उच्चस्तर पर

मुंबई, 6 फरवरी (भाषा)।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 30 जनवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान 14.36 अरब डालर बढ़कर 723.77 अरब डालर के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने यह जानकारी दी है। इससे पिछले सप्ताह में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 8.05 अरब डालर बढ़कर 709.41 अरब डालर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। इससे भी पहले सितंबर, 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार 704.89 अरब डालर की ऊंचाई पर पहुंचा था। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 30 जनवरी को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा माने जाने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 49.3 करोड़ डालर घटकर 562.39 अरब डालर रह गईं। डालर के रूप में व्यक्त की जाने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर अमेरिकी मुद्राओं में मूल्य वृद्धि या मूल्यह्रास के प्रभाव शामिल होते हैं।

रिजर्व बैंक ने कहा कि समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार का मूल्य 14.59 अरब डालर बढ़कर 137.68 अरब डालर हो गया।

रुपया 31 पैसे टूटकर 90.65 प्रति डालर पर बंद

मुंबई, 6 फरवरी (भाषा)।

अमेरिका-ईरान वार्ता को लेकर बनी भू-राजनीतिक अनिश्चितता और कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि होने से शुक्रवार को रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 31 पैसे टूटकर 90.65 प्रति डालर पर बंद हुआ।

विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, रुपया सत्र के पहले भाग में रिजर्व बैंक द्वारा मुख्य ऋण दरों को यथावत रखने की घोषणा के बाद थोड़ा मजबूत हुआ, लेकिन विदेशी निवेशकों की लगातार पूंजी निकासी ने घरेलू मुद्रा पर दबाव डाला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डालर के मुकाबले 90.28 पर खुला और सत्र के दौरान 90.18 के ऊपरी स्तर और 90.83 के निचले स्तर तक गया। कारोबार के अंत में यह 31 पैसे टूटकर 90.65 रुपए प्रति डालर पर बंद हुआ। डालर के मुकाबले रुपया गुरुवार को 13 पैसे मजबूत होकर 90.34 पर बंद हुआ था। मिराए एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर को 5.25 फीसद पर अपरिवर्तित रखने के कारण सत्र के पहले भाग में रुपये में मजबूती आई। हालांकि, अमेरिका-ईरान वार्ता को लेकर भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण रुपए ने शुरुआती बढ़त खो दी। उन्होंने कहा कि बढ़ती वैश्विक राजनीतिक अनिश्चितता के कारण निवेशक जोखिम से बच सकते हैं और वैश्विक बाजार में सतर्कता बढ़ सकती है। चौधरी ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर उम्मीद और नए विदेशी संस्थागत निवेश (एफआइआइ) प्रवाह से रुपया कमजोर स्तर पर भी सहारा पा सकता है। उन्होंने डालर-रुपया का कारोबार 90.40 से 91.20 रुपए के दायरे में रहने का अनुमान लगाया।

बजट

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शुक्रवार को विधानसभा में बजट पेश करने जाते हुए।

श्रीलंका के कृषि मंत्रालय के सचिव डीपी विक्रमसिंघे ने कहा

भारत एशिया की खाद्य सुरक्षा के लिए अहम देश

हिमांशु अग्निहोत्री
नई दिल्ली, 6 फरवरी।

श्रीलंका के कृषि मंत्रालय के सचिव डीपी विक्रमसिंघे ने भारत को एशिया की खाद्य सुरक्षा का आधार बताया। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से श्रीलंका अपनी कृषि नीतियों को मजबूत कर सकता है। भारत एशिया की खाद्य सुरक्षा के लिए एक महत्त्वपूर्ण देश है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर चिंता जताई और कानूनी ढांचे के माध्यम से कृषि-वानिकी को नियमित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

सचिव ने कहा, कृषि-वानिकी के बारे में एक नया सिद्धांत है क्योंकि भारत और श्रीलंका में हम इसे लंबे समय से उपयोग करते आ रहे हैं लेकिन इसे एक अवधारणा के रूप में नियमित करना चाहते हैं। दोनों देशों की नीति बनाना चाहते हैं इसलिए हम भारत और अन्य प्रतिभागियों के अनुभव लेने आए हैं। इस अनुभव से किसानों की मदद के लिए श्रीलंका में कृषि-वानिकी को एक नया आधार देने में मदद मिलेगी।

सचिव ने कहा, कृषि-वानिकी के बारे में एक नया सिद्धांत है क्योंकि भारत व श्रीलंका में हम इसे लंबे समय से उपयोग करते आ रहे हैं लेकिन इसे एक अवधारणा के रूप में नियमित करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, कृषि में नया क्या कर सकते हैं? हमें यहां इतनी सारी चीजें मिली हैं, इतने सारे विचार और इतने सारे दस्तावेज। इसलिए अब अपनी मौजूदा कृषि-वानिकी को नियमित करने और इसे किसी कानूनी ढांचे में डालने के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्रीलंका में कृषि उत्पादन और भारत से आयात की स्थिति पर उन्होंने कहा, हम अपनी आवश्यकताओं के लिए कुछ सब्जियां उगा कर रहे हैं, खासकर धान। हमारे पास धान पर्याप्त मात्रा में है। हम कुछ सब्जियां, फल और कुछ अन्य फसलें भी पैदा कर रहे हैं, जैसे काला चना, हरा चना। लेकिन शेष हम भारत से आयात करते हैं। श्रीलंका अपनी आवश्यकता का 50 फीसद मक्का भारत से प्राप्त कर रहा है। 80 फीसद प्याज, आलू, कुछ अनाज जैसे काला चना, कुछ मूंगफली हम यहां से ले रहे हैं। भारत एशिया की खाद्य सुरक्षा के लिए एक महत्त्वपूर्ण देश है। भारतीय भंडार हमारे लिए अहम है। श्रीलंका के लिए भारतीय बाजार तक पहुंचना आसान है। साथ ही भारतीय कीमत एशिया के अन्य प्रतिस्पर्धियों से कम है।

योगी सरकार का दावा : राज्य में 16 लाख गोवंश किए गए संरक्षित

लखनऊ, 6 फरवरी (ब्यूरो)।

योगी सरकार ने अब तक देश में सबसे अधिक रिकार्ड 16.35 लाख निराश्रित गोवंश का संरक्षण किया है। सरकार का दावा है कि इससे पहले किसी भी राज्य में गोवंश संरक्षण को लेकर इतनी व्यापक, संगठित और प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई।

एक बयान के अनुसार, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब तक प्रदेशभर में 7500 से अधिक गो आश्रय स्थलों का निर्माण कराया गया। जहां निराश्रित गोवंश के लिए चारा, पानी, इलाज और देखभाल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई। यही नहीं, सरकार ने हर जिले में गो संरक्षण समितियों का गठन करते हुए जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इसका नोडल अधिकारी बनाया, जिससे निगरानी और जवाबदेही मजबूत हुई। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना और पोषण मिशन के अंतर्गत अब तक 1,13,534 पशुपालकों को 1,81,339 गोवंश उपलब्ध कराए गए, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली और पशुपालकों की आय में वृद्धि हुई।

गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि धरती, कृषि, प्रकृति और मानव जीवन सभी के लिए गोमाता सबसे बड़ा आशीर्वाद हैं।

प्रदेश में गोसेवा और संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में गो तस्करी के खिलाफ सख्त अभियान चलाया गया।

एकल परिवार और बढ़ता शहरीकरण बढ़ा रहा मानसिक परेशानी | रपट | महिलाओं से ज्यादा परेशान पुरुष, तीन फीसद करते हैं आत्महत्या

हर चौथा युवा उदासी और नींद की समस्या से परेशान

राकेश शर्मा
नई दिल्ली, 6 फरवरी।

एकल परिवार, बढ़ते शहरीकरण, आपसी प्रतिस्पर्धा सहित दूसरे कारणों से हर चौथा युवा उदासी व नींद न आने की समस्या से परेशान है। जबकि हर पांचवें व्यक्ति में तनाव व चिंता की समस्या दिख रही है। यह खुलासा राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम टेली मानस हेल्पलाइन पर आए फोन काल के विश्लेषण से हुआ है।

राष्ट्रीय स्तर पर किए गए विश्लेषण से तैयार हुई रपट के मुताबिक टेली मानस हेल्पलाइन पर पिछले एक साल में 351454 से अधिक फोन आए। इसमें सबसे अधिक फोन 18 से 45 साल के युवा की रही। फोन करने वालों में से 14 फीसद पीड़ित में समस्या नींद की परेशानी रही। वहीं अन्य 14 फीसद में उदासी या मन का भारीपन की परेशानी, 11 फीसद में तनाव से जुड़ी समस्याएं और नौ फीसद में चिंता की समस्या सबसे अधिक सामने आई हैं। कुल मामलों में आत्महत्या से जुड़े मामलों की संख्या तीन फीसद से कम पाई गई। वहीं अन्य मामलों में सामान्य विवाद, घरेलू झगड़े, पढ़ाई व नौकरी में परेशानी, डर सहित दूसरे कारण का पता चला। रपट के मुताबिक टेली मानस हेल्पलाइन में फोन करने वालों में 56.15 फीसद पुरुष हैं। इनमें 18 से 45 साल के आयु वर्ग के फोन करने वालों की हिस्सेदारी 71.5 फीसद रही। आंकड़ों के अनुसार 70.75 फीसद लोग ने अपनी स्वयं की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए सलाह ली। जबकि 18.4 फीसद फोन देखभालकर्ता ने की। इन्होंने किसी परिजन या परिचित की ओर से मदद मांगी। टेली मानस में आए कुल प्राप्त फोन में से 93 फीसद फोन को नियमित श्रेणी में रखा गया है। वहीं, 3.49 फीसद फोन आपातकालीन पाई गईं, जिन्हें तुरंत मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों तक पहुंचाया गया। जबकि 2.2 फीसद फोन शरारती या असंगत पाई गईं।

विशेषज्ञों के मुताबिक सेवाओं में हो रहा है सुधार

विशेषज्ञों का कहना है कि टेली मानस पर सेवाओं का सुधार किया जा रहा है। इस पर फोन करने वाले पीड़ित की लोकेशन, उसकी मानसिक स्थिति, आसपास मौजूद लोगों की उपस्थिति सहित दूसरे तथ्यों का पता लगाया जाता है। पीड़ित की स्थिति का आंकलन लगाने के बाद जरूरत के आधार पर परिवार के सदस्य या पुलिस की मदद ली जाती है। आत्महत्या जैसे मामलों में तुरंत आसपास या पुलिस को सचेत कर उक्त व्यक्ति को बचाया जाता है। अधिकारी का कहना है कि यह कार्यक्रम देशभर में 23 टेली-मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस), बेंगलुरु इस कार्यक्रम का नोडल केंद्र है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलुरु (आईआईआईटी-बी) तकनीकी सहयोग दे रहा है।

देश के 34 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में सुविधा

देश में टेली मानस की सुविधा अक्टूबर 2022 में शुरू हुई। इसका दायरा 34 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश तक फैल गया है। सेवा के शुरू होने के बाद से अभी तक 32.84 लाख से ज्यादा फोन पर सुझाव दिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देशभर में स्थापित 51 टेली मानस सेल में से 47 सेल पूरी तरह कार्यशील हैं। इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को 20 विभिन्न भारतीय भाषाओं में मानसिक स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा दी जा रही है। जल्द ही लक्षद्वीप और पुडुचेरी में भी सेवाएं शुरू की जाएंगी।

खबर कोना

महाराष्ट्र के पुणे में खेती के मौसम के अंत का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किसान क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेतीं महिला किसान।

फास्टैग वार्षिक पास उपयोगकर्ताओं की संख्या 50 लाख के पार: मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 फरवरी (भाषा)।

फास्टैग वार्षिक पास पहल ने पेश होने छह महीनों के भीतर 50 लाख उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा पार कर लिया है और इस अवधि में 26.55 करोड़ से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करने वाले यात्रियों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए 15 अगस्त, 2025 को वार्षिक पास सुविधा शुरू की गई थी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि फास्टैग वार्षिक पास ने पेश होने के छह महीने के भीतर 50 लाख उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा पार कर 26.55 करोड़ से अधिक लेनदेन दर्ज करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। क्षेत्रवार विश्लेषण से पता चला कि वार्षिक पास के उपयोग के मामले में चंडीगढ़ सबसे आगे है, जो देश भर में कुल वार्षिक पास लेनदेन का 14 फीसद है, इसके बाद तमिलनाडु 12.3 फीसद और दिल्ली 11.5 फीसद के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

पीएफसी के निदेशक मंडल ने आरईसी के विलय को मंजूरी दी

नई दिल्ली, 6 फरवरी (भाषा)।

सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) के निदेशक मंडल ने शुक्रवार को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) आरईसी लिमिटेड का विलय कराने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। इस विलय के बाद भी पीएफसी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सरकारी कंपनी बनी रहेगी। पीएफसी और आरईसी के विलय को लेकर निदेशक मंडल की यह मंजूरी रविवार को केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के बाद आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीएफसी कंपनियों के पुनर्गठन का संकेत दिया था। पीएफसी ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि निदेशक मंडल ने बजट घोषणा का संज्ञान लेते हुए पीएफसी और आरईसी के विलय के रूप में पुनर्गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।

चांदी में 13,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट, सोना 3,400 रुपए प्रति 10 ग्राम नरम

नई दिल्ली, 6 फरवरी (भाषा)।

राष्ट्रीय राजधानी में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में शुक्रवार को तेज गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों के लगातार दूसरे दिन मुनाफावसूली जारी रखने से चांदी लगभग पांच फीसद टूटकर 2.55 लाख रुपए प्रति किलोग्राम रह गई जबकि सोना 1.57 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, चांदी 13,000 रुपए यानी 4.85 फीसद टूटकर 2,55,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों समेत) रह गई। यह गुरुवार को 2,68,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसी तरह, 99.9 फीसद शुद्धता वाला सोना 3,400 रुपए यानी 2.12 फीसद टूटकर 1,57,200 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों समेत) रह गया। इसका पिछला बंद भाव 1,60,600 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

भारत-ईयू एफटीए भारतीय वाहन कलपुर्जा कंपनियों को तक बेहतर पहुंच देगा : इक्रा

नई दिल्ली, 6 फरवरी (भाषा)।

भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) एफटीए से दोनों पक्षों के बीच प्रतिस्पर्धी गतिशीलता और बाजार पहुंच के फिर से परिभाषित होने की उम्मीद है। मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से भारतीय वाहन और कलपुर्जा निर्यात के लिए यूरोपीय बाजारों तक बेहतर पहुंच मिलेगी, जिससे इस क्षेत्र की दीर्घकालिक वृद्धि संभावनाओं को मदद मिलेगी। रपट में कहा गया कि इससे प्रीमियम वाहनों के आयात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, लेकिन व्यापक बाजार में इसका असर सीमित रहेगा। रपट के मुताबिक, यूरोपीय संघ में बने वाहनों (सीबीयू) पर शुल्क में भारी कटौती होने की उम्मीद है, जो एक निश्चित कोटा के तहत 15,000 यूरो प्रति वाहन से ऊपर की आयात कीमत पर 110 फीसद से घटकर 10 फीसद तक आ सकता है।

समानता आजादी की आत्मा है। असल में, इसके बिना कोई आजादी नहीं है। -फ्रांसेस राइट

सावधानी जरूरी है

पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नौ फरवरी, 2025 को इस्तीफे दिए जाने के उपरांत लगे राष्ट्रपति शासन के करीब एक वर्ष बाद मणिपुर में नए मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्रियों की व्यवस्था से यह उम्मीद की जा रही थी कि अस्थिरता, हिंसा और अविश्वास के लंबे दौर के बाद अब हालात धीरे-धीरे सामान्य होंगे, लेकिन शीघ्र ही चुराचांदपुर में जिस तरह से हिंसा भड़की, उससे साफ है कि राज्य में शांति बहाली की राह आसान नहीं होने वाली। जातीय संतुलन साधने के लिए नई सरकार में मैतेई समुदाय के भाजपा नेता वाई खेमचंद सिंह को मुख्यमंत्री, तो कुकी नेता नेमचा किपगेन और नगा समुदाय के एल डिखो को उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि उस गहरे सामाजिक-जातीय संकट से बाहर निकलने की एक कोशिश भी है, जिसने बीते वर्षों में मणिपुर को हिंसा, अविश्वास और प्रशासनिक ठहराव की स्थिति में डाल रखा था। लेकिन, चुराचांदपुर में हुई हिंसा केंद्र और राज्य सरकार को 'सावधानी जरूरी है' का संदेश देती है। ताजा हिंसा की वजह यह बताई जा रही है कि नेमचा किपगेन के उपमुख्यमंत्री बनने से कुकी समुदाय बंट गया है, और सरकार में शामिल कुकी विधायकों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, मणिपुर ने 2023 में शुरू हुई मैतेई-कुकी हिंसा में काफी कुछ खोया है। मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे की मांग, भूमि अधिकारों पर विवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों ने हिंसा को भड़काया। हजारों लोग विस्थापित हुए, सैकड़ों मौतें हुईं और अर्थव्यवस्था ठप हो गई। केंद्र सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए, पर स्थानीय नेतृत्व की कमी और समुदायों के बीच अविश्वास ने समस्या को जटिल बना दिया। राष्ट्रपति शासन के दौरान सुरक्षा बलों ने भले ही कट्टरपंथी समूहों के जोश को कम किया है, लेकिन लंबे जातीय संघर्ष के बाद अनुमानित 60 हजार विस्थापितों में से सिर्फ नौ हजार लोगों का ही घर लौटना भरोसे की कमी को ही दर्शाता है। कुकी-जो समूह जिस अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं, वह संभव नहीं और इससे विवाद बढ़ेगा ही। दरअसल, मणिपुर की समस्या केवल प्रशासनिक या सांविधानिक ढांचे की बहाली से खत्म नहीं होगी। सच्ची स्थिरता के लिए सतर्कता के साथ समुदायों के बीच संवाद और दीर्घकालिक समावेशी समाधान की जरूरत है। मणिपुर में खेमचंद सिंह के नेतृत्व वाली नई सरकार राज्य के लिए नई उम्मीद का प्रतीक है, लेकिन यह तो समय ही बताएगा कि यह समुदायों को एकजुट करने की परीक्षा में कितनी सफल रहती है।

जात ही पूछो सबकी

'सामाजिक न्याय' अनिवार्य है और सबको समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। किंतु 'सामाजिक न्याय' के नाम पर हिंदू समाज को जातियों के आधार पर विभाजित करना और वैमनस्य को बढ़ावा देना अंततः किसके हित में होगा? यदि भारत इस औपनिवेशिक नैरेटिव से मुक्त नहीं हो पाता, तो क्या वह विकसित राष्ट्र बन पाएगा?

हम जाति-वर्ग विहीन समतापूर्वक समाज की कल्पना करते हैं, पर व्यवहार में जातिगत पहचान को और गाढ़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जहां कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी 'जितनी आबादी, उतना हक' रूपी बात करते हैं, वहीं 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' (यूजीसी) 'समता विनियम 2026' के रूप में ऐसे नियम लेकर आता है, जिससे जातिगत वैमनस्य बढ़ने की संभावना प्रबल होती है। भारत में जाति सच है, परंतु जातिगत विद्वेष भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है। इसका बीजारोपण पांच सहस्राब्दी पहले तब हुआ, जब यूरोपीय आक्रांताओं और ईसाई मिशनरियों ने भारत में अपनी जड़ें जमाना प्रारंभ किया।

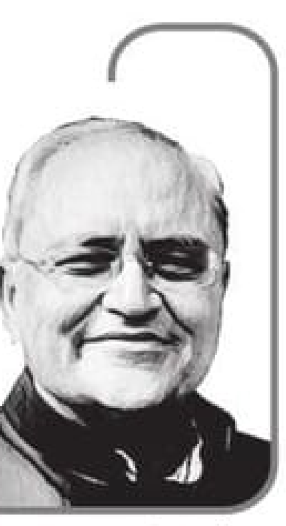

बलबीर पुंज
पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य

यह सत्य है कि हिंदू समाज में सदियों तक अस्पृश्यता जैसी सामाजिक विकृति विद्यमान रही, किंतु इसे समाप्त करने हेतु समाज के भीतर से निरंतर सुधार आंदोलनों की आवाजें उठती रहीं। सिख गुरुओं से लेकर स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, गांधी जी, वीर सावरकर, डॉ. आंबेडकर और डॉ. हेडगेवार आदि ने अस्पृश्यता रूपी सामाजिक व्याधि के विरुद्ध सफलतापूर्वक आंदोलन चलाया। यह किसी बाहरी दबाव से नहीं, आंतरिक चेतना से संभव हुआ। इन्हीं सतत प्रयासों के चलते स्वतंत्र भारत ने आरक्षण व्यवस्था को स्वीकार किया और बौद्धिक जगत में आज अस्पृश्यता के पक्ष में कोई वैचारिक समर्थन शेष नहीं है।

भारत को अनेक खांचों में विभाजित करने की प्रवृत्ति बाहरी शक्तियों की दीर्घकालिक रणनीति रही है। इसी में से एक–हिंदू समाज– विशेषकर सवर्णों (ब्राह्मण सहित) के दानवीकरण की सुनियोजित रणनीति है, जिसका उद्देश्य समाज के वैचारिक और सांस्कृतिक नेतृत्व को संदेह के घेरे में लाकर हिंदू चेतना और स्वाभिमान को समाप्त करना था। इन साजिशों की जड़ें सोलहवीं शताब्दी तक जाती हैं। दक्षिण भारत में जेसुइट मिशनरी फ्रांसिस जेवियर ने अपने पत्राचार में ब्राह्मणों को ईसाई धर्मांतरण के मार्ग का मुख्य बाधक बताया था। इसके उपरांत 'गोवा इंक्विजिशन' का कठोर अध्याय प्रारंभ हुआ, जहां

मजहबी असहमति को अपराध की दृष्टि से देखा गया। बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर ने भी इस कालखंड की क्रूरता का संज्ञान लिया था।

फिर 18वीं शताब्दी में प्लासी युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने मजहबी और शैक्षिक हस्तक्षेप से धर्मांतरण और ब्राह्मण-विरोध को संस्थागत रूप दिया। वर्ष 1813 के चार्टर एक्ट के साथ मिशनरी गतिविधियों को वैधानिक संरक्षण मिला। इसी चिंतन के संगठित प्रतिपादन हेतु थॉमस बैबिंगटन मैकाले ने 1835 में शिक्षा नीति का खाका प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य मैकाले के निजी पत्राचार में मिलता है। उन्होंने 1836 में अपने पिता को लिखा था–'यदि हमारी शिक्षा नीति सफल रही, तो तीस वर्षों के भीतर बंगाल में एक भी मूर्तिपूजक नहीं बचेगा।' इसी कालखंड में अन्य यूरोपीय फ्रेडरिक मैक्समूलर ने वेदों, उपनिषदों और अन्य संस्कृत ग्रंथों का दुर्भावनापूर्वक अंग्रेजी अनुवाद किया। इसकी मंशा का उल्लेख मैक्समूलर ने अपनी पत्नी को 1867 में लिखे पत्र में किया था–'मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे द्वारा तैयार किया गया अनुवाद भविष्य में भारत के भाग्य पर गहरा प्रभाव डालेगा। पिछले तीन हजार वर्षों में उससे जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का यही एकमात्र उपाय है।' ऐसे पत्रों की भरमार है। कालांतर में इसी मानसिकता के गर्भ से 'आर्य आक्रमण सिद्धांत' जन्मा, 'जस्टिस पार्टी' का गठन और 'द्रविड़ आंदोलन' का उदय हुआ।

अस्पृश्यता निस्संदेह गंभीर अपराध है। किंतु इसे केवल कथित रूप से ब्राह्मणों की देन बताना इतिहास की बहुस्तरीयता को नकारना है। प्रायः इस संदर्भ में अक्सर 'मनुस्मृति' को लांछित किया जाता है। पहली बात–मनु स्वयं ब्राह्मण नहीं थे और दूसरी बात–हिंदू परंपरा किसी एक ग्रंथ, एक पैगंबर या संहिताबद्ध सिद्धांत से नहीं बंधी है। इसकी विशेषता निरंतर परिवर्तन और आत्मसमीक्षा है। डॉ. आंबेडकर के अनुसार, 'मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मनु ने जाति कानून नहीं बनाया... यह वर्ण-व्यवस्था मनु से बहुत पहले से अस्तित्व में थी।' उन्होंने इसके लिए ब्राह्मणों को कोई दोष नहीं देते हुए लिखा, 'ब्राह्मण कई दूसरी चीजों के दोषी हो सकते हैं... किंतु गैर-ब्राह्मण आबादी को जाति-व्यवस्था में बांधना उनके स्वभाव के प्रतिकूल था।' यही नहीं, डॉ. आंबेडकर 'आर्य आक्रमणकारी सिद्धांत' को ब्रितानियों की मनगढंत झूठी कहानी तक बता चुके थे।

बाबासाहेब ने यह भी स्पष्ट किया था–'शूद्र सूर्यवंशी आर्य समुदायों में से एक थे। एक समय ऐसा था, जब आर्य समाज केवल तीन वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) को ही मान्यता देता था। शूद्र कोई पृथक वर्ण नहीं थे; वे क्षत्रिय वर्ण का ही अंग माने जाते थे। शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था, जिसमें ब्राह्मणों को अनेक अत्याचारों और अपमानों का सामना करना पड़ा।' डॉ. आंबेडकर ने आगे लिखाः 'शूद्रों द्वारा किए गए अत्याचारों और उत्पीड़नों से अपमानित ब्राह्मणों ने शूद्रों का उपनयन (जनेऊ संस्कार) करना अस्वीकार कर दिया। इससे वंचित किए जाने के कारण, जो शूद्र मूलतः क्षत्रिय थे, वे सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो गए, वैश्य वर्ण से भी नीचे चले गए, और इस प्रकार वे चौथे वर्ण के रूप में स्थापित हो गए।'

यह जातिप्रथा की विकृति का ही परिणाम है कि यदुकुल में जन्मे और भगवान विष्णु के आठवें अवतार श्रीकृष्ण वर्तमान नैरेटिव में ओबीसी कहलाएंगे, जिनकी उपासना अनादिकाल से असंख्य हिंदू कर रहे हैं। वेदों और महाभारत का संग्रह करने वाले कृष्णद्वैपायन महर्षि वेद-व्यास का जन्म मछुआरिन सत्यवती की कोख से हुआ था। 'श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण' के रचयिता आदिकवि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अलंकृत समुदाय दलित के रूप में वर्गीकृत है। रामायण के सबसे कष्टमयी काल में श्रीराम ने उन लोगों (हनुमानजी, सुग्रीव, केवट, निषाद, भील सहित) को अपना सहयोगी-सलाहकार बनाया, जिन्हें आज की भाषा में वनवासी, आदिवासी, पिछड़ा या अति-पिछड़ा कहा जाएगा।

'सामाजिक न्याय' अनिवार्य है और प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। किंतु 'सामाजिक न्याय' के नाम पर हिंदू समाज को जातियों के आधार पर विभाजित करना और वैमनस्य को बढ़ावा देना अंततः किसके हित में होगा? यदि भारत आने वाले वर्षों में औपनिवेशिक नैरेटिव से मुक्त नहीं हो पाता, तो क्या वह वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य साकार कर सकेगा?

-लेखक 'ट्रिस्ट विद अयोध्या : डिकॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया' और 'नैरेटिव का मायाजाल' पुस्तक के लेखक हैं।

edit@amarujala.com

मुद्दा

स्वच्छ हवा, वादे और वित्तीय मकड़जाल

अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसियां स्वच्छ हवा के लिए वादे तो करती हैं, लेकिन उनका धन उन्हीं परियोजनाओं में जा रहा है, जो हवा को और जहरीला बना रही हैं।

स्वच्छ हवा आज दुनिया की सबसे बुनियादी जरूरतों में शामिल है, लेकिन वैश्विक वित्तीय व्यवस्था इसे अब भी प्राथमिकता नहीं मानती। क्लीन एयर फंड की ताजा वैश्विक रिपोर्ट एक बार फिर इस कड़वी सच्चाई को सामने लाती है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति और विकास एजेंसियां स्वच्छ हवा के लिए बड़े-बड़े वादे तो जरूर करती हैं, लेकिन उनका धन उन्हीं परियोजनाओं में जा रहा है, जो हवा को और जहरीला बना रही हैं। यह एक ऐसे वैश्विक अन्याय का उदाहरण है, जिसका सबसे भारी बोझ तीसरी दुनिया के देशों खासकर भारत को उठाना पड़ रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2023–24 के दौरान दुनिया की सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने जीवाश्म ईंधन को लंबे समय तक बनाए रखने वाली परियोजनाओं में वित्तीय राशि 80 फीसदी बढ़ाकर 9.5 अरब डॉलर कर दी। इसके उलट, स्वच्छ हवा और वायु गुणवत्ता सुधार के लिए दी जाने वाली सहायता घटकर 3.7 अरब डॉलर रह गई, जो कुल वैश्विक विकास सहायता का महज एक फीसदी ही है। हर साल होने वाले अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन स्वच्छ हवा को मानवाधिकार के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन जब बजट आवंटन की बात आती है, तो वही सरकारें और संस्थाएं पीछे हट जाती हैं। स्थिति और गंभीर तब हो जाती है, जब दुनिया की सबसे बड़ी विकास एजेंसी यूएसएड के बंद होने और विश्व बैंक पर जीवाश्म ईंधन ऋण बढ़ाने के दबाव जैसी घटनाएं सामने आती हैं। इन फैसलों ने स्वच्छ हवा के लिए चल रहे वैश्विक प्रयासों की रीढ़ कमजोर कर दी है।

कुमार सिद्धार्थ

आज वायु प्रदूषण दुनिया भर में हर साल लगभग 57 लाख लोगों की जान ले रहा है। यह संख्या 2040 तक 62 लाख तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट यह भी दिखाती है कि स्वच्छ हवा के लिए उपलब्ध सीमित वित्तीय अनुदान का वितरण बेहद असमान है। जिन इलाकों में स्वास्थ्य ढांचा सबसे कमजोर है, वहीं मदद सबसे कम पहुंच रही है। भारत इस वैश्विक असमानता का सबसे बड़ा उदाहरण है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के शहर लगातार ऊपर बने हुए हैं। फिर भी भारत को स्वच्छ हवा के लिए अंतरराष्ट्रीय फंडिंग में प्राथमिकता नहीं मिलती। भारत में वायु प्रदूषण से हर साल करीब 95 अरब डॉलर की आर्थिक क्षति होती है। यह नुकसान केवल अस्पतालों के बढ़ते खर्च में नहीं दिखता, बल्कि काम के दिनों की हानि, स्कूल न जा पाने वाले बच्चों, घटती उत्पादकता और जीवन की गिरती गुणवत्ता के रूप में सामने आता है। अगर वैश्विक वित्तीय सहायता जीवाश्म ईंधन आधारित परियोजनाओं पर ही केंद्रित रही, तो भारत का स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और धीमा पड़ेगा। कोयला आधारित बिजली संयंत्र, डीजल आधारित परिवहन और प्रदूषणकारी उद्योग न केवल जलवायु संकट को गहराएंगे, बल्कि भारत को एक स्थायी स्वास्थ्य आपदा की ओर धकेल देंगे।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2040 तक मानवजनित वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों को आधा करने का लक्ष्य रखा है। जी-20 ने भी वायु गुणवत्ता को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। लेकिन जब तक नीतियों और बजट के बीच की यह खाई बनी रहेगी, तब तक कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं होगा। क्लीन एयर फंड की रिपोर्ट समाधान का रास्ता भी सुझाती है कि फंडिंग को जीवाश्म ईंधन के विस्तार से हटाकर स्वच्छ हवा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण की ओर मोड़ा जाए। अगर दाता देश, विकास बैंक और वैश्विक संस्थाएं अब भी अपनी दिशा नहीं बदलतीं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और जी-20 के लक्ष्य केवल खोखले घोषणापत्र बनकर रह जाएंगे।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मशीन को इस काबिल बनाने के बारे में है कि वह दुनिया को हमारी तरह समझ सके और खुद को इसके अनुरूप ढाल सके।
-डेमिस हसाबिस

कमी रोशनी में नहीं, खिड़कियों में है

यदि हम समय-समय पर अपनी मान्यताओं को परखते रहें, उन्हें साफ करते रहें, तो न केवल हमारा दृष्टिकोण बदलता है, बल्कि हमारा पूरा जीवन उज्ज्वल हो जाता है।

हमारी मान्यताएं ही संसार को देखने की खिड़कियां होती हैं। इन्हीं खिड़कियों से झांककर हम लोगों, परिस्थितियों और स्वयं को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन समस्या तब पैदा होती है, जब हम यह मान लेते हैं कि ये खिड़कियां हमेशा साफ ही रहेंगी। समय के साथ उन पर धूल जमती जाती है। अनुभवों की धूल, डर की परतें, असफलताओं की छाया और समाज से मिली अधूरी सीखें धीरे-धीरे हमारी दृष्टि को धुंधला कर देती हैं। तब हमें लगता है कि दुनिया अंधेरी है, जबकि सच यह है कि रोशनी आ ही नहीं पा रही।

आइजैक असिमोव

हर इन्सान अपने जीवन में कुछ धारणाएं बना लेता है। हमें सिखाया जाता है कि क्या संभव है और क्या असंभव, क्या सही है और क्या गलत। धीरे-धीरे ये बातें हमारे भीतर इतनी गहराई से बैठ जाती हैं कि हम उन्हें सत्य मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये केवल विचार हैं, स्थायी सच नहीं। जब हम इन्हें बिना प्रश्न किए स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारी सोच सीमित हो जाती है और हम नए रास्तों को देखने से चूक जाते हैं। मान्यताओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे हमें सुरक्षित महसूस कराती हैं। जब हम स्वीकार करते हैं कि हो सकता है हमने अब तक चीजों को अधूरा या गलत समझा हो। यही स्वीकार्यता ही सीख की पहली सीढ़ी है। जब हम अपनी सोच को जकड़ लेते हैं, तब हम दूसरों के बदलने की संभावना को भी नकार देते हैं। इससे न केवल हमारे रिश्ते सीमित हो जाते हैं, बल्कि हमारी समझ भी संकीर्ण हो जाती है।

जीवन धारा

अपनी मान्यताओं को साफ करना निरंतर चलने वाला अभ्यास है। जब हम अपनी खिड़कियां साफ करते हैं, तब दुनिया हमें नए रंगों में दिखाई देती है। हमें समझ आता है कि हर विचार में कुछ न कुछ सीख छिपी हो सकती है। हम अधिक सहनशील बनते हैं, अधिक संवेदनशील बनते हैं। तब ज्ञान केवल जानकारी नहीं रह जाता, वह समझ बन जाता है। और समझ हमें केवल सफल नहीं बनाती, बल्कि मानवीय भी बनाती है। रोशनी हमेशा बाहर मौजूद रहती है। कमी रोशनी में नहीं, हमारी खिड़कियों में होती है। यदि हम समय-समय पर अपनी मान्यताओं को परखते रहें, उन्हें साफ करते रहें, तो न केवल हमारा दृष्टिकोण बदलता है, बल्कि हमारा पूरा जीवन उज्ज्वल हो जाता है।

मशीन विवेक कहां से लाएगी

विवेक एक ऐसा अद्वितीय मानवीय कौशल है, जिसका स्वचालन नहीं किया जा सकता, निकट भविष्य में तो बिल्कुल नहीं।

कॉलेज के दिनों में मुझे मध्यकालीन अध्ययन के एक सेमिनार में शामिल होने का अवसर मिला। विषय था-ब्रिटिश कॉमन लॉ की उत्पत्ति। वहां मैंने जाना कि 14वीं सदी के इंग्लैंड में न्यायाधीश किस तरह संपत्ति से जुड़े विवादों का निपटारा करते थे। जब गवाहों के बयान आपस में टकराते और दस्तावेज अधूरे या अस्पष्ट होते थे, तब न्यायाधीश अपनी तार्किक क्षमता और विवेक का इस्तेमाल करके निर्णय लेते थे। उस सेमिनार की सीख आज भी मेरे काम आती है। वह मुझे पढ़ने, शोध करने और विश्लेषण करने वाली गहरी शिक्षा की अहमियत की याद दिलाती है। मेरी कॉलेज की शिक्षा ने मुझे यह नहीं सिखाया कि 'क्या सोचना है', बल्कि यह सिखाया कि 'कैसे सोचना है'। तकनीकी प्रभुत्व वाली इस दुनिया में रणनीतिक और वित्तीय फैसले लेते समय यही नजरिया सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। आज जितनी भी बोर्डरूम चर्चा होती है, हरेक के केंद्र में एआई होता ही है। निस्संदेह एआई परिवर्तनकारी साबित होगा। फिर भी, बहुत कुछ ऐसा भी है, जो बिल्कुल नहीं बदलेगा। उनमें सबसे प्रमुख है इन्सानी विवेक। विवेक से मेरा तात्पर्य है-परस्पर विरोधी मूल्यों और मतभेदों के बीच मध्यस्थता करने की क्षमता; उन पहलुओं पर विचार करने का हुनर, जो अपने आप में महत्वपूर्ण तो हैं, पर जिन्हें एकसाथ पूरा नहीं किया जा सकता; और श्रेष्ठ विकल्प तक पहुंचने के लिए कई रास्तों पर विचार करने का कौशल। यह एक अद्वितीय मानवीय कौशल है। हाल ही में, मेरा एक ग्राहक अपने व्यवसाय का एक हिस्सा बेचना चाहता था। उसके सामने दो विकल्प थे-या तो उस तेजी से बढ़ने वाली इकाई को बेच दिया जाए, जो अस्थिर थी व मुख्य कारोबार का केंद्र नहीं थी, या फिर उस धीमी गति से बढ़ने वाली इकाई को बेचा जाए, जो कंपनी के उद्देश्य और मिशन से अधिक मेल खाती थी। एआई आधारित विश्लेषण ने धीमी वृद्धि वाले व्यवसाय को बेचने की सिफारिश की। लेकिन मानवीय विवेक ने दूसरा रास्ता दिखाया कि उतार-चढ़ाव वाली इकाई को बेचें और दूसरी को बेहतर बनाएं। हालांकि, यह कहना जल्दबाजी होगी कि कौन-सा रास्ता सही साबित होगा, लेकिन मैं एआई के उत्तर की निश्चितता देखकर दंग रह गया। बेशक एआई पैटर्न पहचानने, कोड बनाने और भारी मात्रा में टेक्स्ट व डाटा को संकलित करने में सक्षम है। पर किसी को यह तय तो करना ही होता है कि विश्लेषण भरोसेमंद है या नहीं, उसके निहितार्थ क्या हैं और उस पर अमल करना समझदारी होगी या नहीं। यही वे जगहें हैं, जहां तकनीक नहीं, बल्कि मानव विवेक निर्णायक भूमिका निभाता है। पिछले वर्ष एक बोर्ड यह जानना चाहता था कि उसे एक व्यावसायिक सौदे के लिए कितनी बोली लगानी चाहिए। एआई ने एक ऐसी राशि सुझाई, जो मुझे कम लगी। फिर चर्चा हुई कि क्या सौदे की कीमत अधिक रखनी पड़ेगी। जैसा कि अपेक्षित था, जब कंपनी ने एआई द्वारा सुझाई कीमत का प्रस्ताव दिया, तो उसे निरस्त कर दिया गया। बाद में, अधिक कीमत की पेशकश स्वीकार कर ली गई और सौदा सफल रहा। सौदे को लेकर एआई मानवीय पहलुओं को नहीं समझ सका, जिसे मानवीय निर्णय ने बखूबी समझा। इसी वजह से मुझे संदेह है कि एआई जल्द मानवीय पहलुओं की बराबरी लेगा। उच्च शिक्षा और व्यवसाय में लोगों को विशेषज्ञता की तरफ धकेलने का चलन है। एआई इस दबाव को और बढ़ा देता है। आम सोच यह है कि अगर मशीनें सामान्य काम कर सकती हैं, तो इन्सानों को खास कामों पर ध्यान देना चाहिए। मेरा मानना है कि इसका उल्टा सच है। जैसे-जैसे नियमित विश्लेषण स्वचालित होता जाएगा, पेशेवरों को जो चीज अलग बनाएगी, वह होगी अलग-अलग क्षेत्र में चीजों को समझने की क्षमता, ऐसे पैटर्न देखना, जो विशेषज्ञ नहीं देख पाते, और सही फैसला लेना। नियुक्ति करते समय व्यावसायिक नेतृत्वकर्ता ऐसे लोगों की तलाश करते हैं, जो विश्लेषण करने, खुद को बदलने, नए कौशल सीखने और नई जानकारियों से लैस होने में तेजी से सक्षम हों। सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, बिना किसी निर्देश का इंतजार किए अनिश्चितता के बीच रास्ता निकालते हैं। मशीन इन गुणों की नकल नहीं कर सकती। ऐसे उम्मीदवार एआई का इस्तेमाल एक उपकरण के रूप में करते हैं, बैसाखी के रूप में नहीं। बहुत पहले हुए उस मध्यकालीन कानून सेमिनार ने मुझे वित्त और अर्थशास्त्र के मेरे पाठ्यक्रम से ज्यादा इस दुनिया के लिए तैयार किया। जैसे सदियों पहले उन जजों ने सही-गलत की बहस के बीच फैसले दिए, जहां सबूत मिश्रित और अधूरे थे, वैसे ही आज पेशेवरों के पास ऐसा हुनर होना चाहिए कि वे उन जगहों पर चीजों को बेहतर बना सकें, जहां मशीनें काम नहीं कर सकतीं।

ब्लेयर एफ्रॉन
द न्यूयॉर्क टाइम्स

नैपकिन एआई

यह स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, जो साधारण टेक्स्ट को तुरंत प्रोफेशनल, कस्टमाइजेबल और देखने में आकर्षक डायग्राम और इन्फोग्राफिक्स में बदल देता है, जिन्हें प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट्स में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें उपयोगकर्ता को केवल अपना टेक्स्ट डालना होता है। इसके बाद यह एआई उस टेक्स्ट का विश्लेषण करता है और उपयुक्त आइकॉन, लेआउट और कनेक्टर्स सुझाता है। यह खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो कम समय में प्रभावशाली विजुअल कंटेंट बनाना चाहते हैं। यह टूल उच्च गुणवत्ता के विजुअल्स कम समय में तैयार करने की सुविधा देता है।

एजुकेशन & कॅरिअर

मात्रा से अधिक गुणवत्ता चुनना ही सुरक्षित भविष्य की पहचान है।

अमर उजाला Job Alert

Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

पंजाब नेशनल बैंक में संभावनाएं

अप्रेंटिसशिप के लिए करें आवेदन

5138 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 24 फरवरी, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 20 वर्ष व अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : pnb.bank.in

झारखंड लोक सेवा आयोग ■ 103 पद

पुलिस उपाधीक्षक व अन्य पद खाली
आवेदन की अंतिम तिथि
14 फरवरी, 2026
आयु-सीमा
न्यूनतम उम्र 21 वर्ष व अधिकतम उम्र 35 वर्ष
यहां आवेदन करें
jpsc.gov.in

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार ■ 71 पद

आंगनवाड़ी के पदों पर रोजगार के अवसर
आवेदन की अंतिम तिथि
11 फरवरी, 2026
योग्यताएं
इंटरमीडिएट व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें
upanganwadibharti.in

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ■ 804 पद

प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद खाली
आवेदन की अंतिम तिथि : 25 फरवरी, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : sso.rajasthan.gov.in

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र ■ 28 पद

जूनियर रिसर्च फेलो के पदों पर मौके
आवेदन की अंतिम तिथि
12 फरवरी, 2026
योग्यताएं
पोस्ट-ग्रेजुएशन व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें
nitkkr.ac.in

बिहार लोक सेवा आयोग ■ 13 पद

प्राध्यापक के पदों पर निकली भर्ती
आवेदन की अंतिम तिथि
06 मार्च, 2026
योग्यताएं
पीएचडी व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें
bpsc.bihar.gov.in

यहां भी रोजगार के अवसर...

- **चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, दिल्ली :** प्रोजेक्ट टेक्नीशियन व अन्य पदों पर मौके।
  वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि : 11 फरवरी, 2026
  cnbc.delhi.gov.in/en
- **रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलूरू :** वरिष्ठ प्रोफेसर का पद खाली।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 28 फरवरी, 2026
  rri.res.in

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

इतनी तेजी की भी जरूरत नहीं

अनावश्यक तेजी दिखाने से बेहतर है कि सही निर्णय लेकर समझदारी के साथ आगे बढ़ें, ताकि सफलता स्थायी हो

गैरी पिसानो
हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू

आज के समय में कई कंपनियां, खासकर व्यावसायिक क्षेत्र में, यह मानने लगी हैं कि जितनी तेजी से विकास होगा उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। लेकिन वास्तव में सफलता केवल तेजी से बढ़ने में नहीं, बल्कि सही दिशा में और सही तरीके से आगे बढ़ने में होती है। इसके लिए यह समझना जरूरी है कि विकास किस दिशा में हो रहा है और उसे हासिल करने के तरीके कितने सही और व्यावहारिक हैं। इससे मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार होता है, कार्य संस्कृति बनी रहती है और अनावश्यक जोखिमों से बचा जा सकता है। इस तरह धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ना ही लंबे समय में अधिक मूल्य और सफलता दिलाता है।

Harvard Business Review

■ **बुनियादी बातों पर ध्यान दें**
किसी भी संगठन या काम की सफलता उसकी मजबूत नींव पर निर्भर करती है। यदि शुरुआत में ही प्रक्रियाएं, ढांचा और मूल्य स्पष्ट व सुदृढ़ बनाए जाएं, तो भविष्य में बार-बार सुधार की जरूरत नहीं पड़ती। मजबूत आधार न केवल विकास को स्थिर बनाता है, बल्कि समय, संसाधन और ऊर्जा की भी बचत करता है। इसलिए तेजी से आगे बढ़ने से पहले बुनियादी बातों को सही करना दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है।

■ **रणनीतिक योजना बनाएं**
किसी भी संगठन के लिए टिकाऊ विकास तभी संभव है, जब विस्तार को नियंत्रित और योजनाबद्ध तरीके से किया जाए। लाभ प्राप्त करने के लिए बजट, भर्ती और संचालन का विस्तार धीरे-धीरे और वास्तविक जरूरतों के अनुसार होना चाहिए। साथ ही, केवल तेजी से बढ़ने पर ध्यान देने के बजाय यह समझना जरूरी है कि विकास किस गति से, किस दिशा में और किन तरीकों से किया जाए। स्पष्ट रणनीतिक योजना संगठनों को जोखिमों से बचाती है, संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करती है और स्थिर सफलता की ओर ले जाती है।

■ **मात्रा से अधिक गुणवत्ता है जरूरी**
व्यवसाय में केवल अधिक बिक्री या अधिक ग्राहकों पर ध्यान देना हमेशा लाभदायक नहीं होता। अत्यधिक मात्रा में छूट देने से अल्पकाल में बिक्री बढ़ सकती है, लेकिन इससे लाभ मार्जिन घट जाता है और उत्पाद या सेवा की

गुणवत्ता की छवि भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए संगठनों को संख्या बढ़ाने के बजाय गुणवत्ता, मूल्य और ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान देना चाहिए, ताकि स्थायी और लाभदायक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

■ **डाटा-आधारित निर्णय लें**
किसी भी संगठन के लिए केवल अनुमान या तेजी से किए गए अप्रमाणित विस्तार पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। इसके बजाय, डाटा का उपयोग करके यह समझना जरूरी है कि कौन-सी रणनीतियां वास्तव में कारगर हैं और कहां सुधार की आवश्यकता है। आंकड़ों के आधार पर लिए गए निर्णय न केवल गलतियों की संभावना कम करते हैं, बल्कि संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करते हुए संगठन को संतुलित और टिकाऊ विकास की दिशा में आगे बढ़ाते हैं।

खुद को परखें

1. पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना किस देश में स्थित है?
   (a) नेपाल (b) भूटान
   (c) चीन (d) भारत

2. हिमांक परियोजना मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में संचालित होती है?
   (a) लद्दाख
   (b) अरुणाचल प्रदेश
   (c) सिक्किम
   (d) हिमाचल प्रदेश

3. खानजर अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है?
   (a) अमेरिका
   (b) इंडोनेशिया
   (c) किर्गिस्तान
   (d) मलयेशिया

उत्तर : 1.b, 2.a, 3.c

फेलोशिप अलर्ट

एलईएपी इमर्ज फेलोशिप 2026-27

लीडरशिप एजुकेशन फॉर एशियन पैसिफिक्स (एलईएपी) द्वारा एलईएपी इमर्ज फेलोशिप 2026-27 के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। यह कार्यक्रम उभरते हुए युवा लीडर्स को सशक्त बनाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। इसके अंतर्गत कॉलेज के छात्रों को ठोस नेतृत्व कौशल, विभिन्न उद्योगों से परिचय, व्यक्तिगत

मार्गदर्शन तथा निरंतर सहयोग प्रदान किया जाता है, ताकि वे स्नातकोत्तर कॅरिअर के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकें। यह फेलोशिप उन कॉलेज छात्रों के लिए है, जो 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्नातक अध्ययन के अंतिम वर्ष में हों, स्नातक होने के बाद प्रारंभिक स्तर की नौकरी या इंटर्नशिप की तलाश में हों, तथा पाठ्येतर गतिविधियों में नेतृत्व और टीम के साथ कार्य करने का अनुभव रखते हों। चयनित फेलो को शैक्षणिक वर्ष के दौरान 3,000 अमेरिकी डॉलर का वजीफा प्रदान किया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 मार्च, 2026 निर्धारित की गई है। योग्य आवेदक आधिकारिक लिंक leap.org/emerge पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

गूगल की पहल

सिलिकॉन इंजीनियरिंग इंटर्नशिप-2026

गूगल सिलिकॉन इंजीनियरिंग इंटर्नशिप-2026 गूगल द्वारा प्रस्तुत एक प्रतिष्ठित सशुल्क कार्यक्रम है, जो पीएचडी छात्रों को उन्नत हार्डवेयर और सिलिकॉन डिजाइन परियोजनाओं पर कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। इस इंटर्नशिप के लिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या संबंधित क्षेत्र में पीएचडी कर रहे उम्मीदवार पात्र हैं, जिन्हें हार्डवेयर डिजाइन, सिस्टम वैलिडेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल/एएसआईसी डिजाइन, एफपीजीए, एम्बेडेड सिस्टम तथा सी++, पाइथन, वेरिलॉग जैसे टूल्स व भाषाओं का अनुभव हो। अभ्यर्थी को 12 से 14 सप्ताह तक पूर्णकालिक उपलब्ध होना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2026 निर्धारित की गई है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक लिंक tinyurl.com/yjhk4a6a पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन आमंत्रित

एलपीयूएनईएसटी अध्ययन अनुदान

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) एलपीयूएनईएसटी अध्ययन अनुदान का आठवां संस्करण 2026-27 शुरू कर रही है। इस पहल के माध्यम से एलपीयू, एलपीयूएनईएसटी परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी एवं योग्य छात्रों को आईआईटी, एनआईटी, एम्स, आईआईएम, एनएलयू तथा अन्य केंद्रीय एवं राज्य सरकार के उन संस्थानों में अध्ययन हेतु सहायता प्रदान करता है, जो एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग-2025 में शामिल हैं। इस संस्करण के अंतर्गत छात्र एलपीयू या किसी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान में बीएससी, एमबीबीएस, बीई/बीटेक, बीए, एलएलबी (ऑनर्स), बीकॉम एलएलबी (ऑनर्स), बीबीए एलएलबी (ऑनर्स) अथवा बीएससी एलएलबी (ऑनर्स) जैसे पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर सकते हैं। आवेदक आधिकारिक लिंक lpu.in/studygrant/ पर जाकर 30 अप्रैल, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

सामान्य ज्ञान

समृद्ध कार्यक्रम

■ **क्या है**
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का यह कार्यक्रम एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर है, जो शुरुआती चरण की कंपनियों को मार्गदर्शन व वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके विकास में मदद करते हैं।

■ **चर्चा में क्यों**
हाल ही में, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने लोकसभा में समृद्ध कार्यक्रम की जानकारी दी।

■ **स्टार्टअप को आगे बढ़ाता**
इसका उद्देश्य एक्सेलरेटरों की मदद से आईटी स्टार्टअप्स को चुनना और उन्हें आगे बढ़ाना है। यह कार्यक्रम स्टार्टअप्स को ग्राहकों, निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़कर तेजी से विकास में सहयोग करता है।

■ **वित्तीय सहायता**
यह कार्यक्रम तीन वर्षों में 300 तकनीकी स्टार्टअप्स को सहायता देता है। इसके तहत प्रति स्टार्टअप दो लाख रुपये की मदद और स्टार्टअप्स को 40 लाख रुपये तक की मैचिंग फंडिंग दी जाती है।

पहचान

शख्स : युमनाम खेमचंद सिंह

■ **चर्चा :** राजनीतिक अनिश्चितता के बीच मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने।
क्यों : पारंपरिक ताइक्वांडो में 5वीं डैन ब्लैक बेल्ट पाने वाले पहले भारतीय।

ब्लैक बेल्ट मुख्यमंत्री

पारंपरिक ताइक्वांडो में 5वीं डैन ब्लैक बेल्ट पाने वाले पहले भारतीय हैं। समाजशास्त्र और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी गहरी रुचि है। अनुभवी और साफ-छवि वाले नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। देखना होगा कि चुनौतियों से घिरे मणिपुर राज्य में खेमचंद कितनी मजबूती से खुद को साबित कर पाते हैं।

इंफाल की एक गहरी शाम थी। एक संकरी गली के आखिरी सिरे पर बने छोटे से कमरे में रोज एक बालक खामोशी से जूते उतारता, जमीन को छूकर प्रणाम करता और कसरत करने में डूब जाता था। बालक नहीं जानता था कि एक दिन वह मणिपुर की राजनीति में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। बात हो रही है मणिपुर के नए मुख्यमंत्री 'युमनाम खेमचंद सिंह' की। दसवीं करने के तुरंत बाद, करीब सोलह वर्ष की उम्र में उन्होंने ताइक्वांडो की राह पकड़ ली, जो उनके लिए जीवन को साधने की कला बन गया। जब असम विद्रोह की आग में झुलस रहा था, तब उन्होंने ऑल असम ताइक्वांडो एसोसिएशन की स्थापना की और ताइक्वांडो को असम व मणिपुर में पहचान दिलाई। वर्ष 1990 की कोरिया यात्रा ने उनके भीतर अतिरिक्त आत्मविश्वास भर दिया, जहां उन्होंने कुक्कीवोन से प्रशिक्षण लिया। असम पुलिस से लेकर कई राजनीतिक हस्ती तक, उनके शिष्य बने। फिर वक्त बदला और जीवन ने राजनीति की राह पकड़ी। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ राजनीतिक पदों से नहीं बनी है। हाल ही में, पारंपरिक ताइक्वांडो में उन्हें प्रतिष्ठित 5वीं डैन ब्लैक बेल्ट से सम्मानित किया गया है। यह उपलब्धि पाने वाले वह पहले भारतीय हैं। दिसंबर 2025 में, जब मणिपुर मैतेई और कुकी संघर्ष के जख्मों से जूझ रहा था, तो जीवन भर नियंत्रण और संतुलन का अभ्यास करने वाले खेमचंद सामने आए। वह उन गांवों तक गए, जो हिंसा और संघर्ष से बुरी तरह प्रभावित थे। उनकी मौजूदगी एक राजनीतिक कदम से ज्यादा, भरोसा जीतने की कोशिश थी, जिसने संवाद को संभव बनाया।

शुरुआत

युमनाम खेमचंद सिंह का जन्म मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले के सिंगजामेई में 1 मार्च, 1963 को मैतेई समुदाय हुआ था। पिता युमनाम कलाचंद सिंह और माता गंभिनी देवी की मृत्यु के बाद उनके परिवार में पत्नी जॉयबाला देवी, बेटा केल्विन युमनाम और बेटी कैथरीन युमनाम है। उन्होंने 1978 में इंफाल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा के तहत दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने सियोल स्थित वर्ल्ड ताइक्वांडो अकादमी, कुक्कीवोन से मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षण लिया और ताइक्वांडो में स्नातक डिग्री हासिल की। 1982 में खेमचंद ने असम ताइक्वांडो एसोसिएशन की स्थापना की और लगभग नौ वर्षों तक गुवाहाटी में रहे। 1992 के बाद वह मणिपुर लौटे और कोचिंग शुरू की। वह मणिपुर ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे।

उन्होंने 2012 में राजनीति में प्रवेश कर सिंजामेई सीट से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन 157 वोटों से हार गए। फिर उन्होंने भाजपा का दामन थामा और आरएसएस के करीब आ गए। वह मणिपुर में शाखाओं में भी हिस्सा लेते रहे। वर्ष 2017 से 2022 तक मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष रहे। एन. बीरेन सिंह की सरकार में वह कैबिनेट मंत्री बने और नगर प्रशासन, आवास, शिक्षा, पंचायत राज और विकास जैसे विभागों की जिम्मेदारी संभाली।

सामाजिक कार्यकर्ता व स्वच्छ छवि के नेता

युमनाम खेमचंद ने न केवल ताइक्वांडो में महारत हासिल की, बल्कि वे एक सफल व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। युमनाम की पहचान अनुभवी और साफ छवि वाले नेता के रूप में होती है।

दक्षिण कोरिया है पसंदीदा

युमनाम खेमचंद सिंह की पसंदीदा जगह दक्षिण कोरिया है। वह इसे एक बेहद खास और 'पावन स्थान' मानते हैं। उनका मानना है कि जैसे एक हिंदू के लिए वृंदावन जाना महत्वपूर्ण है, वैसे ही ताइक्वांडो सीखने वाले के लिए कोरिया जाना अनिवार्य है।

किताबें, भोजन और संगीत

युमनाम खेमचंद को ऐतिहासिक जीवनियां और सामरिक अध्ययन की किताबें पढ़ना पसंद है। उनकी समाजशास्त्र और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी गहरी रुचि है। उन्हें मणिपुर का पारंपरिक भोजन जैसे 'इरोंबा' और 'चाक-हाओ' बहुत पसंद है। मणिपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विशेषकर 'संकीर्तन' और लोक संगीत में उनकी गहरी रुचि है। वह प्रकृति प्रेमी हैं और अपने खाली समय में पौधों की देखभाल करते हैं। उन्हें मणिपुरी भाषा, अंग्रेजी और हिंदी आती हैं, और वे कई भाषाएं सीखने में भी रुचि रखते हैं।

अनुशासित और अच्छे श्रोता

खेमचंद सिंह सुबह जल्दी उठते हैं। शुरुआत शारीरिक अभ्यास और ध्यान से करते हैं। मार्शल आर्ट्स का अभ्यास उनके डेली रूटीन का वह हिस्सा है जिसे वे कभी नहीं छोड़ते। इसके बाद ही वे अपने सार्वजनिक जीवन और लोगों की सेवा के लिए निकलते हैं। वह बहुत अच्छे श्रोता हैं। करीबी बताते हैं कि वे लोगों की बातों को बहुत धैर्य से सुनते हैं। वे अक्सर छोटे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होकर आम लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं।

नेपथ्य के नायक

खेमचंद सिंह के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वे लाइमलाइट से दूर पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद करते हैं। उनके करीबियों का कहना है कि वे फाइलों से ज्यादा लोगों के चेहरों को पढ़ना जानते हैं। मणिपुर के हालिया संकटों के दौरान, जब प्रदेश अशांति के दौर से गुजर रहा था, तब खेमचंद उन चुनिंदा नेताओं में से थे, जिन्होंने शांति बहाली के लिए पर्दे के पीछे रहकर समुदायों के बीच संवाद बहाल करने की पहल की।

आज का दिन

7 फरवरी, 1992

पहली स्वदेशी पनडुब्बी 'आईएनएस शाल्की' भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुई थी। इसे मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया था। यह शिशुमार श्रेणी की डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है।

- **1477 :** ब्रिटिश मानवतावादी और राजनेता सर थॉमस मोर का जन्म लंदन में हुआ था।
- **1940 :** अमेरिकी एनिमेटेड फिल्म 'पिनोचियो' का विश्व प्रीमियर हुआ था।
- **1974 :** ग्रेनाडा को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली थी।
- **2019 :** अमेरिकी बेसबाल खिलाड़ी फ्रैंक रॉबिन्सन का निधन हुआ था।

व्रत त्योहार

आज : फाल्गुन कृष्ण पक्ष षष्ठी।
कल : शिशिर ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, दक्षिण गोले।
राहुकाल : सायं 16.30 से 18.00 तक।

■ सूर्योदय : 07.09
■ सूर्यास्त : 18.02
(भारतीय मानक समयानुसार)

कल का पंचांग

विक्रमी संवत 2082, 19 माघ मास शक 1947, माघ मास 26 प्रविष्टे, 19 सावान हिजरी 1447, फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी 29.01 तक उपरांत अष्टमी, स्वाती नक्षत्र 29.02 तक उपरांत विशाखा नक्षत्र, गंड योग 24.07 तक उपरांत वृद्धि योग, विष्टि (भद्रा) करण 15.56 तक उपरांत बव करण, चंद्रमा तुला राशि में दिन-रात।

amarujala.com/astrology

राशिफल

■ पं. विनोद त्यागी

मेष : नाते-रिश्तेदारों से भेंट हो सकती है। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। जमीन-जायदाद के अटके कार्य बन सकते हैं।

वृष : अर्थ प्राप्ति हो सकती है। संतान पक्ष की कुछ चिंता रहेगी। व्यवसाय में लाभ होगा। घर में शांति बनी रहेगी।

मिथुन : दिनमान प्रतिकूल रहेगा। बनते कार्य में निराशा हो सकती है। नौकरी में वाद-विवाद से दूरी बनाए रखें।

कर्क : उतावलेपन में निर्णय लेने से बचें। भू-संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। व्यवसाय में उत्तम लाभ हो सकता है।

सिंह : स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अटका कार्य बनेगा। पुराने मित्र से भेंट संभव है। नौकरी में स्थिति अनुकूल रहेगी।

कन्या : शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा। किसी इच्छा की पूर्ति हो सकती है। नौकरी में मान-सम्मान बढ़ेगा।

तुला : स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। विरोधी पक्ष से सावधानी बरतें। नौकरी में श्रम की अधिकता रहेगी।

वृश्चिक : पठन-पाठन में रुचि रहेगी। अटका कार्य बनेगा। कार्य क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। व्यवसाय में लाभ होगा।

धनु : मानसिक उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। कार्यक्षेत्र में वर्चस्व बना रहेगा। व्यवसाय में लाभ कम होगा।

मकर : मनोइच्छापूर्ति का अवसर मिलेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी आ सकती है। व्यवसाय में धन लाभ होगा।

कुंभ : वाणी पर नियंत्रण रखें। स्वजनों से मनमुटाव रहेगा। निर्णय लेने में सावधानी बरतें। वाहन सावधानी से चलाएं।

मीन : वाद-विवाद से बचें। राजकाज में अनुकूलता रहेगी। प्रभावी व्यक्ति से परिचय हो सकता है।

जन्मदिन

शिखा सिंह, अभिनेत्री

इस वर्ष प्रारंभ में योजनाओं में अवरोध आएंगे। विश्वासपात्रों से निराशा होगी। सामाजिक मान-सम्मान में कमी आ सकती है। न्याय क्षेत्र में विजय मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। नौकरी में प्रमोशन या अनुकूल स्थानांतरण संभव है। अविवाहितों के विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

सुडोकू

	9		2		7			
				8		9		
4					9		7	5
			4	5				
	5	2				4	3	
				3	1			
7	4		5					8
		6		1				
			8		3		5	

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

3	9	5	2	4	7	8	1	6
2	6	7	1	8	5	9	4	3
4	1	8	3	6	9	2	7	5
8	3	1	4	5	2	7	6	9
6	5	2	7	9	8	4	3	1
9	7	4	6	3	1	5	8	2
7	4	3	5	2	6	1	9	8
5	8	6	9	1	4	3	2	7
1	2	9	8	7	3	6	5	4

डेली हेल्थ कैप्सूल

काली मिर्च और शहद का सेवन है फायदेमंद

काली मिर्च और शहद का सेवन करने से सर्दी-जुकाम और पाचन की समस्या के साथ संक्रमण से बचाव होता है।

आयुर्वेद में शहद को प्राकृतिक एंटीबायोटिक के रूप में जाना जाता है, जबकि काली मिर्च एक प्रभावशाली एंटीऑक्सिडेंट है। इनका एक साथ सेवन करने से सेहत में सुधार होता है। साथ ही कई बीमारियों में लाभ मिलता है। शहद में मौजूद गुण गले की सूजन को कम करते हैं, जबकि काली मिर्च के सेवन से छाती में जमे बलगम को पतला करने में

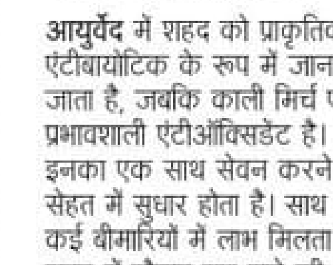

मदद मिलती है। इनका सेवन अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और अन्य सांस संबंधी समस्याओं के लिए फायदेमंद होता है। इससे श्वसन तंत्र की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। काली मिर्च में मौजूद पिपरिन पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। शहद आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है। काली मिर्च और शहद के सेवन से गैस, अपच में आराम मिलता है। इनमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स इम्युनिटी को मजबूत बनाते हैं। काली मिर्च मेटाबॉलिज्म को तेज करके शरीर में चर्बी को कम करने की प्रक्रिया को तेज करती है। काली मिर्च ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखती है और रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखती है। शहद में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स दिल के कार्य को सुचारू बनाते हैं। इससे दिल की बीमारियों का जोखिम कम होता है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

काली मिर्च गरम होती है। इसके अधिक सेवन से गैस, जलन, मुंह के छाले और अम्ल,पित्त बढ़ सकता है। इसे खाली पेट लंबे समय तक न लें। गर्भवती महिलाएं भी पहले चिकित्सक से सलाह लें।
-डॉ. नवदीप जोशी
प्राकृतिक चिकित्सक

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

जानलेवा भ्रष्टाचार

मेघालय में एक अवैध कोयला खदान में हुए विस्फोट में अठारह मजदूरों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से जख्मी मजदूर अस्पताल में भर्ती है और अंदेशा है कि कुछ अन्य मजदूर अभी भी खदान में फंसे हों। यह 'रैट होल' खदान है, जिसमें इतनी संकरी सुरंगें बनाकर खनन किया जाता है, जिनसे मजदूर रेंगकर ही घुस या निकल सकते हैं। ये खदानें पर्यावरण के लिए भी बहुत घातक हैं। इनकी असुरक्षित व अमानवीय परिस्थिति की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट और ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इनको प्रतिबंधित किया हुआ है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में ऐसी खदानें धड़ल्ले से चल रही हैं। अनुमान है कि सिर्फ मेघालय में लगभग 25,000 ऐसी गैर-कानूनी खदानें चल रही हैं। जाहिर है, इतने बडे पैमाने पर यह अवैध काम बिना प्रशासनिक मिलीभगत और भ्रष्टाचार के संभव नहीं है। इसके पहले मेघालय में ही 2018 में बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसमें पंद्रह मजदूर मारे गए थे। बहुत संभव है कि और भी दुर्घटनाएं इन खदानों में होती हों, जिनकी खबर तक बाहर नहीं आ पाती हो।

ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक नेकनीयती व सख्ती से ऐसे गैर-कानूनी और अमानवीय कारोबार पर रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार का जाल इतना मजबूत है कि उसके आगे तमाम कानून और आदेश व्यर्थ हो जाते हैं। देश में कई बार भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुए, कुछेक बार इन आंदोलनों की वजह से सरकारें भी बदलीं, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत ही होती गईं। 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट से तो यही जाहिर होता है। भ्रष्टाचार कम करने के लिए जरूरी है कि सरकारी तंत्र और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता व सरलता लाई जाए, पर होता यह है कि भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर प्रक्रियाओं को ज्यादा जटिल और अपारदर्शी बना दिया जाता है, जिससे अधिकारियों व संस्थानों की जवाबदेही और कम हो जाती है। ऐसे में, भ्रष्टाचार की गुंजाइश बढ़ जाती है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने वाली संस्थाओं को स्वतंत्र व मजबूत बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने की इच्छा हमारी राजनीतिक संस्कृति में नहीं है, इसलिए इसमें पकड़े जाने की गुंजाइश जितनी कम है, पकड़े जाने पर सजा मिलने की गुंजाइश उससे भी कम है।

मेघालय की खदान में मरने वाले गरीबों और नोएडा के उच्च मध्यवर्गीय लोगों की लड़ाई एक है। जरूरी है कि वे आपसी हमदर्दी महसूस करें, तभी साझा दुश्मन से लड़ पाएंगे।

सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत के आम नागरिक की गरिमा, उसके अधिकार, उसकी जान की परवाह भी हमारे तंत्र में कम ही है, बल्कि यह परवाह हमारे समाज में ही नहीं है, जो इन आम नागरिकों से बना है। हमारे समाज के लोगों में ही दूसरे लोगों, खासकर अलग वर्ग, समुदाय या क्षेत्र के, यानी अपने से अलग लगने वाले लोगों के दुख-दर्द या समस्या के प्रति वैसी हमदर्दी नहीं देखने को मिलती, जैसी एक देश में अपेक्षित है और भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में तो हमेशा ही ज्यादातर लोग हमसे अलग ही होंगे। मेघालय की किसी खदान में मरने वाले गरीब मजदूरों की पीड़ा जब तक महानगरों के लोग महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम सब अलग-अलग इस भ्रष्टाचार और लापरवाही के शिकार होते रहेंगे या सिर्फ शिकार नहीं होंगे, बल्कि जाने-अनजाने उसके जिम्मेदार भी होंगे। अभी एक खबर आई है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नोएडा ट्विन टावर मामले में सरकारी जांच कमेटी ने 11 अफसरों को दोषी पाया है। इससे पता चलता है कि मेघालय की खदान में मरने वाले गरीब मजदूर और नोएडा के उच्च मध्यवर्गीय लोगों की लड़ाई दरअसल एक ही है, इसलिए जरूरी है कि वे आपस में हमदर्दी और भाईचारा महसूस करें, तभी वे इस साझा दुश्मन से लड़ पाएंगे।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले

07 फरवरी, 1951

खाद्यान्न की चुनौती

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की व्यवस्था समिति और भारतीय कृषि अनुसंधान संघ के दीक्षान्त समारोह में भाषण करते हुए राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने एक महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत विदेशों से जो अन्न मंगाता है, वह भारत के वैज्ञानिकों और किसानों के लिए एक चुनौती है। 'भारत एक कृषि प्रधान देश है।' यह बताते हुए उन्होंने ठीक ही कहा कि 'इसलिए हमारे लिए यह शर्म की बात है कि हम अपने भोजन के लिए दूसरे देशों पर अवलम्बित रहें और अपनी खाद्य-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने यहां उत्पादन न कर सकें।' उन्होंने यह भी बताया कि केवल अन्न की ही हमारे देश में कमी नहीं है, बल्कि फलों, दूध तथा दूध से निर्मित पदार्थों की भी हमें पूर्ति करनी है। यह स्थिति लज्जास्पद है और राष्ट्रपति के कहे की हम उपेक्षा से न ले लें, तो इसे चुनौती-स्वरूप ही लेना चाहिए और इस चुनौती के मुकाबले के लिए हमारे वैज्ञानिकों तथा किसानों को जुट जाना चाहिए।

इसी अवसर पर भाषण करते हुए हमारे खाद्य-मंत्री श्री कन्हैयालाल मुंशी ने बड़े सुन्दर शब्दों में इस बात को फिर दोहराया है कि 'यदि देशव्यापी प्रयत्न किया गया, तो हम मार्च 1953 की लक्ष्य-अवधि तक 17 लाख टन खाद्यान्न, 6 लाख गांठ रूई और 18 लाख गांठ पटसन की अतिरिक्त उत्पत्ति करके अपने उत्पादन-कार्यक्रम को पूरा कर सकेंगे।' साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया है कि अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन के फलस्वरूप सन् 1950-51 में 17 लाख टन अन्न की उपज बढ़ी है। श्री मुंशी के ऐसे कथन पढ़कर भोले लोग चक्कर में पड़ सकते हैं परन्तु खाद्य-संबंधी जो स्थिति यथार्थ में सन्मुख है, उसे देखते हुए उनका इस तरह के अगर-मगर में लोगों को गुमराह करना ठीक नहीं मालूम पड़ता। वस्तुतः उन्हें अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन की असफलता को स्वीकार कर उसे ऐसा रूप देने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे वह कुछ कारगर सिद्ध हो सके। इस दृष्टि से राष्ट्रपति के सुझाव अधिक उपयोगी हैं, जिन्होंने कहा है कि कृषि अनुसंधानशाला को ऐसे अनुसंधान-कार्य पर ध्यान देना चाहिए, जिससे वास्तव में तथा शीघ्र कृषि को लाभ हो। राष्ट्रपति की यह बात भी गले उतरने वाली है कि किसानों से सम्पर्क बढ़ाया जाये और कृषि औजारों में जो सुधार किये जायें, वे व्यावहारिक हों।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की अंतिम रूपरेखा अभी सामने नहीं आई है, हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये और उनके सिपहसालारों ने मीडिया टिप्पणियों में इस समझौते के कई बिंदुओं को सामने रखा है। संसद में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस पर सरकार का पक्ष रखा है। फिर इस करार को लेकर हंगामा क्यों मच रहा है? देश पर दूरगामी असर वाले इस समझौते पर दो पक्ष :

आमने-सामने

लेन-देन वाली दुनिया में मजबूती से बढ़ा भारत

यहां स्कैन करें

गौरव वल्लभ | सदस्य, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद

- निर्यात पर 18 फीसदी का शुल्क 50 प्रतिशत की तुलना में काफी कम है।
- साल 2022 के बाद हमने कच्चे तेल आयात के स्रोतों को पुनर्गठित किया है।
- इस समझौते में कृषि और डेयरी क्षेत्र सुरक्षित रखे गए हैं।

बीती 2 फरवरी को घोषित भारत-अमेरिका व्यापार समझौता इस बात को दर्शाता है कि अस्थिर वैश्विक व्यवस्था में आर्थिक संबंधों पर बातचीत का तरीका कैसे बदल रहा है। आज व्यापार केवल शुल्क-सूचियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि तुलनात्मक बाजार पहुंच और रणनीतिक विश्वास से जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में नई दिल्ली द्वारा हासिल किया गया नतीजा अमेरिका के साथ भारत की आर्थिक सौदेबाजी की क्षमता में एक संतुलित, मगर ठोस मजबूती दिखाता है।

इस समझौते का सबसे अहम पहलू अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यात पर शुल्क को 18 प्रतिशत पुनः निर्धारित करना है। यह पहले लगाई गई 50 प्रतिशत दर की तुलना में काफी कम है और एशियाई निर्यातकों के बीच भारत को अपेक्षाकृत अनुकूल स्थिति में रखता है। व्यावहारिक तौर पर इसका अर्थ यह है कि भारतीय वस्तुएं अब अमेरिकी बाजार में वियतनाम, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे प्रतिस्पर्द्धी देशों से कम शुल्क पर प्रवेश करेंगी। पिछले कुछ महीनों में रुपये के अवमूल्यन के साथ मिलकर यह स्थिति भारत की निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता को वास्तविक बढ़त दे सकती है। गौरतलब है, अमेरिका द्वारा सहयोगी देशों में भारत पर सबसे कम टैरिफ में से एक लगाया जाना हमारे प्रति उसके आर्थिक भरोसे को दर्शाता है। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए यह एक बड़ा अवसर सिद्ध हो सकता है। कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए भी यह समझौता नए निवेश और व्यापार के विस्तार के द्वार खोलता दिख रहा है।

अमेरिका अब भारत के कुल वस्तु निर्यात का लगभग पांचवां हिस्सा आयात करता है, जो इस दशक की शुरुआत में लगभग 15 प्रतिशत था। पिछले वर्ष शुल्क को लेकर अनिश्चितता के दौर में भी भारत का अमेरिका में निर्यात बढ़ता रहा और वित्त-वर्ष 25-26 के पहले नौ महीनों में यह लगभग 65 अरब डॉलर को पार कर गया। यह वृद्धि उस अवधि में भी हुई, जब कुछ समय के लिए शुल्क काफी अधिक थे, जिससे स्पष्ट होता है कि भारतीय वस्तुओं की मांग संरचनात्मक रूप से मजबूत बनी हुई है। इसलिए यह समझौता किसी नए मोड़ को पैदा करने के बजाय एक मौजूदा प्रवृत्ति को सुदृढ़ करता है।

अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात में इंजीनियरिंग वस्तुएं, रसायन, वस्त्र, चमड़े के उत्पाद, समुद्री उत्पाद व रत्न-आभूषण बड़ा हिस्सा रहे हैं। ये वही क्षेत्र हैं, जिनमें ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी शुल्क औसत से अधिक रहे हैं, विशेषकर वस्त्र, परिधान और फुटवियर में। शुल्क अंतर में कुछ प्रतिशत की भी कमी, विशेषकर कम मार्जिन पर काम करने वाले निर्यातकों के लिए 'लैंडेड कॉस्ट प्रतिस्पर्द्धा' को काफी बेहतर बनाती है। समझौते की घोषणा के बाद रुपया थोड़ा मजबूत हुआ और डॉलर के मुकाबले एक रुपये से अधिक की रिकवरी के साथ लगभग 90 के स्तर पर आ गया। यह इस समझ को दर्शाता है कि यह समझौता कोई नई संवेदनशीलता नहीं पैदा करता, बल्कि मजबूत निर्यात प्रदर्शन के जरिये उन्हें कुछ हद तक कम कर सकता है।

ऊर्जा से जुड़े पहलू इस सौदे की पृष्ठभूमि में शांत रूप से मौजूद हैं। साल 2022 के बाद से भारत ने अपने कच्चे तेल आयात के स्रोतों को पुनर्गठित किया है, जिसमें रूस की हिस्सेदारी नगण्य स्तर से बढ़कर अपने चरम पर एक-तिहाई से अधिक हो गई। रियायती कीमतों से प्रेरित इस बदलाव ने उस समय भारत को वैश्विक ऊर्जा महंगाई से बचाने में मदद की, जब तेल की कीमतें ऊंची थीं। साथ ही, भारत ने आपूर्ति का विविधीकरण जारी रखा है और पश्चिम एशिया, अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका व लैटिन अमेरिका सहित लगभग 40 देशों से कच्चा तेल मंगाया है।

उदाहरण के लिए, अमेरिकी कच्चे तेल की हिस्सेदारी पांच साल पहले की तुलना में अब काफी अधिक है।

आयात पक्ष पर दिखाई देने वाला संयम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अधिक संरक्षण मुख्यतः खाद्य उत्पादों, पशु उत्पादों व फुटवियर तक सीमित है, जो अमेरिका से होने वाले आयात का नगण्य हिस्सा हैं। इसके विपरीत, अमेरिकी शुल्क ऐतिहासिक रूप से उन्हीं श्रेणियों में अधिक रहे हैं, जहां भारत बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। इस प्रकार मौजूदा वार्ता का परिणाम ऐसी विषमता को दर्शाता है, जो घरेलू व्यवधान पैदा किए बिना भारत के पक्ष में काम करती है। कृषि और डेयरी क्षेत्र सुरक्षित रखे गए हैं, जो भारत के विशाल उत्पादन आधार के अनुरूप है। 2010 के दशक के मध्य से दूध उत्पादन में 35 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है और यह सालाना 200 मिलियन टन को पार कर चुका है, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बन गया है। ऐसे क्षेत्रों में उदारीकरण की आर्थिक व राजनीतिक कीमत अनुपातहीन रूप से अधिक होती है, यह समझौता उन सीमाओं को परखने से बचता है।

यह समझौता आने वाले वर्षों में अमेरिका से लगभग 500 अरब डॉलर तक की खरीद बढ़ाने के भारत के घोषित इरादे से भी जुड़ा है, जिसमें ऊर्जा, रक्षा, नागरिक उड्डयन और उच्च-मूल्य विनिर्माण शामिल हैं। यह आंकड़ा संकेतात्मक है, बाध्यकारी नहीं, पर अमेरिका से मौजूदा वार्षिक आयात (लगभग 45-50 अरब डॉलर) की तुलना में काफी महत्वपूर्ण है। धीरे-धीरे यह विस्तार व्यापारिक संबंधों को गहराई से मजबूत करेगा, विशेषकर पूंजी व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर मांग के माध्यम से बाजार पहुंच को सहारा देने की इच्छा का संकेत देगा।

समग्र रूप से देखें, तो यह समझौता दिखाता है कि भारत एक अधिक लेन-देन आधारित वैश्विक व्यापार वातावरण में कैसे आगे बढ़ रहा है। जिसका सबसे अधिक महत्व है, वहां निर्यात पहुंच में सुधार हुआ है, ऊर्जा लचीलापन बना हुआ है व संवेदनशील घरेलू क्षेत्र संरक्षित हैं। ऐसे समय में, जब व्यापार परिणाम औपचारिक नियमों से अधिक सौदेबाजी की क्षमता और रणनीतिक प्रासंगिकता से तय हो रहे हैं, भारत ने ऐसा समझौता हासिल किया है, जो उसकी स्थिति को मजबूत करता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

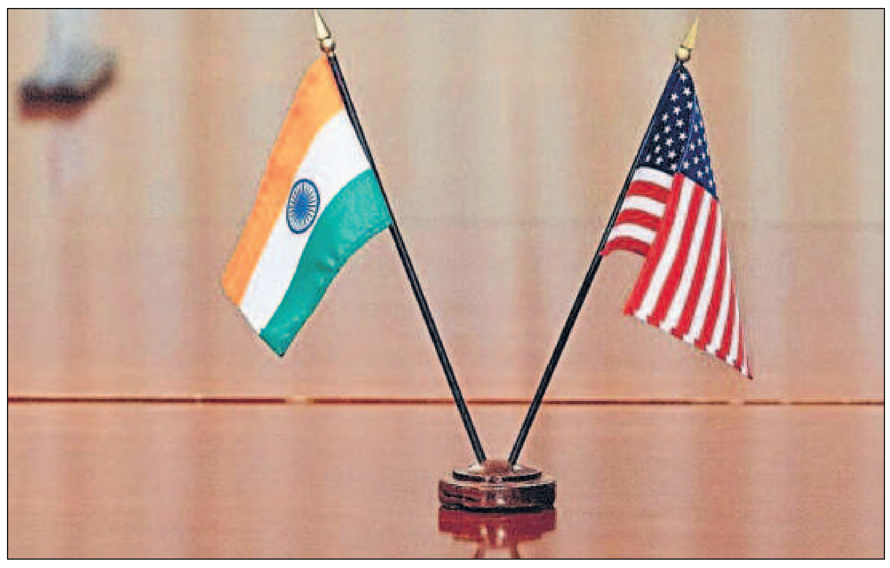

बर्बादियों का जश्न मना रहा सत्तारूढ़ पक्ष

यहां स्कैन करें

सुप्रिया श्रीनेत | अध्यक्ष, कांग्रेस सोशल मीडिया

- 18 प्रतिशत ट्रेड टैरिफ पर कैसी खुशी, पहले यह औसतन 2.93 प्रतिशत था।
- भारत को अब रूस के बदले अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदना होगा।
- सरकार इसे कोई भी रंग दे, पर देश के अन्नदाताओं के हितों की बलि चढ़ा दी।

हम दोनों फिल्म के लिए साहिर लुधियानवी का लिखा और मोहम्मद रफी का गाया मशहूर नज्म *बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया* आज केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर चरितार्थ हो रहा है, क्योंकि जिस व्यापार समझौते को अपनी बड़ी उपलब्धि बताकर सत्तारूढ़ दल या सरकार ढोल पीट रही है, वह देश के लिए घातक है।

भारत पर लगे 18 प्रतिशत ट्रेड टैरिफ के लिए खुशियां मनाना एकदम नादानी है, क्योंकि अभी तक अमेरिका भारत पर औसतन 2.93 प्रतिशत से कम टैरिफ लगाता था। यह टैरिफ मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा परमाणु डील साइन करने से पहले 3.3 प्रतिशत होता था। तो सरकार किस बात पर अपनी पीठ ठोक रही है? किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? छह गुना टैरिफ बढ़ जाने का या लोगों को भ्रमित करने का? वास्तव में, भारत और अमेरिका के व्यापार समझौते पर खुश होने वाले या तो बहुत अनभिज्ञ हैं या जबरदस्त शातिर। यह समझौता इतना एकतरफा और भारत के हितों के खिलाफ है कि इसको सही ठहराने वालों के विवेक पर संदेह होता है।

सर्वप्रथम, इस ट्रेड डील की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। इस समझौते की सारी विस्तृत जानकारी भी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ही दी गई। अमेरिका भारतीय निर्यात पर 18 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा, जबकि इससे पहले भारत से निर्यात की जाने वाली चीजों पर तीन फीसदी से कम टैरिफ लगता था। भारत अमेरिकी वस्तुओं पर शून्य प्रतिशत टैरिफ, यानी कोई टैरिफ नहीं लगाएगा, जबकि इससे पहले भारत अमेरिका से आयातित सामान पर 30 से 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाता था।

समझौते के अनुसार, भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर की ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, खेती की चीजें, कोयला खरीदेगा और बाकी चीजों की खरीद में भी बढ़ोतरी करेगा। भारत अब रूस का सस्ता तेल नहीं खरीदेगा। इसके बदले वह अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप द्वारा दी गई जानकारी का उल्लेख करते हुए अमेरिका की कृषि मंत्री ब्रुक रोलिंस ने इसे अमेरिकी किसानों के लिए जबरदस्त खबर बताया और कहा कि इससे भारत का बड़ा बाजार अब अमेरिकी किसानों के लिए खुल जाएगा। इस बात की पुष्टि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीयर ने की, यह जानकारी व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने अमेरिकी मीडिया को दी। इधर, भारत सरकार ने 48 घंटे बाद सदन में एक वक्तव्य पढ़ा, जिसमें कोई विवरण नहीं था, न ही ट्रंप द्वारा की गई विस्तृत घोषणा की एक भी बात का खंडन था। अगर राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा दी गई जानकारी भ्रामक है, तो सरकार को उसका खुलकर खंडन करना चाहिए। सरकार का प्रतिकार न करना और इस तरह से मौन रहना असल में उनकी सहमति है।

इसीलिए कुछ ज्वलंत सवाल उठते हैं- पहला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीजफायर की तरह हमारे व्यापार समझौते की घोषणा पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यों की? दूसरा, पहले भारत से अमेरिका को निर्यात की जाने वाली चीजों पर तीन फीसदी से कम टैरिफ लगता था, अब 18 फीसदी लगेगा, तो यह भारत की जीत कैसे हुई? तीसरा, जिन अमेरिकी वस्तुओं पर भारत 30 से 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाता था, उस पर हम कोई भी टैरिफ नहीं लगाने पर सहमत कैसे हो गए? चौथा, भारत ने अमेरिका के लिए अपना बाजार पूरी तरह से खोलने पर सहमति जता दी है। ऐसे में, हमारे घरेलू उद्योगों और व्यापारियों, हमारी कंपनियों का क्या होगा?

पांचवां, ज्यादा अमेरिकी सामान खरीदने से हमारे 'मेक इन इंडिया' अभियान का क्या होगा? हमारे पहले से ही चरमराते विनिर्माण उद्योगों का क्या होगा? छठा, जिस तरह से इस व्यापार समझौते के बाद अमेरिकी कृषि मंत्री खुशी जता रही हैं, उससे साफ है कि अमेरिकी किसानों की बल्ले-बल्ले है, लेकिन हमारे किसानों पर इस तरह का हमला करने के लिए प्रधानमंत्री क्यों राजी हो गए? सातवां, अमेरिका कौन होता है यह निर्णय करने वाला कि हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? रूस का तेल सस्ता था, हमारी खपत का 40 प्रतिशत तेल वहीं से आ रहा था और आठवां सवाल यह कि क्या अभी भी हमें ईरान के चाबहार पोर्ट परियोजना से बाहर रहना पड़ेगा?

अब तक तीन फीसदी से कम रहे टैरिफ का, जो अब 18 फीसदी हो गया है, बड़ा प्रभाव हमारी निर्यात कंपनियों पर पड़ेगा। खासतौर से उन उद्योगों में, जहां बड़ी संख्या में लोग कार्यरत हैं। जैसे, रत्न, आभूषण, कालीन, वस्त्र, मशीनरी, फार्मा, फुटवियर, केमिकल इत्यादि। उनकी मार्जिन घटेगी और मुनाफा भी कम होगा, जिसका सीधा असर उनके द्वारा दिए गए रोजगार पर पड़ेगा। भारतीय कंपनियों द्वारा भारत के बाहर किया गया निवेश पिछले दो सालों में 14 बिलियन डॉलर से बढ़कर 24 बिलियन डॉलर हो गया है। इस नई डील के अंतर्गत यह और बढ़ेगा।

साफ है, अमेरिका से इतनी ज्यादा खरीद का हमारे व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसके साथ हमारा व्यापार मुनाफा है, यानी हमारे हक में है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से 45.6 बिलियन डॉलर का सामान आयात किया था और वहां 86.5 बिलियन डॉलर का निर्यात किया था, जिसके चलते हमारा व्यापार मुनाफा 40.9 बिलियन डॉलर था। हम पर 18 प्रतिशत टैरिफ और अमेरिका पर शून्य टैरिफ हमारे व्यापार घाटे को बढ़ा देगा। देश के अन्नदाताओं के हितों की बलि चढ़ा दी गई है।

सरकार इस डील को चाहे कोई भी रंग दे, पर महीनों से अटकी पड़ी इस डील का एकाएक हो जाना संदेह और सवाल पैदा करता है। यह समझौता देश की अर्थव्यवस्था, वैश्विक व्यापार, हमारे व्यापार घाटे के लिए हानिकारक है ही, इसका दुष्प्रभाव भारतीय उद्योग, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग, यहां होने वाले निवेश व किसानों पर जरूर पड़ेगा। इस समझौते ने अनिश्चितता खत्म नहीं की, बल्कि आशंकाएं बढ़ा दी हैं। साथ ही, अमेरिका के रवैये और मोदी सरकार के मौन ने एक बार फिर से भारत की स्वाधीनता, हमारी संप्रभुता को ललकारा है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

वही वासना मुक्त होगा...

कर्मवाद का तात्पर्य यह है कि हमें अपने भले-बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और सारे दर्शनशास्त्रों का एकमात्र उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपनी महिमा को जान ले।

सभी शास्त्र मनुष्य की- आत्मा की -महिमा की घोषणा कर रहे हैं, फिर उसके साथ कर्मवाद का भी प्रचार कर रहे हैं। शुभ कर्मों का शुभ फल और अशुभ कर्मों का अशुभ फल होता है। यदि शुभ और अशुभ कर्म आत्मा पर प्रभाव डाल सकते हैं, तो फिर आत्मा तो कुछ भी नहीं रही। वास्तव में, अशुभ कर्म तो व्यक्ति के अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति में बाधा भर डालते हैं और शुभ कर्म उन बाधाओं को दूर कर देते हैं। तभी मनुष्य की महिमा प्रकट होती है। स्वयं व्यक्ति में कभी परिवर्तन नहीं होता। तुम चाहे जो करो, तुम्हारी महिमा को, तुम्हारे अपने स्वरूप को कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता; क्योंकि कोई भी वस्तु आत्मा पर प्रभाव नहीं डाल सकती। उससे आत्मा पर मानो एक आवरण भर पड़ जाता है, जिससे आत्मा की पूर्णता ढक जाती है। योगी जल्दी-जल्दी कर्म का क्षय कर डालने के लिए शरीर-समूह का सृजन करते हैं। फिर इन सब शरीरों के लिए वे अपनी अस्मिता या अहं-तत्व से बहुत से चित्त की सृष्टि करते हैं। इन निर्मित चित्तों का, मूल चित्त से भेद स्पष्ट करने को 'निर्माणचित्त' कहते हैं।

विभिन्न व्यक्तियों में हम जो विभिन्न प्रकार के मन देखते हैं, उनमें वही मन सबसे ऊंचा है, जिसे समाधि की अवस्था प्राप्त हुई है। कुछ लोग औषधि, मंत्र और तपस्या के बल से कुछ शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं, मगर उनकी वासनाएं बनी ही रहती हैं; लेकिन जो व्यक्ति योग द्वारा समाधि प्राप्त कर लेता है, केवल वही वासनाओं से मुक्त होता है।

स्वामी विवेकानंद

मलाला यूसुफजई | नोबेल विजेता

यह बेहद परेशानी की बात है कि पाकिस्तान में महिलाओं को सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है और दस साल से ज्यादा जेल की सजा दी जा रही है। यह तो उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

दंड के बिना नहीं सुधरेगा नगर प्रशासन

देश की राजधानी के जनकपुरी इलाके में जोगिंदर सिंह मार्ग पर शुक्रवार को दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही एक हंसते-खेलते परिवार पर भारी पड़ गई। एक 25 साल का युवक, जो अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुन रहा था, सड़क पर खुले पड़े 20 फुट गहरे गड्ढे में मोटरसाइकिल समेत गिरा और काल के गाल में समा गया। मृतक की पहचान कमल के रूप में हुई है। इससे पहले, इसी तरह की एक अन्य दुर्घटना में नोएडा के सेक्टर-150 में गत 16 जनवरी की रात एक दर्दनाक हादसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार पानी से भरे गहरे गड्ढे (बेसमेंट के लिए खोदा गया) में गिर गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई। 70 फीट गहरे गड्ढे में डूबकर मरने से पहले उन्होंने लगभग दो घंटे तक मदद की कातर गुहार लगाई, लेकिन उन्हें कोई नहीं बचा पाया।

कमल के जुड़वां भाई करण और उनके परिवार के लोग रात 1 बजे से ही दिल्ली की सड़कों और थानों के चक्कर काट रहे थे। उन्होंने जनकपुरी और विकासपुरी थाने में गुहार लगाई और उस रास्ते को खंगाला, जिससे कमल रोज आते-जाते थे। हैरानी की बात यह है कि परिजन रात में उस गड्ढे के पास भी पहुंचे थे, जहां यह हादसा हुआ था। करण ने बताया कि 'हमने उस गड्ढे के पास फ्लैश लाइट जलाकर भी देखा था, लेकिन वहां सुरक्षा का कोई इंतजाम या चेतावनी बोर्ड नहीं था।' जब सुबह उजाला हुआ, तब पता चला कि जिस गड्ढे के पास खड़े होकर वह अपने भाई को आवाज दे रहे थे, कमल उसी में गिरकर दम तोड़ चुका था। दिल्ली सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त कदम उठाए हैं। उसने दिल्ली जल बोर्ड के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर व जूनियर इंजीनियर को तत्काल निलंबित कर उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है।

बात इतनी सी ही नहीं है। इस तरह के हादसों को केवल दुर्घटना मानकर छोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि यह उस पूरे सिस्टम की नाकामी है, जो बैरिकेडिंग और सुरक्षा के नाम पर खानापूर्ति करता है। आखिर प्रशासन को यह जवाब देना ही चाहिए कि नोएडा जैसी दर्दनाक घटना के बाद भी दिल्ली में खुले गड्ढे ऐसे कैसे पड़े थे? जहां तक नोएडा वाली घटना का प्रश्न है, तो उसके जिम्मेदार बिल्डर को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, क्योंकि प्रशासन ने उसके खिलाफ कोई ठोस सुबूत ही नहीं रखा। दिल्ली में भी प्रशासन द्वारा इसी तरह की लीपापोती की जाएगी। होना यह चाहिए कि जिम्मेदार प्रशासन के पूरे अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आगे से किसी भी विभाग के अधिकारी-कर्मचारी लापरवाही के बारे में न सोचें।

रितुराज, छात्र

हर बात पर सरकार को कोसना ठीक नहीं

कांग्रेस की चर्चित राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट की है- 'दिल्ली के रहने वाले कमल ऑफिस से घर के लिए निकले। रास्ते में बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ था। कमल बाइक के साथ गड्ढे में गिर गए, उनकी मौत हो गई। गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड ने खोदा था, लेकिन न कवर किया, न कोई बैरिकेड लगाया और न चेतावनी का बोर्ड! बीजेपी के डबल इंजन में यह मौत है या हत्या? आप बताइए?'

कमल तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनके माता-पिता और परिजनों का दर्द समझा जा सकता है। कांग्रेस की प्रवक्ता ने उनके प्रति सहानुभूति का एक वाक्य नहीं लिखा, पर सियासत का मौका हाथ से न जाने दिया। हम यहां दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड या सरकार की भूमिका को 'क्लीनचिट' नहीं दे रहे, पर क्या हमारा राजनीतिक वर्ग ऐसी मौतों को लेकर वाकई संवेदनशील है? कहीं कोई हादसा होता है, जिस पार्टी की सरकार होती है, उसे कोसने समूची विरोधी पार्टियां जमा हो जाती हैं। दिल्ली में कांग्रेस कोसती है, बेंगलुरु में भाजपा, मुंबई में शिव सेना, तो लखनऊ में सपा। सवाल यह है कि इस सबसे कोई फर्क पड़ता भी है? दुर्योग से इसका उत्तर 'नहीं' है। फिर निदान क्या है? सबसे बड़ा समाधान तो यही है कि वाहन चलाते समय अपनी जान के प्रति खुद की जिम्मेदारी का परिचय दें। आप किसी भी सड़क पर निकल जाइए, आपको ऐसे अनेक लोग मिल जाएंगे, जो न सिर्फ बेहद लापरवाही से गाड़ी चला रहे होते हैं, बल्कि कई तो गैर-कानूनी रूप से वाहन ड्राइव करते हैं। वहां किसी नगर निगम या सरकार की गलती नहीं होती, वहां सरासर परवरिश और मां-बाप की गलती होती है।

सरकार ने तो कानून बना रखा है कि एक तय उम्र से कम आयु के बच्चों का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, फिर कैसे छोटे-छोटे बच्चे गलियों में स्कूटी से धूल उड़ाते फिरते हैं या रईसजादे फुटपाथों पर लोगों को कुचलते घूमते हैं? हर बात के लिए सरकार को दोष देना अपने नागरिक दायित्व से बचने का सबसे आसान रास्ता है और हमारे देश में बहुत सारी समस्याओं में मूल में यही प्रवृत्ति है। विडंबना यह है कि हमारे देश में न अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होती है और न नागरिकों की।

हमारे पास एक ढीला-ढाला न्यायिक ढांचा है, जो इतने सारे अंतरविरोधों का शिकार है कि समाज और देश को उससे कोई दिशा ही नहीं मिल पा रही। आप गांठ बांध लीजिए, कमल की दर्दनाक मौत आखिरी नहीं होने जा रही है। आपको चंद रोज के भीतर ही ऐसी खबरें फिर पढ़ने-देखने को मिलेंगी। 'सिविक सेंस' के बिना सिविल सोसायटी की अवधारणा ही बेमानी है।

मिहिर राणा, टिप्पणीकार

रफ्तार के दुश्मनों को पहचानें

एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक आंकड़े के अनुसार, दुनिया के 90 फीसदी वाहन चालक अपना ड्राइविंग स्किल दूसरों से बेहतर मानते हैं। शायद यही कारण है कि सड़क दुर्घटनाओं में अति-आत्मविश्वास बड़ी भूमिका निभाता पाया गया है। यह आलेख उन अदृश्य दुश्मनों से आपको अवगत करा रहा है, जो इन दिनों सड़क पर हमारे सुकून और सुरक्षा, दोनों में सेंध लगाने का काम करते हैं। बता रहे हैं निशित पाठक

अगर आपके पास एक एसयूवी या कॉम्पैक्ट एसयूवी है, तो किसी शानदार एक्सप्रेस-वे की चौड़ी सड़कों पर पहुंचते ही कार की गति सीमा परखने की आपको तीव्र इच्छा जरूर होती होगी। हालांकि, आगाह कर दें कि विशेषज्ञों के अनुसार, गति में हर एक प्रतिशत की बढ़ोतरी से घातक दुर्घटना का खतरा करीब 4 फीसदी तक बढ़ जाता है। यहां सवाल केवल रफ्तार का ही नहीं है। यह भी है कि आपके चैन के सफर में रफ्तार का दुश्मन कौन है और हम उसे पहचान क्यों नहीं पाते? आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ कारणों के बारे में....

तकनीक पर ज्यादा भरोसा

आज के वाहन सिर्फ मशीन नहीं रहे। बड़े टच-स्क्रीन, डिजिटल मीटर, इंफोटेनमेंट सिस्टम, वॉयस असिस्ट, नेविगेशन डिस्प्ले और क्रूज कंट्रोल जैसे ड्राइविंग असिस्टेंट फीचर ड्राइवर को यह भ्रम देने लगे हैं कि अब सब कुछ वह संभाल लेंगे। यहीं से रफ्तार का पहला दुश्मन पैदा होता है, यानी टेक्नीक पर जरूरत से ज्यादा भरोसा।

दरअसल, जब ड्राइवर की नजर सड़क की बजाय स्क्रीन पर चली जाती है, तो तेज रफ्तार में प्रतिक्रिया का समय कम हो जाता है। मान लीजिए एसी या वॉल्यूम बदलना हो तो टचस्क्रीन में इसके लिए मेनू खोलकर बार-बार स्क्रीन देखनी पड़ती है। वहीं, भौतिक बटन, जैसे एसी का नॉब या वॉल्यूम बटन, हाथ से दबाते ही 'क्लिक' का एहसास दे देते हैं, जिससे बिना सड़क से नजर हटाए काम हो जाता है। इसी फर्क की वजह से टचस्क्रीन ड्राइविंग के दौरान ध्यान ज्यादा भटकाती है और जोखिम बढ़ाती है।

ऐसे में कार में मौजूद वॉयस कमांड फीचर का उपयोग करना उचित होगा। अगर यह फीचर नहीं है, तो ट्रैफिक रेड लाइट पर प्रतीक्षा के दौरान इसे करना सही होगा। ऐसा तुरंत करना जरूरी हो, तो कार की रफ्तार को धीमा जरूर कर लें।

अति-आत्मविश्वास

प्यू के एक शोध की बात करें, तो जो ड्राइवर खुद को बहुत अनुभवी मानते हैं, उनमें मल्टीटास्किंग, जैसे फोन का इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति दोगुना अधिक होती है। उन्हें लगता है कि उनका नियंत्रण इतना जबर्दस्त है कि वे एक हाथ से फोन और दूसरे हाथ से गाड़ी चला सकते हैं।

जबकि डाटा कहता है कि इससे दुर्घटना का खतरा 400% बढ़ जाता है। बढ़ा हुआ आत्मविश्वास अकसर ओवरस्पीडिंग, गलत लेन से ओवरटेकिंग और नियमों को हल्के में लेने जैसी आदतों को जन्म देता है, जो तेज रफ्तार के साथ मिलकर जानलेवा साबित हो सकती हैं। कई अनुभवी ड्राइवर यह मान लेते हैं कि उन्हें नियमों की जरूरत नहीं, क्योंकि वे सब संभाल सकते हैं। यही सोच तेज रफ्तार के साथ मिलकर घातक साबित होती है।

वहीं, कोहरा, बारिश या धूल भरे मौसम में कम दृश्यता के बावजूद तेज चलना भी उतना ही खतरनाक है। कई चालक मान लेते हैं कि सड़क की स्थिति पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही गलत अनुमान बड़े हादसों की वजह बनता है।

जल्दबाजी की मानसिकता

रफ्तार का दूसरा बड़ा दुश्मन सड़क पर नहीं, हमारे दिमाग में पैदा होता है। देर हो जाने का डर, समय पर पहुंचने का दबाव, हड़बड़ी और जल्दबाजी वाली सोच चालक को अनजाने में तेज वाहन चलाने पर मजबूर कर देती है। ध्यान रखें कि यदि आप 60 किमी/घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, तो अचानक ब्रेक मारने पर गाड़ी रुकने से पहले करीब 35-40 मीटर दूर तक जा सकती है। यह 'रिएक्शन गैप' खतरनाक साबित होता है। यह मानसिक जल्दबाजी खासकर शहरों में अधिक देखी जा रही है, जहां ट्रैफिक से बचने के लिए अचानक तेज चलने की कोशिश हादसों को जन्म देती है।

71%

के लगभग जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं का कारण रहा तेज गति में वाहन चालन बीते सालों में। अति-आत्मविश्वास की इसमें अहम भूमिका पायी गई।

- **ड्राइविंग सीखने के 6 से 18 माह के दौरान सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाओं से सामना होता है, एक अध्ययन के अनुसार।**
- **अमेरिका के एक अध्ययन में पाया गया कि टचस्क्रीन वाली कारों के चालकों ने अचानक कोई भी प्रतिक्रिया देने में 30 फीसदी ज्यादा समय लिया।**

फोन के साथ ड्राइविंग

गाड़ी चलाते समय फोन डायल करने से दुर्घटना का खतरा लगभग 8 गुना बढ़ जाता है। टेक्स्ट पढ़ते हुए कुछ सेकंड की लापरवाही में गाड़ी काफी दूरी तय कर लेती है। ड्राइवर की प्रतिक्रिया देने तक हादसे का जोखिम और बढ़ जाता है।

एक्सपर्ट की राय...

कई मामलों में देखा गया है कि हादसा एक पल की असावधानी से होता है। उदाहरण के तौर पर, हाल ही में एक घटना में ड्राइवर ने चलते वाहन में म्यूजिक सिस्टम सेट करने के लिए नजर हटाई और कुछ ही सेकंड में आगे चल रहे वाहन से टक्कर हो गई। जांच में रफ्तार के साथ प्रतिक्रिया का समय खत्म होना कारण बना। आज की ड्राइविंग में खतरा यह है कि ड्राइवर एक साथ कई काम करने लगता है, जबकि सड़क पूरे ध्यान की मांग करती है। वाहन इतने तकनीक-समृद्ध हो गए हैं कि चालक का ध्यान कहीं न कहीं बंटा रहता है। नेविगेशन स्क्रीन देखना, म्यूजिक बदलना, सनरूफ या कार के दूसरे फीचर्स पर ध्यान देना, ये सब काम छोटे लगते हैं, लेकिन तेज रफ्तार पर यही चूक बड़ा हादसा बन सकती है।

क्या करें : सड़क सुरक्षा केवल नियमों से नहीं आएगी, बल्कि ड्राइवर की सोच बदलने से आएगी। वाहन कितना तेज चल सकता है, की बजाय किस हालात में कितना तेज चलना सुरक्षित है यह समझना जरूरी है। रफ्तार तभी सुरक्षित है, जब ड्राइवर का ध्यान पूरी तरह सड़क पर हो, न कि अन्य सुविधाओं में उलझा हो।

-डॉ. अनिल वर्मा, सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ और ट्रैफिक बिहेवियर एनालिस्ट

सड़क की जानकारी न होना

भारत की कई सड़कें तेज रफ्तार के लिए बनी ही नहीं हैं। अचानक मोड़, अधूरी लेन, खराब रोशनी और बिना संकेत वाले कट तेज गति के साथ मिलकर खतरा बढ़ा देते हैं। सड़क चौड़ी होना सुरक्षित तेज रफ्तार की गारंटी नहीं है, क्योंकि असल सीमा सड़क की बनावट और ट्रैफिक तय करता है। कई लोग हाईवे की रफ्तार शहर में भी अपनाते हैं, जहां पैदल यात्री और दोपहिया वाहन अचानक सामने आ सकते हैं।

वाहनों की शानदार क्षमताएं

आधुनिक वाहन पहले से कहीं ज्यादा तेज पिक-अप, ऊंची टॉप -स्पीड और स्मूद ड्राइविंग का अनुभव देकर चालक को यह अहसास दिलाते हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है। अध्ययन बताते हैं कि इस तरह इंसान की प्रतिक्रिया क्षमता सीमित रहती है और सजगता कम हो जाती है। तेज गति पर अचानक ब्रेक लगाना भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाता है।

निजी कारण भी

तनाव और नींद की कमी से उपजी थकान ड्राइवर की प्रतिक्रिया क्षमता को काफी हद तक कम कर देती है। तेज रफ्तार पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को सिर्फ देखना ही नहीं, बल्कि दिमाग से तुरंत फैसला भी लेना होता है। कई बार चालक सड़क देख रहा होता है, लेकिन उसका दिमाग हालात को समय पर समझ नहीं पाता। यही कारण है कि लंबी दूरी की ड्राइव और देर रात तेज गति से गाड़ी चलाना सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है।

सोशल मीडिया का उपयोग

ड्राइविंग के दौरान सोशल मीडिया इस्तेमाल करना यानी लाइव स्ट्रीमिंग, रील बनाना, स्टंट करने को लेकर तेज स्पीड में कार चलाना नए वक्त के रफ्तार के दुश्मन साबित हो रहे हैं। एक अध्ययन कहता है कि ड्राइविंग के दौरान टेक्स्ट करना शराब पीकर गाड़ी चलाने से 6 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। इस तरह प्रतिक्रिया का समय 35 से 40 फीसदी बढ़ जाता है।

बड़ी बैटरी वाला नया स्मार्टफोन

गैजेट

स्मार्टफोन खरीदारों के लिए रेडमी और रियलमी के नए फोन बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इनमें दमदार बैटरी, 5जी कनेक्टिविटी और नए फीचर्स मिलेंगे। कीमत और छूट को अलग-अलग यूजर्स की जरूरतों के हिसाब से रखा गया है।

रिअलमी पी 4पावर 5जी

बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहते हैं, तो रिअलमी पी 4पावर से बेहतर विकल्प नहीं है। फोन की सबसे बड़ी खासियत ही 10,001 एमएएच (मिलीएम्पियर-आवर) की बैटरी है।

स्टोरेज और कीमत

8 जीबी रैम और 128 जीबी वेरिएंट लगभग 25,999 रुपये और 8 जीबी रैम के साथ 256 जीबी वेरिएंट की कीमत लगभग 27,999 रुपये है। टॉप-एंड वेरिएंट 12जीबी रैम और 256जीबी स्टोरेज के साथ 30,999 रुपये में आएगा। इन्हें ई-कॉमर्स मंच, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं।

फीचर्स में क्या खास

10,001 एमएएच की दमदार बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर लंबे समय तक चलती है। 80वाट फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग की भी सुविधा है, यानी जरूरत पड़ने पर यह दूसरे डिवाइस भी चार्ज कर सकता है। खास बात यह है कि बड़ी बैटरी के बावजूद फोन बहुत भारी नहीं लगता और रोजमर्रा के इस्तेमाल में आरामदायक है।

डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और डिजाइन

फोन में बड़ी और स्मूद एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जिसमें हाई रिफ्रेश रेट है, जिससे स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने का अनुभव बेहतर होता है। इसमें 5जी प्रोसेसर, अच्छा कैमरा सेटअप और वॉटर-डस्ट रेजिस्टेंट बॉडी भी है। यह ट्रांस सिल्वर, ट्रांस ऑरेंज और ट्रांस ब्लू तीन रंगों में उपलब्ध है।

रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज

शाओमी की हाल ही में पेश हुई रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज बिक्री के लिए उपलब्ध है। सीरीज में रेडमी नोट 15 प्रो और नोट 15 प्रो+ शामिल हैं।

डिस्प्ले और परफॉर्मेंस

दोनों फोन में 6.83-इंच की बड़ी और साफ स्क्रीन मिलती है, जो धूप में भी आसानी से देखी जा सकती है और मजबूत ग्लास से सुरक्षित भी है। परफॉर्मेंस के लिए नोट 15 प्रो में मीडियाटेक प्रोसेसर है, जबकि नोट 15 प्रो+ में स्नैपड्रैगन चिप दी गई है, जो मल्टीटास्किंग के लिए बढ़िया है।

कैमरा और बैटरी

दोनों फोन में 200 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा है और 6,500 एमएएच की बैटरी है। नोट 15 प्रो 45 वाट चार्जिंग के साथ आता है, जबकि प्रो+ में 100 वाट फास्ट चार्जिंग है। इन -डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसे अन्य फीचर्स भी दिए गए हैं।

कीमत और रंग विकल्प

नोट 15 प्रो 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपये है। यह ब्लैक, ग्लेशियर ब्लू, टाइटेनियम और मिस्ट पर्पल रंगों में मिलेगा। नोट 15 प्रो+ 8 जीबी रैम/256 जीबी से लेकर 12 जीबी रैम/512 जीबी वेरिएंट में उपलब्ध है, कीमत 37,999 से 43,999 रुपये तक है। यह ब्लैक, मोचा ब्राउन व ग्लेशियर ब्लू रंगों में उपलब्ध है।

इस महीने कुछ कारों का रहेगा इंतजार

कार बाजार

भारतीय ऑटो बाजार में कुछ नई गाड़ियों के मॉडल पेश होने की तैयारी है, जिनमें बजट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक के वाहन शामिल हैं। इन मॉडल्स में डिजाइन और टेक्नोलॉजी के मामले में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो कार खरीदारों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है।

निसान ग्रेवाइट

यह एक कॉम्पैक्ट 7-सीटर एमपीवी है, जो रेनो ट्राइबर के प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। स्टाइलिश डिजाइन के साथ उन्नत और उपयोगी फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इंजन के तौर पर 1.0 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो पेट्रोल विकल्प मिलेंगे, जो मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स के साथ आएंगे।

कीमत 5.76 लाख रुपये के लगभग से शुरु हो सकती है।

निसान टेक्टन

निसान की टेक्टन मिडसाइज एसयूवी भी इस सूची में शामिल है। यह इंडिया-स्पेक रेनो डस्टर के प्लेटफॉर्म पर बनी है, लेकिन डिजाइन मजबूत और आकर्षक है। अंदर बड़ी स्क्रीन, डिजिटल मीटर, पैनोरमिक सनरूफ और एडवांस सुरक्षा सिस्टम जैसी सुविधाएं टेक्टन को आरामदायक और हाई-टेक बनाती हैं।

कीमत 15-25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) संभावित कीमत।

कुछ फेसलिफ्ट भी आएंगे

फरवरी-मार्च 2026 के बीच स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट, एमजी हेक्टर और हेक्टर प्लस फेसलिफ्ट और टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट के लॉन्च होने की संभावना है। इसके अलावा, अप्रैल-मई 2026 में मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट भी आ सकती है। सभी में नए डिजाइन, बेहतर फीचर्स और बड़े स्क्रीन मिलने की संभावना है। कीमतें मॉडल के अनुसार लगभग 6.8 लाख से 19.5 लाख रुपये तक जा सकती हैं।

मारुति सुजुकी ई-विटारा

यह नेक्सा डीलरशिप के जरिए उपलब्ध होगी और 49 केडब्ल्यूएच और 61केडब्ल्यूएच बैटरी विकल्प के साथ आएगी। एक बार चार्ज करने पर यह लगभग 543 किलोमीटर तक चल सकती है। यह फीचर्स से भरपूर है और हार्टटेक-ई प्लेटफॉर्म पर बनी है, यानी इसे इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए मजबूत और हल्का बनाया गया है।

कीमत 15-25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रहने की उम्मीद है।

महंगी कारें भी कतार में

हाल ही में फॉक्सवैगन ने इंडिया-स्पेक टायरॉन पेश की है, जिसे भारत में बनाया जा रहा है। इसका फुली-लोडेड आर - लाइन वैरिएंट प्रीमियम और स्पोर्टी है, जिसमें उन्नत तकनीक और नया डिजाइन है। यह ऑल-व्हील ड्राइव के साथ आता है, 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन तथा 7-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से चलता है। अनुमानित कीमत 45-50 लाख रुपये लगभग के बीच हो सकती है।

बीएमडब्ल्यू एक्स3 30एम

बीएमडब्ल्यू एक्स 3 30 एक्स ड्राइव एम स्पोर्ट प्रो भारत में 16 फरवरी, 2026 को लॉन्च की जाएगी। इसमें 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो बेहतर पावर देता है और माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक से लैस है। सामान्य मॉडल के मुकाबले इसमें अलग और आकर्षक डिजाइन के साथ नया ग्रे शेड मिलेगा। इस कार की कीमत अनुमानित रूप से 75-87 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

फीचर डेस्क

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। धैर्य रखें। कारोबार में वृद्धि होगी। कारोबार के लिए विदेश जाने के अवसर मिल सकते हैं। यात्रा से लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

वृष : मन प्रसन्न रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। किसी मित्र का सहयोग भी मिल सकता है। लाभ में वृद्धि होगी। कारोबार के लिए यात्रा से लाभ के अवसर मिलेंगे।

मिथुन : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, परंतु सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। भागदौड़ अधिक रहेगी।

कर्क : मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। अत्यधिक क्रोध से बचें। माता की सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा। रहन-सहन कष्टमय हो सकता है।

सिंह : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान हो सकता है। धैर्यशीलता बनाए रखें। मानसिक शांति बनाए रखने के प्रयास करें। परिवार की सेहत का ध्यान रखें।

कन्या : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। वाहन के रखरखाव तथा वस्त्रों आदि पर खर्च बढ़ सकते हैं।

तुला : आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान भी हो सकता है। कारोबार के लिए किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें।

वृश्चिक : मन परेशान हो सकता है। संतान की सेहत का ध्यान रखें। भागदौड़ अधिक रहेगी। कारोबार में भी कठिनाइयां आ सकती हैं। परिवार का साथ मिलेगा।

धनु : पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। सेहत पर ध्यान दें। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। बातचीत में संतुलित रहें।

मकर : मन परेशान रहेगा। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। कारोबार के विस्तार के लिए पिता से धन मिल सकता है। संपत्ति से आय के साधन बन सकते हैं।

कुंभ : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। संयत रहें। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। माता का साथ मिलेगा। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी।

मीन : आत्मविश्वास से तो भरपूर रहेंगे, परंतु कारोबार के लिए परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाना हो सकता है। किसी संपत्ति से धन की प्राप्ति भी हो सकती है।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

07 फरवरी, शनिवार, **शक संवत्:** 18, माघ (सौर) 1947, **पंजाब पंचांग:** 25, माघ मास प्रविष्टे 2082 **इस्लाम:** 18, शब्बान, 1447, **विक्रमी संवत्:** फाल्गुन कृष्ण षष्ठी तिथि रात्रि 02.55 मिनट तक पश्चात सप्तमी तिथि, चित्रा नक्षत्र रात्रि 02.29 मिनट तक पश्चात स्वाती नक्षत्र, शूल योग रात्रि 11.41 मिनट तक पश्चात गण्ड योग। चंद्रमा कन्या राशि में दोपहर 01.32 मिनट तक उपरांत तुला राशि। **सूर्य उत्तरायण।** शिशिर ऋतु। प्रात: 09 बजे से प्रात: 10.30 मिनट तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 02.55 मिनट से।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

कृपया हमें जीवन में बेहतरी के लिए किए जाने वाले कुछ छोटे-छोटे और आसान से उपाय बताएं। - मंदार, रांची

- लगभग 43 दिन के अंदर अपने बाल कटवा लेना ठीक रहता है।
- किसी सफाई कर्मचारी को शनिवार के दिन कुछ पैसे देना शुभ रहता है।
- कोशिश करें कि चंदन या कपूर के साबुन से स्नान करें।
- शनिवार को घर के बाहर किसी कैक्टस के पौधे में स्टील के बर्तन से पानी देना और शनिवार को किसी अस्पताल की कैंटीन में जाकर चाय पीना अच्छा रहता है।
- यदि यात्रा में हैं, तो कभी भी शाम को किसी बड़े पेड़ के नीचे लघुशंका न करें।

वर्ग पहेली : 8233

■	1	■	2	3		4		5
6			■		■		■	
■		■	7		■	8		
9		■		■	10	■	■	
	■	11					■	
	■	■		■		■	12	
13		14	■	15		■		■
	■		■		■	16		
17						■		■

बाएं से दाएं
2. आरामतलब; आलसी; निकम्मा; सुख चाहने वाला (6)
6. अंतर मिटना; साथ लगना; सटना; सम्मिलित होना; भेंट होना (3)
7. माता; पराजय; हार (2)
8. उमंग; हिलोर; तरंग; मौज (3)
9. विष; बिच्छू का डंक (2)
11. जिसमें कमानी हो; नवचंद्राकार (5)
12. अनुभव करना; जान लेना; खोज निकालना; प्राप्त करना; मिलना (2)
13. व्यवसायी; व्यापारी; वैश्य (3)
15. आठ पहर का समय; चौबीस घंटे का समय; दिवस; वार (2)
16. कल्याण; भलाई; सप्ताह का एक दिन; वार; एक ग्रह (3)
17. नरक में जाना; नरक में रहना (3,3)

ऊपर से नीचे
1. जल और स्थल; संपूर्ण धरातल (2,2)
3. आराम; चैन; सुख; करार (3)
4. पत्ते से बनी थाली (3)
5. एकता भंग करना; फूट डालना (3,3)
7. माल से भरपूर; धनी; संपन्न (4)
9. नया; प्रशिक्षु; जिसे अनुभव न हो (6)
10. अक्ल का तेज न होना; नासमझी (4)
12. जो पार हो चुका हो; पूर्ण पंडित; ज्ञानी (4)
14. कंचन; स्वर्ण; धतूरा (3)
15. बुद्धि; मस्तिष्क; समझ; भेजा (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8232

1 जं	■	2 सा	■	3 नि	4 क	ट	त	5 म
6 ग	टा	ग	ट	■	रा	■	■	र
ल	■	र	■	7 ग	ह	रा	हो	ना
■	8 म	त	ग	ण	ना	■	■	स
9 ल	■	ट	■	ना	■	10 प	■	न्न
त	■	■	11 जा	य	के	दा	र	■
12 ल	ज्जा	ज	न	क	■	थि	■	13 त
ग	■	■	व	■	14 पु	का	र	ना
15 ना	म	क	र	ण	■	री	■	व

सुडोकू : 8215

*आसान

	2					3		5
9			6				7	
			1	5				
6	9		8	3				2
		4				7		
8				4	1		5	9
				9	6			
	8				2			1
7		5					9	

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8214

9	3	5	8	1	6	2	7	4
2	8	1	9	7	4	6	5	3
7	4	6	2	5	3	1	8	9
3	9	2	4	6	8	5	1	7
5	1	4	3	2	7	8	9	6
8	6	7	1	9	5	3	4	2
4	2	9	6	8	1	7	3	5
1	7	3	5	4	2	9	6	8
6	5	8	7	3	9	4	2	1

संपादकीय जागरण

शनिवार, 7 फरवरी, 2026 : फाल्गुन कृष्ण - 6 वि. 2082

क्रोध का आरंभ मूर्खता से और अंत पश्चाताप पर होता है

गड्ढों में गिरी व्यवस्था

नोएडा में एक कार सवार इंजीनियर की गड्ढे में गिरने से मौत का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि दिल्ली में भी एक बाइक सवार युवक की गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। यह गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड की ओर से खोदा गया था। नोएडा की तरह दिल्ली के इस गड्ढे के पास भी न तो कोई बैरीकेडिंग थी और न ही किसी तरह का चेतावनी बोर्ड। इसका मतलब है कि नोएडा की घटना के बाद भी उससे सटी दिल्ली में कोई सबक नहीं सीखा गया। दिल्ली की घटना पर नोएडा की तरह कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कुछ भी किया जाए, काल के गाल में समा गए युवक की जिंदगी लौटने वाली नहीं। इस युवक की मौत को हादसा कहना घटना की गंभीरता को कम करना होगा। यह हादसा नहीं, एक हत्यारी लापरवाही है। नोएडा और दिल्ली जैसी घटनाएं अपवाद नहीं हैं। अपने देश में ऐसी घटनाएं रह-रहकर घटती ही रहती हैं। लोग सड़क किनारे खोदे गए गड्ढों या फिर टूटी सड़कों में गिरकर मरते ही रहते हैं। बहुत सी जानलेवा घटनाएं इसलिए होती हैं कि जोखिम भरे स्थान अंधेरे में डूबे होते हैं और वहां लोगों को सावधान करने वाले कोई संकेत भी नहीं होते। जब देश की राजधानी और उससे लगे क्षेत्रों में यह हाल है, तब फिर दूर-दराज के शहरों में कितनी चौकसी बरती जाती होगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है।

बड़े शहरों में तो व्यवस्था के नाकारापन और संवेदनहीनता से होने वाली मौतें फिर भी चर्चा में आ जाती हैं और दिखावटी ही सही, कोई कार्रवाई भी हो जाती है, लेकिन छोटे शहरों में किसी के कान पर जूं भी नहीं रेंगती। अपने यहां सड़क, बिजली, पानी उपलब्ध कराने और मार्ग प्रकाश, यातायात आदि की देखभाल करने वाली एजेंसियों की लापरवाही के कारण प्रति वर्ष न जाने कितने लोग जान गंवाते हैं। आम तौर पर ऐसी मौतों को दुर्घटना करार दिया जाता है और जो लोग अपने स्वजन खोते हैं, वे उसे विधि का विधान मान लेते हैं, लेकिन सच यह है कि नोएडा और दिल्ली सरीखी जानलेवा घटनाएं इसलिए होती रहती हैं, क्योंकि लोगों की मौतों के लिए जवाबदेह कर्मचारी और अधिकारी कभी कठोर दंड के भागीदार नहीं बनते। वे अधिक से अधिक निलंबित होते हैं। सब जानते हैं कि निलंबन कोई सजा नहीं होती और बर्खास्तगी जैसी कठोर कार्रवाई कठिनाई से ही होती है। जिम्मेदार विभागों पर भारी भरकम जुर्माना भी नहीं लगाया जाता। इसी कारण कोई चेतता नहीं। नतीजा यह है कि घटिया, बेतरतीब और समय खपाऊ निर्माण होता रहता है, जो प्रायः जोखिम को निमंत्रण देता है। यह शर्मनाक स्थिति केवल विकसित भारत के नारे को मुंह ही नहीं चिढ़ाती, बल्कि शासन-प्रशासन के गड्ढों में धंसे होने को भी बयान करती है।

उचित कदम

राजधानी में परिवहन व्यवस्था को एकीकृत करने के उद्देश्य से दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट अथारिटी (डुमटा) के गठन की दिशा में दिल्ली सरकार का आगे बढ़ना सर्वथा उचित है। सरकार ने इसके लिए विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को डुमटा संबंधी विधेयक तैयार करने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स के साथ बैठक कर उसे इसका मसौदा जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। इस विधेयक का मसौदा तैयार करने का काम शुरू करने के साथ ही सरकार ने दिल्ली अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड (डीयूटीएफ) के गठन के लिए मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

> दिल्ली की सड़कों पर वाहनों के दबाव को देखते हुए परिवहन व्यवस्था को समग्र रूप से देखकर विकल्प तलाशे जाएं

दिल्ली में जिस तरह वाहनों का दबाव बढ़ रहा है, ये आवश्यक है कि यहां समूची परिवहन व्यवस्था को समग्र रूप से देखा जाए और उसी अनुरूप उसे विकसित करने की दिशा में काम किया जाए। वर्तमान में राजधानी में जहां परिवहन के मौजूदा साधनों को विकसित किए जाने की आवश्यकता है, वहीं नए विकल्पों को तलाशने की भी जरूरत है। ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि डुमटा का गठन होने पर वह इस दिशा में भी काम करेगा। वहीं, परिवहन आवश्यकताओं को देखते हुए विभिन्न योजनाओं के लिए एक समर्पित वित्तीय तंत्र के रूप में प्रस्तावित डीयूटीएफ से उसे अपेक्षित सहयोग मिलेगा।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या भारत टैक्सी पहले से स्थापित टैक्सी सेवाओं को चुनौती देने में सक्षम होगी?

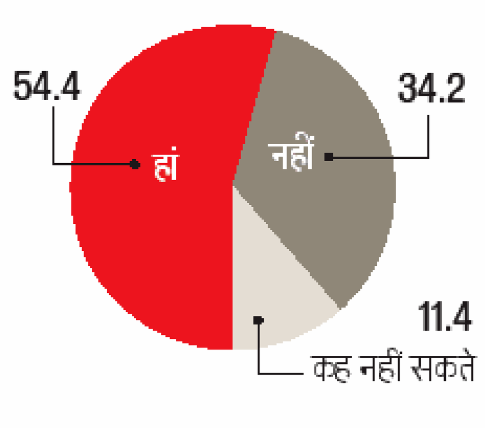

आज का सवाल

क्या सेवारत आइएएस या आइएफएस को सिविल सेवा की परीक्षा में बैठने से रोकने का फैसला सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

जवाबदेही के दायरे में आएं टेक कंपनियां

राजीव शुक्ला

डिजिटल मीडिया का दुरुपयोग आज एक महामारी की तरह फैल चुका है

सुबह की पहली किरण के साथ जब हम अपने स्मार्टफोन का स्क्रीन अनलाक करते हैं, तो हम केवल एक उपकरण नहीं खोलते, बल्कि एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं, जो कभी सोती नहीं है। यह डिजिटल दुनिया जितनी चमकदार है, उतनी ही बेरहम भी। आज हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल मीडिया के गलियारों में बीत रहा है। हमारी पहचान, रिश्ते और समाज में प्रतिष्ठा अब हमारे पदचिह्नों यानी डिजिटल फुटप्रिंट्स से तय होती है, पर समस्या तब शुरू होती है जब ये पदचिह्न हमारी वर्तमान पहचान के लिए बोझ बन जाते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे युवक की, जिस पर दस साल पहले एक छोटा आरोप लगा था। अदालत ने उसे ससम्मान बरी कर दिया, लेकिन आज जब कोई कंपनी उसे नौकरी देने के लिए उसका नाम गूगल करती है, तो सबसे ऊपर वही पुरानी गिरफ्तारी की खबर चमकती है। यही वह बिंदु है जहां राइट टू बी फारगाटेन यानी भुला दिए जाने का अधिकार एक विलासिता नहीं, बल्कि जीने के अधिकार का हिस्सा बन जाता है।

डिजिटल मीडिया का दुरुपयोग आज एक महामारी की तरह फैल चुका है। फेक न्यूज, ट्रोलिंग और साइबरबुलिंग ने वर्चुअल स्पेस को एक युद्ध का मैदान बना दिया है। सबसे भयावह रूप तब सामने आता है, जब किसी की निजी जानकारी या तस्वीरें उसकी मर्जी के बिना सार्वजनिक कर दी जाती हैं। इसे डाक्सिंग कहा जाता है। यह केवल तकनीक का गलत इस्तेमाल नहीं है, बल्कि यह एक इंसान की गरिमा पर सीधा हमला है। जब कोई अपमानजनक सामग्री एक बार वायरल हो जाती है, तो उसे पूरी तरह मिटाना लगभग असंभव हो जाता है। डिजिटल दुनिया में कुछ भी स्थायी रूप से मरता नहीं है, वह बस कहीं दबा रहता है और समय-समय पर बाहर आता रहता है।

यहीं पर राइट टू बी फारगाटेन की अवधारणा उम्मीद की किरण है। व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने पुराने, अप्रासंगिक या गलत डिजिटल रिकार्ड्स को हटवा सके। यूरोपीय संघ का एक कानून इस मामले में एक मिसाल है। वहां के एक चर्चित मामले में यह तय हुआ कि अगर कोई जानकारी अब जरूरी नहीं है, तो उसे सर्च रिजल्ट्स से हटाना होगा। भारत में भी इस अधिकार की सुगबुगाहट तेज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस में निजता को मौलिक अधिकार तो माना, लेकिन राइट टू बी फारगाटेन अभी भी एक कानूनी धुंध में फंसा हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल में माना कि एक व्यक्ति को अपनी पुरानी गलतियों या विवादों से आगे बढ़ने का हक है। सवाल यह है कि क्या हमारे पास इसके लिए कोई ठोस कानून है?

अवधेश राजपूत

भारत का डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 इस दिशा में एक कदम जरूर है। यह डाटा मिटाने का अधिकार देता है, लेकिन इसमें कई पेच हैं। जब कोई व्यक्ति अपना डाटा हटवाने की मांग करता है, तो उसके सामने अभिव्यक्ति की आजादी और न्यायिक पारदर्शिता की दीवार खड़ी हो जाती है। मिसाल के तौर पर, क्या एक भ्रष्ट नेता यह कह सकता है कि लोग उसके पुराने घोटाले भूल जाएं, क्योंकि अब वह सुधर गया है? निश्चित रूप से नहीं। जनता को जानने का अधिकार और सार्वजनिक हित हमेशा निजी निजता से ऊपर रहेगा, लेकिन एक सामान्य नागरिक, जो किसी झूठे मुकदमे या निजी विवाद का शिकार हुआ है, उसे अदालतों के चक्कर क्यों काटने पड़ें? हमारे वर्तमान कानून में एक ऐसी स्पष्ट प्रक्रिया की कमी है, जो टेक कंपनियों को जवाबदेह ठहरा सके।

इस जटिल समीकरण में अब एआइ ने प्रवेश किया है। एआइ के दुरुपयोग का सबसे वीभत्स रूप डीपफेक है। आज किसी भी आम इंसान का चेहरा किसी अश्लील वीडियो या भड़काऊ भाषण के साथ जोड़ना बच्चों का खेल बन गया है। एआइ एल्गोरिदम आज इतने शक्तिशाली हैं कि वे आपकी पसंद-नापसंद को भांप लेते हैं और आपको उसी दिशा में ले जाते हैं, जो वे चाहते हैं। नफरत भरे कंटेंट पर इंगेजमेंट ज्यादा आती है, इसलिए एल्गोरिदम उसे बढ़ावा देते हैं। यह एआइ का वह चेहरा है, जो समाज को बांट रहा है। इसी एआइ में समाधान भी छिपा है। अगर हम एआइ को सही नीयत के साथ इस्तेमाल करें, तो यह एक डिजिटल रक्षक बन सकता है। जिस रफ्तार से डिजिटल मीडिया पर डाटा अपलोड होता है, उसे इंसान कभी मानिटर नहीं कर सकते। यहां एआइ एक फिल्टर की तरह काम कर सकता है। यह आपत्तिजनक कंटेंट, डीपफेक और फेक न्यूज को उसके फैलने से पहले ही पहचान कर ब्लाक कर सकता है। राइट टू बी फारगाटेन को लागू करने में एआइ मददगार साबित हो सकता है। यह इंटरनेट के समंदर में से आपके उन निशानों को ढूंढ़कर मिटा सकता है, जिन्हें आप भुलाना चाहते हैं। जरूरत एक ऐसी नीति की है, जो टेक कंपनियों को बाध्य करे कि वे अपने एआइ माडल्स को सुरक्षा और निजता के अनुकूल बनाएं।

भारत को राइट टू बी फारगाटेन के लिए एक स्वतंत्र और सशक्त ढांचा तैयार करना होगा। यह केवल कागजी अधिकार न हो, एक ऐसी व्यवस्था हो, जहां एक क्लिक पर पीड़ित की सुनवाई हो। हमें विशेष डिजिटल ट्रिब्यूनल्स की जरूरत है जहां तकनीकी विशेषज्ञ और कानूनी जानकार मिलकर त्वरित फैसले लें। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को इतनी शक्ति मिलनी चाहिए कि वह उन प्लेटफार्म्स पर भारी जुर्माना लगा सके, जो आदेश मिलने के बाद भी डाटा नहीं हटाते। कानून में यह स्पष्ट करना होगा कि किन परिस्थितियों में डाटा हटाया जा सकता है और कहां सार्वजनिक हित सर्वोपरि होगा? एक और महत्वपूर्ण सुधार यह होना चाहिए कि टेक कंपनियों के लिए ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट अनिवार्य हो, ताकि पता चले कि उन्होंने कितने अनुरोध स्वीकार किए और कितने खारिज। हमें एक ऐसी डिजिटल संस्कृति विकसित करनी होगी, जहां हम दूसरों की निजता का सम्मान करें। कानून अपना काम करेगा, एआइ अपना सुधार करेगा, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति को एक दूसरा मौका मिलने का हक है। डिजिटल युग में विस्मृति का अधिकार दरअसल मानवीय गरिमा को बचाने की आखिरी कोशिश है। जब तक हम तकनीक और कानून को मानवीय संवेदनाओं के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम इस डिजिटल पिंजरे में कैद रहेंगे।

(लेखक कांग्रेस के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं)
response@jagran.com

जोर पकड़ता एक बच्चे का चलन

क्षमा शर्मा

एक बच्चे का चलन जिस तरह बढ़ रहा है, उससे भारत में भी कुछ समय बाद चीन जैसे नतीजे सामने आ सकते हैं

पिछले दिनों दिल्ली में महिलाओं पर किए गए एक सर्वे में बताया गया कि अब स्त्रियां 30 की उम्र के बाद ही संतान चाहती हैं। 2024 में किए गए एक अन्य सर्वे में पता चला था कि चार में से एक बच्चे को 30 से अधिक उम्र वाली महिला ने जन्म दिया। 30 से 35 वर्ष की माताओं की संख्या 2005 से 2024 तक 2.7 प्रतिशत से बढ़कर 8.9 प्रतिशत हो गई। 20 से 24 साल की उम्र में मां बनने वाली महिलाओं की संख्या 2024 में घटकर 27.1 प्रतिशत रह गई। लंबे समय तक माना जाता रहा है कि महिलाओं की मां बनने की उम्र 30 के बाद ठीक नहीं होती, लेकिन अब वक्त बदल गया है। स्त्रियां अब पढ़ना चाहती हैं। नौकरी करना चाहती हैं। तरक्की के लिए नौकरियां बदलती भी रहती हैं। अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी उनका ध्यान बढ़ा है। विवाह उनकी प्राथमिकता में नहीं रहा। यदि विवाह करती भी हैं, तो देर से। एक जमाने में यदि किसी लड़की की उम्र 30 के पार पहुंच जाती थी, तो मान लिया जाता था कि अब उसका विवाह नहीं होगा या कैसे होगा, क्योंकि इस उम्र तक तो लड़के ही कुंवारे नहीं बैठे रहते, लेकिन अब प्रायः लड़के-लड़कियों के विवाह 30 के बाद की उम्र में हो रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण बढ़ता शहरीकरण भी है। फिर विवाह के बाद ये लोग एकदम से बच्चे नहीं चाहते। पहले एक नई जीवनशैली में रचना-बसना चाहते हैं, फिर बच्चों के बारे में सोचते हैं।

इन दिनों मध्यवर्ग में एक बच्चे का चलन भी बढ़ा है। इसका कारण यह कि इन दिनों बच्चे पालना महंगा है। यदि माता-पिता दोनों भी कमाते हैं, तो बताया जाता है कि एक बच्चे की देखभाल, शिक्षा-दीक्षा में ही एक वेतन खर्च हो जाता है। एक बच्चे के बारे में पुरानी अवधारणा थी कि वह अपने को बहुत अकेला महसूस करता है। उसे जीवनभर साथीपन की कमी सालती है। अब यह भी नहीं रहा कि बेटी है, तो बेटा जरूर चाहिए। कुछ दिन पहले एक अखबार ने उन माता-पिता से बातचीत की थी, जिनके एक बेटा या एक बेटी है। उन अभिभावकों ने बताया था कि उनके एक बच्चे को कभी कोई समस्या नहीं हुई, बल्कि वे जीवन को जीना जल्दी सीख जाते हैं। अपना काम खुद करते हैं। अधिक अनुशासित होते हैं।

शादी एवं संतान को लेकर बदलता युवाओं का सोच • फाइल

अपने देश में उस पीढ़ी को अधिक समय नहीं बीता है, जब घर में पांच-छह भाई-बहन होना मामूली बात थी। घर में आय का साधन एकमात्र कमाने वाले पिता होते थे। सरकारी स्कूलों में पढ़कर भी बच्चे ठीक-ठाक नौकरी पा जाते थे। उनके विवाह भी 30 से पहले हो जाते थे। उन दिनों नौकरी करने वाली स्त्री का मतलब किसी आपदा की मारी कोई स्त्री ही होती थी। स्त्री की पढ़ाई का मतलब उसकी नौकरी या आत्मनिर्भरता नहीं, बल्कि यह माना जाता था कि अगर कहीं दूर-देश ब्याह दी जाए, तो कम से कम चिट्ठी-पत्री लिखकर अपना हाल-चाल तो दे सके। फिर एक ऐसा दौर भी आया जब देश में अल्ट्रासाउंड के जरिये गर्भ में ही लड़कियों को मारने वालों की बाढ़ आ गई। भ्रूण हत्या पर हालांकि सरकार ने रोक लगा रखी है, लेकिन अब भी यदा-कदा इसकी खबरें आती रहती हैं, लेकिन जैसे-जैसे लड़कियां पढ़ी-लिखीं, आगे बढ़ीं, उन्होंने अपने लिए बनाई गई छवियों को ध्वस्त कर दिया। 1975 में अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया, तब से अपने यहां स्त्रियों के मसले भी जोर-शोर से उठाए गए। उनकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर अधिक जोर दिया गया। विवाह और बच्चे पहली प्राथमिकता से बहुत पीछे चले गए। आज किसी साधन-संपन्न लड़की से पूछें या किसी गरीब से, सब इस बात पर एकमत हैं कि पहले वे पढ़ना चाहती हैं, नौकरी करना चाहती हैं, उसके बाद ही शादी आदि के बारे में सोचेंगी।

अब हम दो-हमारे दो जैसे नारे कहीं सुनाई नहीं देते। स्त्रियों के नजरिये से देखा जाए, तो यह ठीक मालूम पड़ता है कि एक बच्चा हो, लेकिन विश्व स्तर पर जो बातें दिखाई दे रही हैं, हो सकता है कि भारत को भी 50 साल बाद यही भुगतना पड़े। एक समय में चीन की जनसंख्या दुनिया भर में सबसे ज्यादा थी। वहां की सरकार ने एक बच्चा नीति को सख्ती से लागू किया। अब उसी चीन की हालत क्या है। वहां लगातार युवाओं की कमी हो रही है और वृद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस कारण वहां की सरकार युवाओं को तरह-तरह के प्रलोभन दे रही है। युवा डेटिंग पर जाएं, विवाह करें, बच्चे पैदा करें इसके लिए अधिक छुट्टियां और विशेष पैकेज दिए जा रहे हैं। मातृत्व अवकाश को बढ़ाया जा रहा है। पिताओं को भी छुट्टी दी जा रही है, मगर युवा विशेषकर स्त्रियां, बच्चे नहीं चाहतीं। वे सरकार के किसी प्रलोभन में नहीं फंस रहीं। यही हाल जापान का है। वहां भी कम बच्चे जन्म ले रहे हैं। यूरोप के बहुत से देशों में भी ऐसा है। रूस में सरकार ने घोषणा की थी कि जो स्त्री दस बच्चे पैदा करेगी, उसे मदर हीरोइन कहा जाएगा और दस लाख रूबल का पुरस्कार दिया जाएगा।

नेता कुछ भी कहते रहें, लोग उनकी बात नहीं मान रहे। खास तौर से स्त्रियां कह रही हैं कि वे कोई बच्चे पैदा करने की मशीन हैं! आखिर स्त्रियों के तमाम विमर्शों मे उन्हें इतना जागरूक तो कर ही दिया है कि वे बच्चों के जन्म और उनकी परवरिश के मुकाबले अपने सुख और खुशियों के बारे में पहले सोच रही हैं। विश्व और अपने देश में ऐसे दंपतियों की संख्या भी बढ़ रही है, जो बच्चे चाहते ही नहीं हैं।

(लेखिका साहित्यकार हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

व्यक्ति की शक्तियां

भारतीय परंपरा में दो प्रकार की शक्तियों का कथन किया गया है। एक है बाह्य शक्ति और दूसरी है अंतःशक्ति। बाह्य शक्ति में तन, मन और धन गिने जाते हैं। तन ईश्वर प्रदत्त होता है। इसलिए यह स्वस्थ और सुंदर होने के साथ अस्वस्थ और असुंदर भी हो सकता है। किंतु हम अपने सत्कर्मों से असुंदर को भी सुंदर बना सकते हैं। मन बहुत ही समर्थ होता है, किंतु इसकी प्रवृत्ति प्रतिकूल कार्यों की ओर ही सदा आकर्षित रहती है। इस पर निग्रह करने में वही समर्थ होता है, जो इसकी प्रार्थना करके इसे सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करता है। धन की प्राप्ति मनुष्य के भाग्य और श्रम पर निर्भर है। यहां यह जानना जरूरी है कि धन तभी व्यक्ति के उत्कर्ष में सहायक होता है, जब उसका स्वार्थ के साथ-साथ परमार्थ में भी प्रयोग होता हो। इस प्रकार जब व्यक्ति इन तीनों शक्तियों का पारमार्थिक प्रयोग करता है, तो वह प्रतिष्ठित पुरुष की श्रेणी में गिना जाता है।

इसी तरह दम, दया और दान को व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों में गिना जाता है। व्यक्ति दस इंद्रियों का समूह है। ये सभी इंद्रियां काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद जैसे त्याज्य दुर्गुणों के प्रति ही सदा आकर्षित रहती हैं। दम अंतःशक्ति को जागृत कर हम इन्हें इन दुर्गुणों की ओर जाने से रोक सकते हैं। इसी तरह जिस मनुष्य में करुणा का स्वभाव होता है और जो दया के भाव से दयालु होकर हर एक निराश्रित और अकिंचन की सहायता करता है, वह दया अंतःशक्ति वाला व्यक्ति होता है। दान एक ऐसी मानवीय प्रवृत्ति है, जो न केवल दानी व्यक्ति को इस लोक में सुखी और संपन्न बनाती है, अपितु परलोक में भी आनंदित करती है।

श्रीमद्भागवत पुराण में कहा गया है कि जो कोई धर्म के लिए, अर्थार्जन के लिए, कामनाओं की पूर्ति हेतु, यशवर्धन के लिए तथा अपने स्वजनों के लिए धन व्यय करता है, वह उभय लोक में सुख का भागी बनता है।

डा. गदाधर त्रिपाठी

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

संसद में अराजकता

''संसदीय मर्यादा की अनदेखी'' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय पढ़कर मन अत्यंत व्यथित, क्षुब्ध और आक्रोश से भर उठा। देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था-संसद में जो दृश्य हाल के दिनों में देखने को मिले हैं, वे किसी भी जागरूक नागरिक के लिए शर्मनाक और पीड़ादायक हैं। संसद, जो लोकतंत्र का मंदिर कही जाती है, आज वहां के कुछ जनप्रतिनिधियों के आचरण के कारण सड़कछाप अराजकता का मंच बनती जा रही है। जिन संसद सदस्यों से गरिमा, संयम और मर्यादा की अपेक्षा की जाती है, वही आज असभ्य की भांति व्यवहार करते दिखाई दे रहे हैं। यह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि लोकतंत्र के आत्मा पर सीधा प्रहार भी है। विपक्ष, जिसे लोकतंत्र का प्रहरी और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला स्तंभ माना जाता है, इस भूमिका में पूरी तरह विफल सिद्ध हुआ है। स्वस्थ आलोचना और तार्किक बहस के स्थान पर जिस प्रकार का असंयमित, अशोभनीय और उग्र व्यवहार प्रदर्शित किया गया, वह किसी पढ़े-लिखे, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की नहीं, बल्कि एक अशिक्षित और उन्मादी भीड़ की मानसिकता को दर्शाता है। कुछ राजनीतिक दल सकारात्मक राजनीति और रचनात्मक विमर्श के बजाय निम्नस्तरीय हंगामे और सस्ती लोकप्रियता के माध्यम से सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। यह अत्यंत निंदनीय और घोर आपत्तिजनक है। इस प्रकार की राजनीति न तो लोकतंत्र को मजबूत करती है और न ही जनता के विश्वास को बनाए रख सकती है। संसद हंगामे का अखाड़ा नहीं है, बल्कि गंभीर विचार-विमर्श का मंच है-यह बात सभी पक्षों को समझनी ही होगी।

बिमलेश कुमार सिंह चौहान, लखनऊ

शिक्षा का डिजिटलीकरण कितना सही

गाजियाबाद में मोबाइल गेम की लत से तीन सगी बहनों के नौवीं मंजिल से कूदकर जान देने की घटना के बाद हर अविभावकों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं और सभी को अंदर तक हिला कर रख दिया है। बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत और दुष्परिणाम को लेकर दैनिक जागरण ने पाठक पैनल शुरू किया है, जनहित और बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए अविभावकों में जागरूकता फैलाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। पाठक पैनल में भागीदारी करने वाली बहनों ने अपने-अपने उदगार व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना काल के बाद शिक्षा डिजिटल मोड़ पर आ गई है, लेकिन इसके दुष्परिणाम ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। शिक्षा का डिजिटल मोड़ बच्चों को शारीरिक और मानसिक तौर पर अच्छा करने के बजाय नुकसान ज्यादा पहुंचा रहा है, बच्चों में जिद्दीपन और चिड़चिड़ापन बहुत ही चरम सीमा पर बढ़ रहा है और हालात यह हो गए हैं कि स्कूल में भी बच्चों को होमवर्क से लेकर अन्य सभी सूचनाएं इंटरनेट मीडिया से ही सांझा की जा रही हैं, इस वजह से अविभावकों को मजबूरी में अपने बच्चों को मोबाइल देना पड़ रहा है। प्राईवेट स्कूलों में दाखिले के समय तीन-चार सौ रुपए तक की डायरी खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन डिजिटल दौर में उस डायरी का उपयोग ही नहीं किया जा रहा है।

मेघश्याम शर्मा, मोहन नगर पलवल

राष्ट्रहित सर्वोपरि

जब किसी राष्ट्र में राष्ट्रभक्ति केवल भावना नहीं, बल्कि संकल्प बन जाए, तब इतिहास की दिशा बदलने लगती है। भारत आज ऐसे ही एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है, जहां स्पष्ट सोच, मजबूत इरादे और निडर नेतृत्व की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देशहित में संघर्ष की बात केवल एक राजनीतिक वक्तव्य नहीं, बल्कि उस जिम्मेदारी और पीड़ा की अभिव्यक्ति है, जिसे राष्ट्र सेवा के मार्ग पर चलने वाला नेतृत्व ही अनुभव कर सकता है। आज भारत विकास की अभूतपूर्व यात्रा पर अग्रसर है। आधारभूत ढांचे के विस्तार से लेकर डिजिटल क्रांति तक, रक्षा क्षेत्र की मजबूती से लेकर वैश्विक मंचों पर भारत की सशक्त उपस्थिति तक, हर क्षेत्र में देश की स्थिति पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ हुई है। इतिहास साक्षी है कि जब कोई राष्ट्र आगे बढ़ता है, तब उसे रोकने के प्रयास भी तेज हो जाते हैं। कुछ शक्तियां बाहर से भारत की उभरती ताकत से असहज हैं, तो कुछ भीतर बैठकर विकास की गति को बाधित करने का प्रयास करती हैं। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में प्रधानमंत्री मोदी अकेले नहीं हैं। उनके पीछे 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास, समर्थन और संकल्प खड़ा है। वर्षों से लंबित निर्णयों को अमल में लाना, राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना और विश्व मंचों पर भारत की आवाज को मजबूती से रखना, ये सब उस नेतृत्व की पहचान बने हैं, जिसने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है।

सीपी शर्मा, रानी बाग, दिल्ली

X पोस्ट

वर्तमान में जातीय उग्रता बहुत कुछ संचार माध्यमों की भी देन है। इंटरनेट मीडिया पर उग्र जातिवादी भावना को व्यक्त होने देने में एकांत और कुटिल एल्गोरिदम भी सहायक है।

सुशांत झा @jhasushant

पीएम मोदी ने छात्रों से परीक्षा पे चर्चा की। एक चर्चा उनको छात्रों के इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल पर भी करनी चाहिए। यह आज बच्चों के सामने सबसे बड़ा खतरा है। चर्चा के बाद एक सीमा तय हो कि 16 या 18 साल के बाद ही बच्चों का एक्सपोजर इंटरनेट मीडिया पर हो।

सुकेश रंजन @RanjanSukesh

अमेरिका-भारत व्यापार समझौता रणनीतिक मेल-मिलाप से अधिक एक सामरिक युद्धविराम जैसा प्रतीत होता है। भारत के खिलाफ ट्रंप के छह महीने लंबे व्यापार युद्ध और कई अपमानजनक टिप्पणियों-जिनमें भारतीय अर्थव्यवस्था को 'मृत' बताना भी शामिल है, के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि यह समझौता द्विपक्षीय संबंधों को वास्तव में पुनर्जीवित कर पाएगा।

ब्रह्मा चेलानी @Chellaney

जनपथ

बिट्टू जी यदि पार्टी छोड़ हुए 'गद्दार',
इस रिश्ते से क्या लगे ममता-शरद पवार!
ममता-शरद पवार पूर्व में थे कांग्रेसी,
राहुल जी पहचान उन्हें अब देंगे कैसी?
जो 'अबोध' इंसान स्वयं पर रहता लट्टू,
उसको ही 'गद्दार' दिखाई देते बिट्टू!!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय :0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 204

पीएम ने अंकों की बीमारी से बचने व तनाव मुक्त होकर पढ़ाई करने का दिया मंत्र

- मोदी ने छात्रों को पढ़ाई के पैटर्न पर भरोसा करने की भी सलाह दी, संतुलन बनाने पर दिया जोर
- परीक्षाएं त्योहार जैसे हैं, जश्न मनाना चाहिए, नंबर के बजाय जीवन पर फोकस करें

नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शुक्रवार को आयोजित 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं से बातचीत करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ● प्रेट्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने से पहले छात्रों को अंकों की बीमारी से बचने, तनाव मुक्त होकर पढ़ाई करने और जीवन को बेहतर बनाने का मंत्र दिया। छात्रों को पढ़ाई के पैटर्न पर भरोसा करने की भी सलाह दी। कहा कि यदि कोई सलाह देता है तो उसे सुनो, समझो और ठीक लगे तो उसमें बदलाव कर सकते हो। किसी के कहने भर से बदलाव मत करो। मैं प्रधानमंत्री बन गया, तब भी कुछ लोग बताते हैं कि ऐसा करो, तो कोई कहता है वैसा करो। परीक्षा पे चर्चा के पैटर्न में भी मैं धीरे-धीरे कुछ बदलाव लाता जा रहा हूं।

परीक्षा पे चर्चा के नौवें संस्करण के तहत पीएम ने देश के अलग-अलग हिस्सों के छात्रों के साथ पिछले दिनों चर्चा की थी, जो शुक्रवार को प्रसारित हुई। इस दौरान छात्रों ने पढ़ाई, तकनीक, परीक्षाओं की तैयारी आदि से जुड़े सवाल किए, तो पीएम ने भी छात्रों से विकसित भारत को लेकर सवाल किए और उन्हें उसे पूरा करने के लिए कुछ नए लक्ष्य भी दिए। तेलंगाना के छात्र वेंकटेश ने पूछा कि टेक्नोलाजी और रोबोटिक्स में मुझे बहुत रुचि है, लेकिन लोग बोलते हैं मार्क्स ज्यादा जरूरी है। आप बताइए स्किल जरूरी है या फिर मार्क्स? पीएम ने जवाब दिया कि हर चीज में संतुलन होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए दबाव से निपटने के बारे में कहा कि शिक्षा सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए है। परीक्षाएं त्योहारों की तरह हैं, उनका जश्न मनाना चाहिए। पीएम ने छात्रों को सपने देखने की भी सीख दी और कहा कि सपने नहीं देखना भी अपराध है। उन्होंने छात्रों को स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने की आदत डालने को कहा। मोदी ने याद किया कि एक नेता ने उनकी जन्मतिथि पर फोन किया और बताया कि मैंने 75 वर्ष पूरे कर लिए। इस पर मैंने जवाब दिया- नहीं, 25 वर्ष बाकी हैं। जो सामने है, उसे जीने की कोशिश करो।

गेमिंग व तकनीक के सुरक्षित इस्तेमाल की सलाह दी

पीएम ने कहा, आपको गेमिंग में दिलचस्पी है, सिर्फ इसलिए समय बिताने के लिए इसमें शामिल न हों। मजे के लिए ऐसा न करें। जो लोग पैसे के लिए गेमिंग में शामिल होते हैं, वे बर्बाद ही होंगे। छात्रों को एआइ के सुरक्षित इस्तेमाल की टिप्स दी।

चाय मिलने पर मुस्कराए पीएम, कहा- चाय वाले को चाय

चर्चा समाप्त होने के बाद त्रिपुरा की छात्रा ने जब पीएम को आर्गेनिक चाय भेंट की, तो पीएम उसे देख मुस्कराए और कहा कि चाय वाले को चाय।

'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के दौरान पीएम ने दिव्यांग बच्ची को दिया सहारा ● प्रेट्र

शिक्षकों और अभिभावकों को भी दिए अहम सुझाव

- **शिक्षकों को** : छात्रों में जिज्ञासा पैदा करने और समझ बेहतर बनाने के लिए उन्हें पहले से जानकारी दें।
- **माता-पिता को** : वे बच्चों को उनकी क्षमता, योग्यता और रुचि के अनुसार खिलने दें।

छात्रों को यह भी सीख दी

- लक्ष्य पहुंच के अंदर होने चाहिए लेकिन आसानी से हासिल होने वाले नहीं, लक्ष्य बनाएं और काम करें।
- पढ़ाई, स्किल्स, आराम और हाबीज में संतुलन ही विकास की कुंजी है।
- मिलकर सीखना सभी को बेहतर बनाने में मदद करता है।
- पहले स्कूली पढ़ाई पर ध्यान दें। प्रतियोगी परीक्षाएं उसके साथ या बाद में हो जाएंगी।
- परीक्षाएं त्योहारों की तरह हैं, उन्हें मनाएं।
- कंफर्ट जोन जीवन को आकार नहीं देते बल्कि आपका जीने का तरीका उसे आकार देता है।

धोखाधड़ी मामले में सांसद पप्पू यादव देर रात गिरफ्तार

सांसद को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस

जागरण संवाददाता, पटना : करीब 31 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। रात करीब 11 बजे पुलिस पटना में मंदिरी स्थित उनके आवास पहुंची, लेकिन पप्पू यादव गिरफ्तारी नहीं देने पर अड़े हुए थे। उनके समर्थक भी कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि सांसद को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के लिए आइजीआइएमएस ले जाया गया है।

वर्ष 1995 में पटना के गर्दनीबाग थाने में दर्ज मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने पप्पू यादव समेत तीन आरोपितों के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसका मकान धोखाधड़ी के जरिए किराए पर लिया गया था। मकान मालिक को बाद में पता चला कि उनके घर का इस्तेमाल कार्यालय चलाने के लिए किया जा रहा, जबकि किराए पर लेते समय तथ्यों को छुपाया गया था। अदालत ने पहले आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। जब वारंट पर भी उनकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकी, तो कोर्ट ने इश्तेहार चस्पा करने का आदेश दिया। इसके बावजूद आरोपित कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अब अदालत ने उनकी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश पारित किया है। आदेश तीन दिन पहले ही जारी हुआ है। पुलिस की टीम के साथ आसपास के कई थानों की पुलिस उनके आवास पर पहुंची। पुलिस के आने की सूचना पर घर के बाहर समर्थकों की भीड़ जुट गई।

संसद प्रश्नोत्तर

पीएम-प्रणाम योजना के तहत राज्यों को प्रोत्साहन नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : पीएम-प्रणाम योजना के तहत केंद्र ने इसके लांच के बाद से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया है। यह योजना जून 2023 में कैबिनेट की स्वीकृति के बाद शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है। यह योजना वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर 2025-26 तक तीन वर्षों के लिए बनाई गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया, अब तक, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है।"

दस साल में रेलवे ने दीं पांच लाख नौकरियां : रेल मंत्री

नई दिल्ली, प्रेट्र : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय रेलवे की वित्तीय सेहत में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और अब सभी खर्च पूरे करने के बाद भी रेलवे के पास छोटा राजस्व अधिशेष बच रहा है। बताया कि 2024-25 वित्त वर्ष में रेलवे का आपरेटिंग रेशियो 98.22% रहा, सकल ट्रैफिक प्राप्तियां 2,65,114 करोड़ रुपये रहीं और 2,660 करोड़ रुपये का अधिशेष दर्ज किया गया। 2014 से 2024 के बीच रेलवे में लगभग 5.04 लाख नौकरियां दी गईं। तीसरे कार्यकाल में 1.5 लाख और रोजगार देने की प्रक्रिया जारी है।

कनाडा में पढ़ाई कर रहे 17 भारतीयों की हमलों में मौत

नई दिल्ली, प्रेट्र : कनाडा में पढ़ाई कर रहे 17 भारतीयों की 2018-2025 के बीच "हिंसक हमलों" के कारण मौत हो गई। विदेश में मारे गए भारतीय छात्रों की संख्या कनाडा में सर्वाधिक है। एआइएमआइएम के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने विभिन्न देशों में भारतीय छात्रों की मौत के आंकड़ों को देशवार तालिका के रूप में प्रस्तुत किया। कहा, सरकार विदेश में भारतीय छात्रों की सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देती है व हिंसक घटनाओं की निगरानी करती है।

सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के 814 जजों में 116 महिलाएं

नई दिल्ली, आइएएनएस : कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि उच्च न्यायपालिका में वर्तमान में कार्यरत जजों की संख्या 814 है, जिनमें 116 महिला जज हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा 18 महिला जज हैं। मेघवाल ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कार्यरत जजों और महिला जजों की संख्या साझा की, जिसमें यह बताया गया कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 33 जजों में केवल एक महिला हैं। 2014 से अब तक उच्च न्यायालयों में 170 महिला जजों की नियुक्ति की गई है, जिसमें पांच वर्षों में 96 और सुप्रीम कोर्ट में छह महिला जज शामिल हैं।

बांग्लादेश से संबंध तीसरी दुनिया के देशों से स्वतंत्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने संसद को बताया कि भारत का बांग्लादेश के साथ संबंध "तीसरी दुनिया के देशों के साथ संबंधों से स्वतंत्र" है और सभी आवश्यक उपायों को अपनाते हुए नई दिल्ली अपने हितों पर प्रभाव डालने वाले घटनाक्रमों की निगरानी जारी रखे है। लोकसभा में राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार "पड़ोस में हो रहे घटनाक्रमों पर निरंतर निगरानी" रखती है, विशेष रूप से उन घटनाक्रमों पर जो सुरक्षा व राष्ट्रीय हितों पर प्रभाव डालते हैं। "सरकार भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्राथमिकता देती है।

बिहार में कैग को नहीं मिला 70877.61 करोड़ का हिसाब, दो माह की मोहलत

विपक्ष ने सरकार पर लगाया घोटाले का आरोप, हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है मामला

विकाश चन्द्र पाण्डेय ● जागरण

- विभिन्न विभागों द्वारा यह खर्च वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2022-22 के बीच हुआ
- 18687.98 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) उपलब्ध कराए गए हैं

पटना : हिसाब पुराना है, जिससे विधानसभा को भी पिछले वर्ष ही अवगत करा दिया गया था, फिर भी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) को अभी तक 70877.61 करोड़ के खर्च का पूरा ब्योरा नहीं मिला है। विभिन्न विभागों द्वारा यह खर्च वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2022-22 के बीच हुआ है। नियमानुसार, उतने ही अनुदान का भुगतान होना चाहिए, जितना कि वर्ष के भीतर खर्च होने की संभावना हो। सहायता अनुदान के खर्च का हिसाब 18 माह के भीतर उपलब्ध करा दिया जाना चहिए, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। विपक्ष ने इसे घोटाला बताते हुए धज्जियां उड़ा देने की सौगंध खाई, तो सरकार ने पाई-पाई का हिसाब देने की प्रतिबद्धता जताई। मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया, तब जाकर कहीं 18687.98 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) उपलब्ध कराए गए। फिर भी 52189.63 करोड़ का हिसाब-किताब बाकी रह जाता है। जो यूसी सौंपे गए हैं, उनसे संबंधित खर्च की गुणवत्ता का अब आकलन भी बेमानी हो जाएगा, क्योंकि काफी समय निकल चुका है।

लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) का विवरण

वित्तीय वर्ष	यूसी की संख्या	राशि करोड़ रुपये
2016-17	2647	14452.38
2017-18	525	3746.64
2018-19	542	5870.67
2019-2021	27041	17980.24
2021-22	15348	16014.34
2022-23	3546	12813.34

(नोट : शिकायत के बाद मात्र 18687.98 करोड़ के यूसी सौंपे गए)

पिछले वर्ष जुलाई में कैग ने विधानसभा को सौंपी अपनी रिपोर्ट में 49649 मामलों में लंबित यूसी का उल्लेख किया था। किशोर कुमार इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू और न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ सुनवाई कर रही। महाधिवक्ता पीके शाही ने यथाशीघ्र यूसी सौंप दिए जाने के लिए खंडपीठ को आश्वस्त किया है। बहरहाल, विस्तृत रिपोर्ट के लिए सरकार को दो माह की मोहलत मिल गई है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन का कहना है कि इस बीच चालू वित्तीय वर्ष के खातों की क्लोजिंग भी करनी होगी। अपनी ही सुस्ती के कारण विभागों पर लेखा-जोखा का दबाव बढ़ेगा। आशंका है कि पुराने हिसाब-किताब में व्यस्तता के बहाने वे चालू वित्तीय वर्ष का हिसाब दबा लें। सरकार में यही कार्य-संस्कृति बन गई है।

लंबित यूसी के वर्षों में एनडीए की भी सरकार रही थी और महागठबंधन की भी। इस हवाले से एक-दूसरे को आईना दिखाने में दोनों पक्ष नहीं चूके। दरअसल, यूसी से पता चलता है कि जारी की गई राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए ही हुआ है। इसके नहीं मिलने से धन के गबन, दुरुपयोग या विचलन की आशंका होती है। कैग ने कहा था कि इतने बड़े पैमाने पर यूसी का नहीं दिया जाना वित्तीय अनुशासन के लिए ठीक नहीं है। यह संकेत करता है कि उल्लेखित राशि लाभार्थियों तक सही ढंग से नहीं पहुंची है। याचिकाकर्ता ने मामले की जांच सीबीआइ या किसी अन्य सक्षम एजेंसी से कराने का आग्रह किया है। एक विकल्प यह भी है कि हाई कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में टीम गठित की जाए, जो जांच करे।

सीमा सुरक्षा के लिए तकनीक का इस्तेमाल बेहद जरूरी : शाह

हीरानगर बार्डर की बोबिया पोस्ट पर सोलर प्लांट के निर्माण को देखते गृहमंत्री शाह ●

जागरण संवाददाता, कठुआ : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 60 वर्ष पहले की सीमा-संबंधी चुनौतियां आज पूरी तरह से बदल चुकी हैं। जवानों का शौर्य, तत्परता और ड्यूटी के प्रति अटूट लगन आवश्यक है, लेकिन अब चुनौतियां तकनीकी रूप से उत्पन्न हो रही हैं। इनका सामना करने के लिए उन्नत तकनीकी समाधान खोजना और अपनाना होगा। शाह ने शुक्रवार को कठुआ के हीरानगर बार्डर पर आउट पोस्ट गुरनाम व बोबिया का दौरा कर जवानों का हौसला बढ़ाया। साथ ही, आपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले बलिदानी जवानों को नमन किया। सीमा प्रहरियों के कल्याण के लिए सात करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया जिनमें नवनिर्मित सोलर वाटर हीटर, सोलर पावर प्लांट और आफिसर्स मेस शामिल हैं।

जम्मू-कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को शाह ने कहा कि बीएसएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में कहा था कि बीएसएफ का 61वां वर्ष आधुनिकीकरण के अलावा जवानों और उनके परिवार के कल्याण का वर्ष होगा। अधिकारियों से कहा कि घुसपैठ रोकने के लिए तकनीकी ढांचा मजबूत होना चाहिए। शाह ने कहा कि बीएसएफ जवानों के कल्याण के लिए जल्द विशेष योजना लेकर आ रहे हैं। पूरी सीमा सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी तौर पर आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ी राशि खर्च करेगी। बोबिया परिसर में पौधरोपण किया। सीमा प्रहरियों के कल्याण के लिए सात करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल की 242 करोड़ की बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे।

तिरुपति लड्डू में इस्तेमाल घी बाथरूम क्लीनर से बना : चंद्रबाबू

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ● फाइल

अमरावती, आइएएनएस : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि तिरुपति लड्डू बाथरूम की सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले रसायनों से बने घी से तैयार किया गया था, जो पूर्ववर्ती वाइएसआर कांग्रेस पार्टी (वाइएसआरसीपी) सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ। उन्होंने वाइएसआरसीपी पर 'प्रसाद' (अर्पण) को मिलावट करके श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की पवित्रता को धूमिल करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री नायडू ने कहा, "पिछले पांच वर्षों में, उन्होंने (वाइएसआरसीपी) रसायनों से बने घी से 'प्रसाद' तैयार किया। यह घी बाथरूम की सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले रसायनों से बनाया गया था।" नायडू ने कर्नूल जिले के येम्मिगानुर में किसानों के बीच 'आपकी भूमि-आपका अधिकार' पट्टेदार पासबुक वितरण के अवसर पर सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी यह दावा कर रहे हैं कि सीबीआइ ने क्लीनचिट दी है, लेकिन देवस्थानम के अध्यक्ष रहे उनके चाचा वाई.वी. सुब्बा रेड्डी ने स्वीकार किया कि मिलावट हुई थी।

जनसुराज को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- जनता ने नकार दिया तो कोर्ट का सहारा ले रहे

बिहार चुनाव रद करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से शीर्ष अदालत का इन्कार, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर (पीके) की पार्टी जनसुराज की बिहार का चुनाव रद कर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इन्कार कर दिया। कोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह याचिका और कुछ नहीं, बल्कि समग्र रूप से चुनाव याचिका है जिसमें पूरे राज्य का चुनाव रद करने की मांग की गई है। चुनाव याचिका व्यक्तिगत तौर पर दाखिल की जाती है। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आपको चुनाव में कितने वोट मिले? जब जनता ने नकार दिया तो आप न्यायिक मंच का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बाद में शीर्ष अदालत ने जनसुराज पार्टी को पटना हाई कोर्ट जाने की छूट देते हुए याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी।

ये आदेश और टिप्पणियां प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने जनसुराज पार्टी की याचिका पर कीं। जनसुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव रद करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि चुनाव के दौरान बिहार सरकार ने गैरकानूनी तरीके अपनाए। इसलिए चुनाव रद कर दोबारा कराए जाएं।

सुनवाई के दौरान जनसुराज के वकील सीयू सिंह ने जैसे ही दलीलें रखना शुरू किया, तभी कोर्ट ने सीधा सवाल किया यह याचिका कैसे हो सकती है, आपको चुनाव याचिका दाखिल करनी चाहिए। जस्टिस बागची ने पूछा कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा-100 के किस प्रविधान के तहत पूरे चुनाव को रद करने की मांग की जा सकती है? वकील सीयू सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही मुफ्त रेवड़ियां बांटने के मामले में सुनवाई कर रहा है। बिहार जैसे आर्थिक रूप से कमजोर राज्य में बिना बजटीय प्रविधान के हजारों करोड़ रुपये की घोषणा से समान अवसर बाधित होता है।

सीयू सिंह ने कहा कि बिहार सरकार ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 15,600 करोड़ रुपये बांटे, जिससे दूसरे राजनीतिक दलों को बराबरी का मौका नहीं मिला। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यह एक तरह से चुनाव याचिका है जिसमें पूरे राज्य का चुनाव रद करने की मांग की गई है। मामले में कोर्ट का नकारात्मक रुख देखते हुए वकील ने हाई कोर्ट जाने की छूट मांगते हुए याचिका वापस ले ली।

हंगामे की भेंट चढ़ गए लोकसभा में जनहित के 19 घंटे

बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को लोकसभा में हंगामा करते विपक्षी दलों के सदस्य ● प्रेट्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : लोकसभा में पूरे सप्ताह चले सियासी टकराव ने संसदीय कार्यवाही को लगभग ठप कर दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद बजट पर चर्चा शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन विपक्ष के लगातार हंगामे व नारेबाजी के कारण अभी तक ठोस कामकाज नहीं हो सका। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मौजूदा सत्र में अब तक लोकसभा के 19 घंटे 13 मिनट अव्यवस्था और स्थगन की भेंट चढ़ चुके हैं। शुक्रवार को भी सदन पहली बार तीन मिनट एवं दूसरी बार मात्र सात मिनट ही चल पाया, जिसके बाद कार्यवाही नौ फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सुबह जैसे ही प्रश्नकाल की शुरुआत हुई, विपक्षी सदस्यों ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दीं। स्पीकर ओम बिरला ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रश्नकाल सभी सदस्यों का साझा समय होता है और इसमें जनता से जुड़े सवालों को उठाया जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई सदस्यों के प्रश्न सूचीबद्ध थे, लेकिन गतिरोध पैदा कर प्रश्नकाल को बाधित किया गया। विपक्ष के व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताते हुए स्पीकर ने कहा कि 140 करोड़ लोगों की अपेक्षा होती है कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो। जनता ने सांसदों को पोस्टर दिखाने व नारे लगाने के लिए चुनकर नहीं भेजा है, बल्कि विमर्श एवं समस्याओं का समाधान खोजने के लिए चुना है।

खरगे बोले- प्रधानमंत्री में सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं है

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह सदन को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलाना चाहती। प्रधानमंत्री मोदी में उनसे पूछे गए सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में किसी सवाल का उत्तर नहीं देने का दावा करते हुए खरगे ने दावा किया कि "झूठ दोहराना" ही पीएम मोदी का काम रह गया है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब जब कांग्रेस के पास है, तो सत्ता में बैठे लोगों के पास नहीं होगी, यह विश्वास के लायक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए खरगे ने कहा कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने संबंधी विवाद को सिखों के अपमान से जोड़ने के बयान को उन्होंने खारिज किया।

'मुस्लिमों को बंदूक थमा रही सरकार' के बयान पर हंगामा

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता: बंगाल विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को उस वक्त अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई, जब भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल और राज्य के शहरी विकास मंत्री व कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम के बीच तीखी बहस छिड़ गई। अल्पसंख्यकों के लिए बजट आवंटन और मदरसा शिक्षा को लेकर दिए गए अग्निमित्रा के बयानों ने सदन के भीतर भारी हंगामा खड़ा कर दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी को हस्तक्षेप करते हुए विवादित टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही (रिकार्ड) से बाहर निकालने का निर्देश देना पड़ा।

बजट पर चर्चा के दौरान आसनसोल दक्षिण की भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मदरसा शिक्षा के बजट में 10 प्रतिशत की वृद्धि की है, लेकिन वहां से डाक्टर या इंजीनियर क्यों नहीं निकल रहे? क्या यह पैसा घुसपैठियों को बचाने के लिए दिया जा रहा है? उन्होंने आगे बेहद कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि यह सरकार मुस्लिमों के हाथों में बंदूक थमा रही है और उन्हें अपराधी बना रही है। इन टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि भाजपा मुस्लिमों से नफरत करती है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिमों के योगदान का स्मरण कराते हुए पूछा कि क्या एपीजे अब्दुल कलाम और काजी नजरुल इस्लाम अपराधी थे? आपको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने भाजपा नेताओं के पुराने रिकार्ड पर भी सवाल उठाए और कहा कि भारत में सभी समुदाय भाई-चारे के साथ रहते हैं।

तृणमूल ने मौलवी और मदरसों पर लुटाया बंगाल का खजाना : भाजपा

सांसद सुधांशु त्रिवेदी ● फाइल फोटो

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : बंगाल सरकार के बजट में अल्पसंख्यक मामलों के मदरसों के लिए आवंटित हुए 5713 करोड़ रुपये की तुलना विकास संबंधित अन्य मदों से करते हुए भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। भाजपा प्रवक्ता व सांसद डा. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने मां, माटी, मानुष की जगह मौलवी, मुअज्जिन और मदरसों पर ममता का खजाना लुटा दिया है। इतना ही नहीं, भाजपा प्रवक्ता ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का पुराना बयान भी याद दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ से प्रायोजित अनेक मदरसे बंगाल में संचालित हो रहे हैं। सुधांशु ने कहा कि बजट में अल्पसंख्यक मामलों व मदरसों के लिए 5713 करोड़ आवंटित किए गए हैं, उद्योग एवं वाणिज्य के लिए 1400 करोड़, आइटी के लिए 217 करोड़ और साइंस एंड रिसर्च के लिए मात्र 82 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

सहमति से संबंध के लिए उम्रसीमा घटाने पर कोई विचार नहीं : केंद्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्र सरकार पोक्सो कानून में यौन संबंध बनाने के लिए सहमति की उम्र 18 वर्ष से कम करने की पक्षधर नहीं है। सरकार का कहना है कि सहमति की उम्र में किसी भी प्रकार की ढील या अपवादों का समावेश बाल सुरक्षा को कमजोर करेगा, शोषण के जोखिम को बढ़ाएगा और बच्चों विशेषकर किशोरियों की सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को कमजोर करेगा।

केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से लोकसभा सदस्य सुब्बारायमण के. और सेल्वाराज वी. ने सवाल किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा पोक्सो कानून के बार-बार दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए किशोर वय के वास्तविक संबंधों के मामले में रोमियो जूलिएट क्लाज पर विचार करने और पोक्सो कानून के कठोर प्रविधानों से छूट देने के सुझाव का जिक्र करते हुए इस बारे में स्थिति और ब्योरा पूछा था।

इसके जवाब में अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि पोक्सो अधिनियम में सहमति शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है और वैधानिक ढांचे के तहत 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना अपराध माना जाता है, चाहे सहमति दी गई हो या नहीं।

पोक्सो नियम 2020 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने और बाल हितैषी प्रक्रियाओं और संस्थागत सुरक्षा उपायों के माध्यम से बच्चों को यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा से बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचित किया गया था।

नेहरू-गांधी परिवार पर प्रतिबंधित पुस्तकों की लाइब्रेरी खोलेंगे निशिकांत

नई दिल्ली, आइएएनएस : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा के अंशों को उद्धृत करने पर केंद्र सरकार के विरोध के बाद उठे विवाद के बीच, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को कहा कि वह नेहरू-गांधी परिवार के योगदान की जानकारी प्रदान करने के लिए सुलभ लाइब्रेरी स्थापित करेंगे, जिसमें प्रकाशित और प्रतिबंधित पुस्तकें शामिल होंगी। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को अक्सर निशाना बनाने वाले दुबे ने गुरुवार को 40 पुस्तकों की एक सूची जारी की थी। इन पुस्तकों को उन्होंने भारत के 'वास्तविक इतिहास' को उजागर करने वाली व कांग्रेस के पिछले शासन से जुड़े विवादों को सामने लाने वाली बताया था।

चिंतन

सालों से जो बोया, वही काट रहा है पाकिस्तान

जैसा बोएंगे, वैसा काटेंगे। यह कहावत पाकिस्तान पर पूरी तरह से सटीक उतरती है। सालों तक आतंकवाद का पालन-पोषण करने के बाद आज पाकिस्तान खुद उसी आतंकवाद से जूझ रहा है। पाकिस्तान ने सरकारी नीति बनाकर आतंकवाद को शह दी। सरकारी संरक्षण की वजह से वहां आतंकवाद दिन दूनी, रात चौगुनी तेजी से फैला। हालात यह हो गए हैं कि भारत सहित दुनिया के तमाम हिस्सों में होने वाली किसी भी आतंकी वारदात में प्रत्यक्ष या परोक्ष पाकिस्तान का हाथ निकल ही जाता है। भारत सालों से पाकिस्तानी आतंकवाद का शिकार रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों पर हुए भारतीय हमलों में मारे गए आतंकियों के जनाजों को कंधा देते हुए पाकिस्तानी सैन्य अफसरों के फोटो व वीडियो दुनिया ने देखे हैं। शुक्रवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद में कथित आत्मघाती बम विस्फोट में दर्जनों लोगों की मौत हो गई और डेढ़ सौ से अधिक लोग घायल हो गए। शहजाद टाउन क्षेत्र स्थित तरलाई इमामबारगाह में शुक्रवार की नमाज के दौरान विस्फोट हुआ। यह घटना उस समय हुई जब उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव पाकिस्तान के दौरे पर थे। फिलहाल किसी भी समूह ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि हमलावर एक विदेशी नागरिक था और उसके संबंध 'फितना अल ख्वारिज' से थे। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को 'फितना अल ख्वारिज' कहा जाता है। टीटीपी तालिबान का एक सहयोगी संगठन है, जो मुख्य रूप से पड़ोसी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सक्रिय है। हमला किसने किया, यह जांच का विषय हो सकता, लेकिन यह आतंकवादी हमला था, इस पर कोई शक नहीं है। सवाल यह है कि जिस तालिबानी संगठन का नाम इस विस्फोट से जुड़ रहा है, उसको पाकिस्तान ने ही पाला-पोसा और बड़ा बनाया। बदली परिस्थितियों में पाकिस्तान का वही सृजन उसके लिए चुनौती बन गया है। पाकिस्तान के कई राज्यों में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। आतंकी घटनाओं का दुखद और मानवीय पहलू यह है कि इसके शिकार हमेशा निर्दोष और मासूम लोग ही होते हैं। इनमें बड़ी संख्या बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की होती है। किसी आतंकी घटना में बचे लोग भी लंबे समय उसकी दहशत से नहीं उबर पाते। असल में आतंकवाद किसी सरकार या देश से अधिक मानवता के खिलाफ अपराध होता है। पाकिस्तान के शासकों ने शायद ही कभी इस बात को समझा हो, क्योंकि आज भी भारत के खिलाफ उसकी यह नीति जारी है। भारत के सख्त रुख के बाद उसकी गतिविधियां कुछ कम तो हुई हैं, लेकिन वह अब भी अजहर मसूद जैसे दुर्दांत आतंकी को प्रश्रय दे रहा है। कई आतंकी कैंप चला रहा है। वह अब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि आतंकवाद की उसकी सरकारी नीति ने पाकिस्तान के आम लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया है। जो संसाधन लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होने थे, वे आतंकवाद को पोषित करने में लग रहे हैं। अब तो यह हालात हो गए है कि पाकिस्तान का कोई इलाका सुरक्षित नहीं है। करीब तीन महीने पहले भी इस्लामाबाद में जिला एवं सत्र न्यायालय की इमारत के बाहर एक आत्मघाती बम विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई थी। इसी महीने की शुरुआत में एक अन्य आत्मघाती हमले में खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिण वजीरिस्तान स्थित एक कैडेट कॉलेज में छह लोग घायल हो गए थे। बेहतर हो कि पाकिस्तान अब अपने गिरेबां में झांके।

'ऑरेंज इकॉनमी' युवाओं का भविष्य

करियर
ममता कुशवाहा

पारंपरिक क्षेत्रों में जहां विकास का आधार मुख्यतः प्राकृतिक संसाधन या विनिर्माण उद्योग रहे हैं, वहीं ऑरेंज इकॉनमी विचारों, प्रतिभा, डिजिटल रचनात्मकता, डिज़ाइन, मीडिया, मनोरंजन और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति पर आधारित है। भारत जैसे युवाओं की विशाल आबादी वाले देश, जहां समृद्ध सांस्कृतिक विरासत मौजूद है, ऑरेंज इकॉनमी न केवल एक नया आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, बल्कि बेरोज़गारी की समस्या के समाधान, कौशल विकास के विस्तार और वैश्विक रचनात्मक उद्योगों में नेतृत्व स्थापित करने का एक सशक्त अवसर भी प्रदान करती है। युवाओं के लिए यह केवल एक नया करियर विकल्प नहीं, बल्कि आत्म-अभिव्यक्ति, नवाचार और वैश्विक प्रभाव का द्वार है।

ऑरेंज इकॉनमी की अवधारणा इस बात में एक क्रांतिकारी बदलाव का संकेत देती है कि देश रचनात्मकता, नवाचार और सांस्कृतिक उद्योगों को आर्थिक विकास के प्रमुख स्रोत के रूप में कैसे देखते हैं। पारंपरिक क्षेत्रों में जहां विकास का आधार मुख्यतः प्राकृतिक संसाधन या विनिर्माण उद्योग रहे हैं, वहीं ऑरेंज इकॉनमी विचारों, प्रतिभा, डिजिटल रचनात्मकता, डिज़ाइन, मीडिया, मनोरंजन और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति पर आधारित है।

भारत जैसे देश के लिए, जहां युवाओं की विशाल आबादी और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत मौजूद है, ऑरेंज इकॉनमी न केवल एक नया आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, बल्कि बेरोज़गारी की समस्या के समाधान, कौशल विकास के विस्तार और वैश्विक रचनात्मक उद्योगों में नेतृत्व स्थापित करने का एक सशक्त अवसर भी प्रदान करती है। अपने मूल स्वरूप में ऑरेंज इकॉनमी के अंतर्गत एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, डिज़ाइन, डिजिटल कंटेंट निर्माण, संगीत, फिल्म, विज्ञापन, फैशन और रचनात्मक तकनीक जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ये सभी उद्योग तेज़ी से डिजिटल प्लेटफॉर्म और वैश्विक बाज़ारों से जुड़े हुए हैं, जिससे दूर-दराज़ क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए भी इनमें प्रवेश संभव हो गया है। इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और डिजिटल उपकरणों के प्रसार के साथ रचनात्मकता अब केवल शौक नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक और टिकाऊ करियर विकल्प बनती जा रही है। यह बदलाव पारंपरिक रोजगार मॉडल से अलग है, जहां सफलता का रास्ता मुख्यतः इंजीनियरिंग, चिकित्सा या सरकारी नौकरियों जैसे परंपरागत पेशों से जुड़ा हुआ था। ऑरेंज इकॉनमी का सबसे आशाजनक पक्ष इसकी व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन की क्षमता है। जैसे-जैसे रचनात्मक उद्योगों का विस्तार हो रहा है, वैसे-वैसे विभिन्न प्रकार के कौशलों की मांग भी बढ़ रही है, जैसे एनीमेशन और कोडिंग में तकनीकी दक्षता, कहानी लेखन, डिज़ाइन थिंकिंग, मार्केटिंग और डिजिटल रणनीति। सरकारें और शैक्षणिक संस्थान अब इस संभावना को गंभीरता से समझने लगे हैं। स्कूलों और कॉलेजों में क्रिएटिव लैब की स्थापना, पाठ्यक्रमों में रचनात्मक कौशलों का समावेश और डिजिटल कला से जुड़े व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर, भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यबल तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

अनुमान है कि 2030 और उसके बाद लाखों युवा रचनात्मक क्षेत्रों में अवसर प्राप्त कर सकेंगे, जिससे आर्थिक विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक समृद्धि भी बढ़ेगी। इस परिवर्तन की आधारशिला कौशल विकास है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली अक्सर रटंत विद्या और सैद्धांतिक ज्ञान पर केंद्रित रही है, जिसमें रचनात्मकता और नवाचार के लिए बहुत कम स्थान होता है। जबकि ऑरेंज इकॉनमी एक ऐसे दृष्टिकोण की मांग करती है, जो प्रयोग, आलोचनात्मक सोच, सहयोग और बहुविषयक अध्ययन को प्रोत्साहित करे। जब छात्रों को प्रारंभिक स्तर से ही रचनात्मक उपकरणों और डिजिटल प्लेटफॉर्म से परिचित कराया जाता है, तो उनमें न केवल तकनीकी दक्षता विकसित होती है, बल्कि आत्मविश्वास और उद्यमशीलता की भावना भी जागृत होती है। यही मानसिक बदलाव उन्हें वैश्विक रचनात्मक अर्थव्यवस्था

में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सक्षम बनाता है। ऑरेंज इकॉनमी का एक महत्वपूर्ण पहलू अवसरों का लोकतंत्रीकरण है। पूंजी-प्रधान उद्योगों के विपरीत, रचनात्मक क्षेत्रों में प्रवेश के लिए अपेक्षाकृत कम निवेश की आवश्यकता होती है। एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और रचनात्मक सोच, ये तीनों मिलकर डिजिटल कंटेंट, डिज़ाइन या गेमिंग जैसे क्षेत्रों में करियर की शुरुआत के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों या ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और जिनके पास पारंपरिक करियर विकल्पों तक पहुंच सीमित होती है। रचनात्मक कौशल और डिजिटल साक्षरता से उन्हें सशक्त बनाकर ऑरेंज इकॉनमी सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। फिल्म, संगीत, फैशन और डिजिटल कंटेंट के माध्यम से सांस्कृतिक कथाएं अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचती हैं। जैसे-जैसे भारतीय रचनात्मक उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है, वैसे-वैसे देश की सांस्कृतिक उपस्थिति और आर्थिक प्रभाव भी मजबूत होता जाता है। हालांकि, एक सशक्त ऑरेंज इकॉनमी की दिशा में यात्रा चुनौतियों से मुक्त नहीं है। आधारभूत संरचना की कमी, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण का अभाव, वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुंच और अपर्याप्त नीति ढाँचे विकास में बाधा बन सकते हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार, शैक्षणिक संस्थानों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिए, जो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करें, बौद्धिक संपदा की रक्षा करें, नवाचार को बढ़ावा दें और रचनात्मक उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करें।

इसके अतिरिक्त, ऑरेंज इकॉनमी के विकास के लिए सामाजिक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आवश्यक है। अनेक समाजों में रचनात्मक पेशों को आज भी अस्थिर या कम प्रतिष्ठित माना जाता है, जबकि पारंपरिक नौकरियों को अधिक सुरक्षित समझा जाता है। इस मानसिकता को बदलना युवाओं की प्रतिभा को पूरी तरह विकसित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब रचनात्मकता को एक वैध और मूल्यवान आर्थिक संपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाएगा, तब युवा बिना सामाजिक या आर्थिक भय के अपने जुनून को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। दीर्घकालिक दृष्टि से देखा जाए तो ऑरेंज इकॉनमी रोजगार और आर्थिक विकास की संरचना को नए सिरे से परिभाषित कर सकती है। जैसे-जैसे स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारंपरिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम कर रही हैं, वैसे-वैसे रचनात्मक उद्योग अधिक प्रासंगिक और टिकाऊ बनते जा रहे हैं। मानवीय कल्पना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को मशीनें आसानी से प्रतिस्थापित नहीं कर सकतीं। इसलिए रचनात्मकता में निवेश करना केवल एक आर्थिक रणनीति नहीं, बल्कि डिजिटल युग में सतत विकास की अनिवार्य आवश्यकता है। ऑरेंज इकॉनमी युवाओं के सशक्तिकरण, कौशल विकास और राष्ट्रीय प्रगति के लिए एक नए क्षितिज का उद्घाटन करती है।

रचनात्मक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करके, शिक्षा प्रणाली में सुधार लाकर और सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करके भारत जैसे देश ऑरेंज इकॉनमी की शक्ति का उपयोग कर चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं। युवाओं के लिए यह केवल एक नया करियर विकल्प नहीं, बल्कि आत्म-अभिव्यक्ति, नवाचार और वैश्विक प्रभाव का द्वार है। जैसे-जैसे दुनिया ज्ञान और रचनात्मकता आधारित भविष्य की ओर बढ़ रही है, ऑरेंज इकॉनमी आशा की किरण बनकर उभरती है, जो मानव रचनात्मकता और सांस्कृतिक समृद्धि पर आधारित समृद्धि का वादा करती है।

(लेखिका शिक्षिका हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

आर्थिकी
सतीश सिंह

मौद्रिक समीक्षा पर महंगाई का साया

महंगाई को 4% के लक्ष्य पर स्थिर रखने की प्रतिबद्धता, खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव और अनिश्चित वैश्विक आर्थिक माहौल के कारण और विकास की रफ्तार को बनाए रखने के लिए सतर्क रुख अपनाते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 6 फरवरी को नीतिगत ब्याज दर को 5.25% के स्तर पर अपरिवर्तित रखा। रिजर्व बैंक का प्राथमिक लक्ष्य महंगाई को नियंत्रित करना है। अस्तु,खाद्य पदार्थों की कीमतों में अनिश्चितता के कारण रिजर्व बैंक ने फिलहाल दरों को कम न करने का निर्णय लिया ताकि महंगाई और न बढ़े। दुनिया भर में आर्थिक अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनावों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर लगातार दबाव बना हुआ है, जिसके कारण सतर्कता बरतना आवश्यक है। डॉलर के मुकाबले रुपये की अस्थिरता और बॉन्ड यील्ड के दबाव के कारण भी केंद्रीय बैंक ने रेपो दर में कटौती करने से गुरेज किया। दिसंबर 2025 में रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 0.25% की कटौती की थी, जिससे यह मौजूदा स्तर पर आ गया। वैसे, 2025 की शुरुआत से रिजर्व बैंक नीतिगत दरों में 125 आधार अंकों की कटौती कर चुका है, लेकिन अभी तक बैंकों ने इस कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को नहीं दिया है, क्योंकि अभी भी नये ऋणों में आधार अंकों की कटौती करना शेष है. इसलिए, रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों को यथावत रखने के बाद भी उधारी दरों में कटौती की गुंजाइश बनी हुई है। रिजर्व बैंक,जिस दर पर बैंकों को ऋण देता है, उसे रेपो दर कहते हैं। जब रिजर्व बैंक इसे घटाता है तो बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है और बैंक इसका लाभ आमजन और जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। हालांकि,नीतिगत दरों में कटौती नहीं करने के बावजूद जरूरत पड़ने पर रिजर्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कटौती करके और ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ) के जरिये बैंकिंग प्रणाली की तरलता को बढ़ा सकता है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय बैंक ने 29 जनवरी 2026 को हुई नीलामी सहित, ओएमओ के माध्यम से रिजर्व बैंक बैंकिंग प्रणाली में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये डाल चुका है। सबसे महत्वपूर्ण,भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की गति अच्छी है। केंद्रीय बैंक मौद्रिक समीक्षा के दौरान वित्त वर्ष 2026 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के वृद्धि अनुमान को 7.3% से बढ़ाकर 7.4% कर दिया, जबकि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में इसके 6.9% रहने का अनुमान जताया है, जो इसके पहले 6.7% था, वहीं, वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में जीडीपी के 7% रहने का अनुमान जताया है, जो पहले 6.8% था। इसके अलावा, हाल ही में अमेरिकी सरकार ने टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है, जिससे निर्यात में इजाफा, आर्थिक गतिविधियों में तेजी, व्यापार घाटा में कमी आने, विदेशी मुद्रा में इजाफा आदि होने की उम्मीद है, जिससे अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के दौरान महंगाई के 2.1% रहने का अनुमान जताया है, जो पहले 2% था। वहीं, वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में इसके 3.2% रहने का अनुमान जताया है, जो पहले 2.9% था। महंगाई के कारण लोगों की क्रय शक्ति में कमी, जीवनयापन की लागत में वृद्धि, और बचत के वास्तविक मूल्य में गिरावट आती है। इससे गरीबों पर सबसे अधिक असर पड़ता है, क्योंकि उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं, जैसे भोजन और स्वास्थ्य के मद में ज्यादा खर्च करना पड़ता है। यह आर्थिक विकास को भी बाधित करती है और कंपनियों के मुनाफे को भी कम करती है। महंगाई दर के जमा दर से अधिक होने पर बैंक में जमा पैसों की वास्तविक कीमत घट जाती है और भविष्य के लिए जमा की गई पूंजी कम हो सकती है और बुढ़ापे में वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार जनवरी, 2026 में, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की ऋण वृद्धि दर धीमी होकर वर्ष दर वर्ष के आधार पर 13.1% रह गई, जो दिसंबर 2025 में 14.5% थी। वहीं, 5 जनवरी, 2026 को खत्म हुए पखवाड़े तक जमा वृद्धि दर कम होकर वर्ष दर वर्ष के आधार पर 10.6% रह गई। इस तरह, इस अवधि में बैंक जमा में लगभग 3 लाख 57 हजार करोड़ रुपये की कमी आई, जिससे क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात रिकॉर्ड 82.2% के उच्च स्तर पर पहुंच गया। इस वजह से फिलवक्त,बैंक तरलता की कमी का सामना कर रहे हैं और उन्हें जरूरतमंदों को ऋण देने में मुश्किलें आ रही है। निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि महंगाई आमजन और विकास की राह में एक बहुत बड़ी बाधक है। चूंकि, आगामी महीनों में इसमें तेजी आने की आशंका है, इसलिए, रिजर्व बैंक ने सतर्कता बरतते हुए रेपो दर को यथावत रखा है। बैंक जमा में लगातार कमी आने के कारण मौजूदा समय में बैंक पूंजी की भारी कमी का सामना कर रहे हैं।

(लेखक एसबीआई में एजीएम हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मानव के लिए नैतिक मूल्यों का क्या महत्व है?

संकलित
दर्शन

नैतिक मूल्य मानव को परिपूर्णता प्रदान कर उसे ईश्वरीय रचनाओं में श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु आधुनिकता के नाम पर इन मूल्यों का निरंतर अवमूल्यन होता जा रहा है। बढ़ता भौतिकतावाद उन्हें लील रहा है। परिणामस्वरूप नैतिकता घुट-घुटकर ही सांस ले पा रही है। यह स्थिति तब है जब नैतिकता को मानव समाज के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता मिली है। नैतिकता के अभाव में मनुष्यता का आकलन संभव ही नहीं। नैतिकता व्यक्ति के विकास में एक सीढ़ी के समान है, जिसके सहारे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। नैतिक मूल्यों के अभाव में मनुष्य मानव जीवन को निरर्थक बना देता है। प्रख्यात विचारक अल्बेयर कामू ने भी कहा है कि नैतिकता के बिना एक व्यक्ति इस दुनिया में किसी पशु के समान है। हम जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय नैतिक कसौटी पर कसने के बाद ही करते हैं, लेकिन देखने में आता है कि कई बार मनुष्य उसे अनदेखा कर फैसला करता है, जो नैतिक पतन का कारण बनता है। स्मरण रहे कि ईश्वर ने हमें सिर्फ सुख भोगने के लिए ही इस संसार में नहीं भेजा है। इसीलिए केवल भौतिक सुखों के लिए नैतिकता का परित्याग करना उचित नहीं। इसका एक कारण यही है कि अब हमने अपने अंतःकरण की आवाज को अनसुना करना आरंभ कर दिया है। हमें यह पता होता है कि अमुक कार्य नैतिक रूप से सही नहीं, लेकिन सुख के लिए वह कार्य करने से संकोच नहीं करते। इसमें अक्सर दूसरे के हितों की बलि चढ़ जाती है। स्वाभाविक है कि इससे टकराव बढ़ेगा।

बिना चिंतन के कीर्तन का कोई लाभ नहीं

संकलित
प्रेरणा

राजा के मन में आया कि अगर मैं भी भागवत की कथा सुन लूं तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। राजा ने एक पण्डित जी से बात की। पण्डित जी भागवत सुनाने के लिए तैयार हो गए। निश्चित समय पर भागवत-कथा आरंभ हुई। सात दिन बीतने पर कथा समाप्त हुई। दूसरे दिन राजा ने पण्डितजी को बुलाया और कहा- पण्डित जी ! न तो आपने भागवत सुनाने में कोई कमी रखी, न मैंने सुनने में कोई कमी रखी, फिर भागवत सुनने पर कोई फर्क तो नहीं पड़ा, बात क्या है? पण्डित जी ने कहा- महाराज! इसका उत्तर तो मेरे गुरु जी ही दे सकते हैं। राजा ने कहा- आप अपने गुरुजी को आदरपूर्वक मेरे यहां ले आएं, हम उनसे पूछेंगे। राजा ने अपनी शंका गुरु जी के सामने रखी कि, भागवत सुनने पर भी मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ? गुरुजी ने राजा से कहा कि थोड़ी देर के लिए मुझे अपना अधिकार दे दो। राजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। गुरु जी ने आदेश दिया कि राजा और पण्डित जी दोनों को बांध दो। राजपुरुषों ने दोनों को बांध दिया। अब गुरुजी ने पण्डित जी से कहा कि, तुम राजा को खोल दो। और राजा से कहा- तुम पण्डित जी को खोल दो। दोनों ने उत्तर दिया कि हम बंधे है कैसे एक-दूसरे को खोल सकते हैं। गुरु जी ने कहा- महाराज! मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया! राजा ने कहा- मैं समझा नहीं! गुरुजी बोले- जैसे खुद बंधा हुआ आदमी दूसरे को बन्धन-मुक्त नहीं कर सकता है, वैसे ही स्वयं ज्ञान को अपने अनुभव में उतारे बिना कोई दूसरे का कल्याण कैसे कर सकता है?

अंतर्मन

आज की पाती

डिजिटल क्रांति का सच

आज का दौर डिजिटल क्रांति का है, लेकिन यही क्रांति अब बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए चुनौती बनती जा रही है। भारत में तेजी से बढ़ते इंटरनेट उपयोग और सस्ते डेटा ने जहां अवसरों के नए द्वार खोले हैं, वहीं यह बच्चों के लिए एक अदृश्य खतरा भी बनकर उभरा है। इकोनोमिक सर्वे 2025-26 ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि डिजिटल एडिक्शन और अत्यधिक स्क्रीन टाइम अब सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम का रूप ले रहा है, क्योंकि स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म बच्चों के व्यवहार, सीखने की क्षमता और मानसिक संतुलन पर मापने योग्य प्रभाव डालने लगे हैं। यही नहीं, रिपोर्ट ने यह भी सुझाया है कि कम उम्र के उपयोगकर्ताओं की अधिक संवेदनशीलता को देखते हुए सोशल मीडिया के लिए आयु-आधारित सीमाएं तय करने पर विचार किया जाना चाहिए।

- रोहित कुमार यादव

ट्रेंड

ऐतिहासिक समझौता

यह एक ऐतिहासिक समझौता है, जो विशेष रूप से पूर्वी नागालैंड के विकास पथ को गति प्रदान करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे लोगों के लिए अवसरों और समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। यह पूर्वोत्तर में शांति, प्रगति और समावेशी विकास के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

'भारत विस्तार' प्लेटफार्म

किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और उनकी आजीविका में सुधार लाने के लिए हमने एआई के उपयोग का फैसला किया है। 'भारत विस्तार' प्लेटफार्म भी हम बना रहे हैं, जिस पर बीज, खाद, दवा और योजनाओं के सवाल और समाधान सब मिल जाएगा।

-शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री

सार्थक विकास

विकास वही सार्थक होता है जो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के मूल्यों का संरक्षण और सम्मान करते हुए हमें नित नए सोपान की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके।

-योगी आदित्यनाथ, सीएम, उप्र

शिक्षा विरोधी सोच

भाजपा की शिक्षा विरोधी सोच ही सरकारी स्कूलों को बंद करवा रही है। भाजपाई जानते हैं कि शिक्षा से लोगों में जागरूकता और वैज्ञानिक चेतना आती है जो भाजपा की दकियानूसी, रूढ़िवादी, संकीर्ण सोच और तंग नजरिये को उखाड़ फेंकने का काम करेगी।

-अखिलेश यादव, सांसद, सपा

करंट अफेयर

पूर्व मीडिया दिग्गज लाई को सोमवार को मिलेगी सजा

हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक पूर्व मीडिया दिग्गज जिमी लाई को चीन द्वारा लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत दिसंबर में दोषी ठहराए जाने के बाद सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। अब बंद हो चुके 'एप्पल डेली' अखबार के संस्थापक लाई (78) को इस मामले में आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। लाई के खिलाफ कार्रवाई की कुछ विदेशी सरकारों ने आलोचना की है। न्यायपालिका ने शुक्रवार को अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी कि वह सोमवार को पूर्वाह्न 10 बजे सजा सुनाए जाने की कार्यवाही शुरू करेगी। लाई चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के मुखर आलोचक रहे हैं और उन्हें 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। चीन पिछले वर्ष हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद शहर की स्थिरता के लिए इस कानून को आवश्यक मानता है। लाई के खिलाफ मुकदमे को व्यापक पैमाने पर हांगकांग में प्रेस की स्वतंत्रता के पतन के एक संकेतक के रूप में देखा गया है। लाई को सजा सुनाए जाने से चीन और विदेशी सरकारों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। लाई की दोषसिद्धि की अमेरिका और ब्रिटेन ने आलोचना की थी। लाई को विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत कर राजद्रोहपूर्ण लेख प्रकाशित करने की साजिश रचने का दोषी पाया गया।

ऑफ बीट

चार लाख साल पहले ग्रीनलैंड हरा-भरा था

लगभग 400,000 साल पहले, ग्रीनलैंड के बड़े हिस्से बर्फ-मुक्त थे। द्वीप की उत्तर-पश्चिमी उच्चभूमि पर झाड़ीदार टुंड्रा सूर्य की किरणों का आनंद लिया करता था। साक्ष्य बताते हैं कि कीड़ों से गुलजार स्प्रूस पेड़ों का जंगल, ग्रीनलैंड के दक्षिणी हिस्से में फैला हुआ था। उस समय वैश्विक समुद्र का स्तर बहुत अधिक था, आज के स्तर से 20 से 40 फुट ऊपर। दुनिया भर में, वह भूमि जो आज करोड़ों लोगों का घर है, पानी में डूबी हुई थी। वैज्ञानिक काफी समय से जानते हैं कि ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर पिछले दस लाख वर्षों में किसी न किसी समय गायब हो गई थी, लेकिन निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि यह कब गायब हुई थी। ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के लगभग एक मील मोटे हिस्से के नीचे से शीत युद्ध के दौरान निकाली गई जमी हुई मिट्टी का उपयोग करके तारीख निर्धारित की। समय - लगभग 416,000 वर्ष पहले, जिसमें बड़े पैमाने पर बर्फ-मुक्त स्थितियाँ 14,000 वर्षों तक चलीं - महत्वपूर्ण है। उस समय, पृथ्वी और इसके प्रारंभिक मानव सबसे लंबे अंतर-हिमनद काल से गुजर रहे थे क्योंकि बर्फ की चादरें 25 लाख वर्ष पहले उच्च अक्षांशों को ढके हुए थीं।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

तृणमूल कांग्रेस सरकार के बजट में मौलवी, मुअज्जिन और मदरसा पर खजाना लुटायाः त्रिवेदी

ममता का बंगाल लगातार तुष्टीकरण की गहरी खाई में गिरता जा रहाः भाजपा

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल सरकार के बजट पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जहां एक ओर देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास, पारदर्शिता और समावेशी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार का बजट तुष्टीकरण और असंतुलित प्राथमिकताओं को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने बजट में माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसों के लिए 5713 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जबकि इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए मात्र 1400 करोड़ रुपए रखे हैं। ममता बनर्जी ने मां, माटी, मानुष की जगह मौलवी, मुअज्जिन और मदरसा के लिए पूरी ममता का खजाना लुटा दिया है। शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए ये बातें कही।

त्रिवेदी ने कहा कि देश गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसका स्पष्ट प्रतिबिंब हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में देखने को मिला है। वहीं दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य तुष्टीकरण की गहरी खाई में लगातार गिरता चला जा रहा है, जिसकी अत्यंत विद्रूप झलक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में दिखाई पड़ती है। माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसों के लिए 5713 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है, जबकि इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए मात्र 1400 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यानी उद्योग और वाणिज्य के लिए केवल 1400 करोड़ रूपये जबकि माइनॉरिटी मदरसों के लिए 5713 करोड़ रूपये। इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 217 करोड़, माइनॉरिटी मदरसों के लिए 5700 करोड़ रुपए। साइंस व रिसर्च के लिए केवल 82 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी और पश्चिमी भाग के विकास के लिए क्रमशः 920 करोड़ और 810 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। मदरसों को दिया जाए, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन एक तरफ यह कहा जाता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में शिक्षा की स्थिति खराब है और दूसरी तरफ केवल मुअज्जिनों को, जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते कि वे वही होते हैं जो उस समय अजान लगाते हैं और लाउडस्पीकर पर जाते हैं, उनकी तनख्वाह दी जाती है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि ममता बनर्जी द्वारा प्रस्तुत बजट में विकास के प्रति पूरी तरह निर्ममता दिखाई देती है और मां, माटी, मानुष की जगह मौलवी और मदरसा को ममता दी गई है। मां, माटी, मानुष की जगह मौलवी, मुअज्जिन और मदरसा के लिए पूरी ममता का खजाना लुटा दिया गया है। इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार को दोष देना सही नहीं होगा, क्योंकि उनके मंसूबे पूरी तरह साफ हो चुके हैं। ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि 30 प्रतिशत की कम्युनिटी है और वो रोड रेज कर सकती हैं। ममता बनर्जी से सवाल यह है कि यह प्यार से दिया गया है या डर के कारण, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि रोड रेज हो सकती है?

भाजपा सांसद त्रिवेदी ने कहा कि वर्ष 2021 में तृणमूल कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बयान दिया था कि उनकी गिनती 30 प्रतिशत से शुरू होती है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी के सिद्धांत पर बजट में किसने किसकी बाजी मारी? ममता बनर्जी से एक प्रश्न हैं, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल के कुछ मदरसे, जिन्हें मान्यता प्राप्त मदरसा बोर्ड से समर्थन मिलता है, देश विरोधी गतिविधियों के केंद्र हैं। यह बात कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी से पहले मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कही थी। 9 सितंबर 2006 को एक बैठक में आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने कहा था कि पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा प्रायोजित अनेक मदरसे पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न हैं, जिनमें से कई बॉर्डर एरिया में सक्रिय हैं। ममता बनर्जी जवाव दें कि जिन मदरसों के एक बड़े हिस्से को पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने आईएसआई प्रायोजित बताया था, यदि उनकी सरकार उन्हें पोषित कर रही है, तो क्या यह राष्ट्र की सुरक्षा और सद्भावना की कीमत पर राजनीति करना नहीं है?

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि एक तरफ मुस्लिम समाज की 87 में से 78 जातियों को ओबीसी का दर्जा देकर पहले उन पर संवैधानिक ममता उड़ेली गई और अब वित्तीय ममता भी उढेली जा रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मौलवी और मुअज्जिन को जो पैसा मिलेगा, उसके लिए किसी प्रकार का रेजिडेंशियल या रेजिडेंसी प्रूफ भी नहीं मांगा जा रहा है। इससे यह साफ हो जाता है कि इंडी गठबंधन, जो अपने जिस मूल विचार पर चल रहा है, वह तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक अत्यंत विद्रूप और विकृत स्वरूप में दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए केवल तृणमूल कांग्रेस ही दोषी नहीं है, बल्कि माइनॉरिटी कम्युनिटी की एक ऐसी ताकत भी है, जो यह दर्शाती है कि वे कुछ भी करेंगे और सरकारों व सेक्युलर दलों को झुकाने में सफल होंगे।

खबर संक्षेप

भूकंप से हिला गोंडा 3.7 रही तीव्रता

गोंडा। शुक्रवार सुबह गोंडा भूकंप के झटकों से हिल गया। भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई। इसका केंद्र

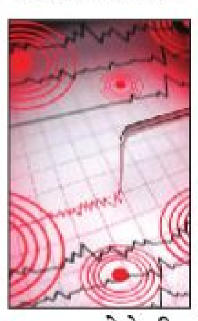

इटियाथोक क्षेत्र के इटहिया नवीजोत गांव के आसपास बताया गया है।सुबह-सुबह अचानक धरती में कंपन महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि राहत की बात यह रही कि अब तक किसी प्रकार की धनहानि या जनहानि की सूचना नहीं मिली है।

17वीं मंजिल से बेकरी मालिक ने लगाई छलांग

सोलापुर। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक समय मशहूर रही मुल्तानी बेकरी के मालिक द्वारा आत्महत्या

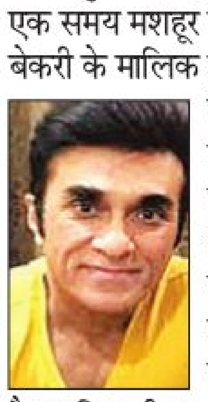

किए जाने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। व्यक्ति की पहचान 60 वर्षीय सुनील सदारंगानी के रूप में हुई है। उन्होंने पनाश अपार्टमेंट की 17वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। पुलिस पड़ताल कर रही है।

सबरीमाला में सोना गायब, एक्टर को समन

सबरीमाला। सोने की चोरी के मामले में जांच जारी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया

कि प्रवर्तन निदेशालय ने चोरी के मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए एक्टर जयराम को समन भेजा है। एजेंसी कथित मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को भी समन भेजने की तैयारी कर रही है। वे बेल मिलने के बाद जेल से बाहर आए हैं।

जालंधर में आप नेता ओबेरॉय की हत्या

जालंधर। पंजाब के जालंधर में गुरुद्वारा साहिब के बाहर आप नेता लक्की ओबरॉय की गोली मारकर

हत्या कर दी गई है। सुबह-सुबह गोलियों की आवाज से इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात शुक्रवार सुबह उस समय हुई जब लक्की ओबरॉय मॉडल टाउन में गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेककर लौट रहे थे। बदमाशों ने आठ-दस राउंड फायरिंग की।

एयर इंडिया का यह कायाकल्प टेस्ट जैसा

नई दिल्ली। एअर इंडिया का कायाकल्प अब किसी क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें दिन की सुबह जैसा है,

जहां खेल निर्णायक मोड़ पर होता है। एयर लाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन ने एयरलाइन की मौजूदा स्थिति को बयां करने के लिए क्रिकेट की यह दिलचस्प उपमा दी है।

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खरगे ने लगाया आरोप

प्रधानमंत्री का मनोबल टूट चुका, वे राहुल के सवालों से डरे हैं सदन में ही नहीं बैठते

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी एपस्टीन फाइल आने को लेकर विचलित हैं, इसी कारण उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपने घुटने टेक दिए और भारतीय किसानों के हितों की बलि दे दी। खरगे ने कहा कि ट्रेड डील से अमेरिकी किसान अमीर और भारतीय किसान गरीब होंगे, जिस पर अमेरिका की कृषि मंत्री ने खुश होकर कहा है कि इससे अमेरिका के पास खूब पैसा आएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय संबोधन पर तीखा पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे ₹स्तरहीन₹ और 'झूठ से भरा' बताया। राज्यसभा में प्रधानमंत्री के 97 मिनट के भाषण को तथ्यों से परे बताते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के पास विपक्ष के सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रधानमंत्री के भाषण पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उनकी स्तरहीन बातों का जवाब देना जरूरी है क्योंकि झूठी बातों को दोहराना उनका पुराना काम रहा है। खरगे ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का मनोबल टूट चुका है और वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सवालों से इस कदर डरे हुए हैं कि सदन में बैठने से कतराते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार संसद को जानबूझकर नहीं चलाना चाहती और लगातार संसद ठप होना लोकतंत्र की विफलता है। इंटेलिजेंस इनपुट के बहाने पीएम के लोकसभा में न आने पर खरगे ने पूछा कि अगर सरकार की इंटेलिजेंस इतनी ही चौकस है, तो पुलवामा हमला क्यों हुआ? देश में दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर हो रही लिंचिंग को इंटेलिजेंस क्यों नहीं रोक पाती?

पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब को लेकर खरगे ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब यह किताब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, तो रक्षा मंत्री और गृह मंत्री संसद में यह क्यों कह रहे हैं कि किताब प्रकाशित ही नहीं हुई? खरगे ने इसे संसदीय विशेषाधिकार का हनन बताते हुए कहा कि राहुल गांधी द्वारा उठाए गए तथ्यों से सरकार घबरा गई है। उन्होंने कहा कि जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया, तो सरकार को मिर्ची लग गई और तथ्यों का जवाब देने के बजाय व्यक्तिगत हमले किए गए।

सिख समुदाय के अपमान वाले प्रधानमंत्री के बयान को खरगे ने खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सिखों का पूरा सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा डॉ. मनमोहन सिंह को दो बार प्रधानमंत्री बनाना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने याद दिलाया कि मोदी ने खुद डॉ. मनमोहन सिंह के लिए 'रेनकोट पहनकर नहाने' जैसी अभद्र टिप्पणी कर सिखों का अपमान किया था। उन्होंने आगे कहा कि सदन के बाहर दो लोगों के बीच दोस्ताना बातचीत को सिखों का अपमान बताया जा रहा है जबकि प्रधानमंत्री मोदी न सिखों का आदर करते हैं, न दलितों का और न ही आदिवासियों का। कांग्रेस अध्यक्ष ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा स्थापित किए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 'दिवाला निकालने वाले कारखाने' कहे जाने को देश के गौरवशाली इतिहास का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि नेहरू जी के शासन में एचएमटी, एचएएल और भेल जैसे संस्थानों ने देश के औद्योगिक विकास की नींव रखी, लेकिन मौजूदा सरकार उन्हें खत्म करने का इरादा रखती है। खरगे ने भाजपा को दलित विरोधी बताते हुए यह भी याद दिलाया कि 2014 में भाजपा सरकार चाहती तो अपने विवेकाधीन अधिकारों का इस्तेमाल कर उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।

राज्यसभा में प्रधानमंत्री के भाषण पर जयराम रमेश का तीखा हमला

नई दिल्ली (हरिभूमि ब्यूरो)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संचार प्रभार जयराम रमेश ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री के हालिया भाषण को लेकर तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुवार शाम के भाषण ने एक बार फिर यह उजागर कर दिया कि उनके भीतर कितनी गहरी असुरक्षा, पूर्वाग्रह और कड़वाहट भरी हुई हैं। प्रधानमंत्री लगातार झूठ फैलाते रहे और उनके वक्तव्य में विष और नकारात्मकता साफ झलकती रही। रमेश ने प्रधानमंत्री के 97 मिनट लंबे भाषण को 'दयनीय' करार देते हुए कहा कि इसे दयनीय कहना भी बहुत हल्का आकलन होगा। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री अपनी ही निजी नफरतों के कैदी बन चुके हैं और उन्होंने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए किसी भी गंभीर सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री चाहे जितनी बार स्वयं को महान साबित करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा करने से यह और स्पष्ट होता जाता है कि वे न तो अच्छे व्यक्ति हैं और न ही कभी हो सकते हैं।

ऑपरेशन सिंदूर और विदेश नीति पर सवाल

जयराम ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस समय वाशिंगटन डीसी में बैठे प्रधानमंत्री के 'अच्छे मित्र' लगातार यह दावा कर रहे हैं कि 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने में उन्होंने हस्तक्षेप किया था। यह दावा अब बार-बार दोहराया जा रहा है और इसकी संख्या 'शतक के करीब' पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री इस गंभीर मुद्दे पर पूरी तरह मौन हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि जिस तरह 19 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख में बीस से अधिक भारतीय जवानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री ने चीन को कथित 'क्लीन चिट' दी थी और बाद में इस विषय पर चुप्पी साध ली थी, वही स्थिति अब भी देखने को मिल रही है।

संसद में जवाबदेही का मुद्दा

जयराम ने कहा कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और यहां प्रधानमंत्री से गंभीर सवालों के स्पष्ट जवाब अपेक्षित होते हैं। लेकिन राज्यसभा में दिए गए हालिया भाषण में प्रधानमंत्री ने आलोचनाओं और सवालों का सामना करने के बजाय केवल आरोप-प्रत्यारोप और आत्मप्रशंसा का रास्ता अपनाया।

8 वर्ष बाद परिणाम, 1711 पदों पर 39 का चयन

हरियाणा के युवाओं से एचपीएससी ने फिर धोखा कियाः कुमारी सैलजा

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) की भर्ती प्रणाली पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि वर्ष 2019 में निकली स्नातकोत्तर शिक्षक (कंप्यूटर साइंस) के 1711 पदों की भर्ती का परिणाम 2026 में आना और उसमें भी सिर्फ 39 अभ्यर्थियों का चयन होना हरियाणा के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। कुमारी सैलजा ने कहा कि आठ वर्षों तक हज़ारों युवाओं को उम्मीद में बाँधे रखना और अंत में उन्हें अयोग्य घोषित कर देना, उनकी मेहनत, आत्मसम्मान और भविष्य, तीनों पर सीधा हमला है। इस दौरान भर्ती के नियम बार-बार बदले गए, मानदंडों में फेरबदल किया गया और परीक्षा पद्धति में लगातार बदलाव किए गए, जिससे अभ्यर्थी भ्रम में रहे। इसी बीच सैकड़ों युवा आयु सीमा पार कर चुके हैं। उन्होंने सवाल किया इस नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा।

उन्होंने कहा कि हाल में घोषित असिस्टेंट प्रोफेसर की मुख्य परीक्षा के नतीजे भी भर्ती व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर करते हैं। सामान्य वर्ग में केवल 336 अभ्यर्थियों को पास किया गया, जबकि नियमों के अनुसार 2020 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना चाहिए था। आरक्षित वर्ग के साथ तो और भी बड़ा अन्याय हुआ जहाँ 1016 के स्थान पर मात्र 166 अभ्यर्थियों को ही पास किया गया। जिन अभ्यर्थियों को एसकेटी परीक्षा में पास किया गया उनमें से 80 प्रतिशत से भी अधिक अभ्यर्थी बाहर के यानी हरियाणा से दूसरे राज्यों के हैं। कई सब्जेक्ट में तो हरियाणा के मात्र 8 प्रतिशत छात्र ही पास किए गए हैं। यह हरियाणा के युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अंग्रेजी विषय में स्थिति अत्यंत चौंकाने वाली है। आरक्षित वर्ग के लिए 301 पद थे, लेकिन केवल 16 अभ्यर्थियों को पास किया गया और 285 पद खाली छोड़ दिए गए। अनुसूचित जाति की ओएससी व डीएससी श्रेणियों के लिए 120 पदों में से केवल 3 अभ्यर्थी पास हुए। कुल 613 अंग्रेजी पदों के विरुद्ध मात्र 151 अभ्यर्थी ही योग्य घोषित किए गए। सामान्य वर्ग में भी 502 पदों के सामने केवल 336 अभ्यर्थियों को पास किया गया, जबकि 1004 अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए था।

कुमारी सैलजा ने कहा कि एएमओ और पीजीटी की भर्तियों में भी 35 प्रतिशत की कठोर सीमा लगाकर हजारों अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से बाहर कर दिया गया, जिससे अधिकांश पद खाली रह गए। यह स्पष्ट करता है कि समस्या युवाओं की योग्यता में नहीं, बल्कि भर्ती प्रक्रिया की खामियों और मनमानी में है। उन्होंने मांग की कि विषय ज्ञान परीक्षा में कुल पदों के कम से कम दो गुना अभ्यर्थियों को पास कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए, सभी विज्ञापित पद भरे जाएँ और पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जाँच करवाई जाए।

भाजपा-एआईएमआईएम ने मिलाया हाथ

अमरावती में भाजपा के तेजवानी बने महापौर, सचिन उपमहापौर

अमरावती। महाराष्ट्र की अमरावती महानगरपालिका के मेयर चुनाव में राजनीति के अप्रत्याशित समीकरण सामने आए हैं। भाजपा की कट्टर विरोधी मानी जाने वाली एआईएमआईएम की पार्षद मीरा कांबले ने ऐन वक्त पर भाजपा उम्मीदवार श्रीचंद तेजवानी के पक्ष में मतदान किया। इससे भाजपा के श्रीचंद तेजवानी अमरावती के मेयर निर्वाचित हो गए। उपमहापौर पद के लिए भी चुनाव हुआ, जिसमें युवा स्वाभिमान पार्टी के सचिन भेंडे को उपमहापौर चुना गया।

सीएम उमर का बजट में ऐलान

यहां 554 स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन, 200 ई-बसें चलेंगी

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को केंद्र

शासित प्रदेश के लिए 1.13 लाख करोड़ का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय योजना का मकसद केंद्र शासित प्रदेश में स्थायी विकास, सामाजिक सद्भाव और आर्थिक समृद्धि के लिए एक मजबूत नींव रखना है।अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में 2आयुष अस्पताल की घोषणा की। राजौरी, बारामूला और डोडा में कैथ लैब व उरी और पुंछ में इमरजेंसी अस्पताल खोले जाएंगे। एम्स कश्मीर 2026 में शुरू किए जाने का ऐलान किया गया। सीमावर्ती जिलों के लिए बुलेट प्रूफ एंबुलेंस सेवा भी शुरू होगी। 554 स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने लक्ष्य रखा कि 200 नई ई-बसें चलाई जाएंगी। नए कल्चरल सेंटर बनाए जाएंगे। नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए कठुआ और हंदवाड़ा बायोटेक पार्क को फिर से शुरू किया जाएगा। किसानों को भी सुविधाएं दी।

दिल्ली में खुला महाराजा लाउंच

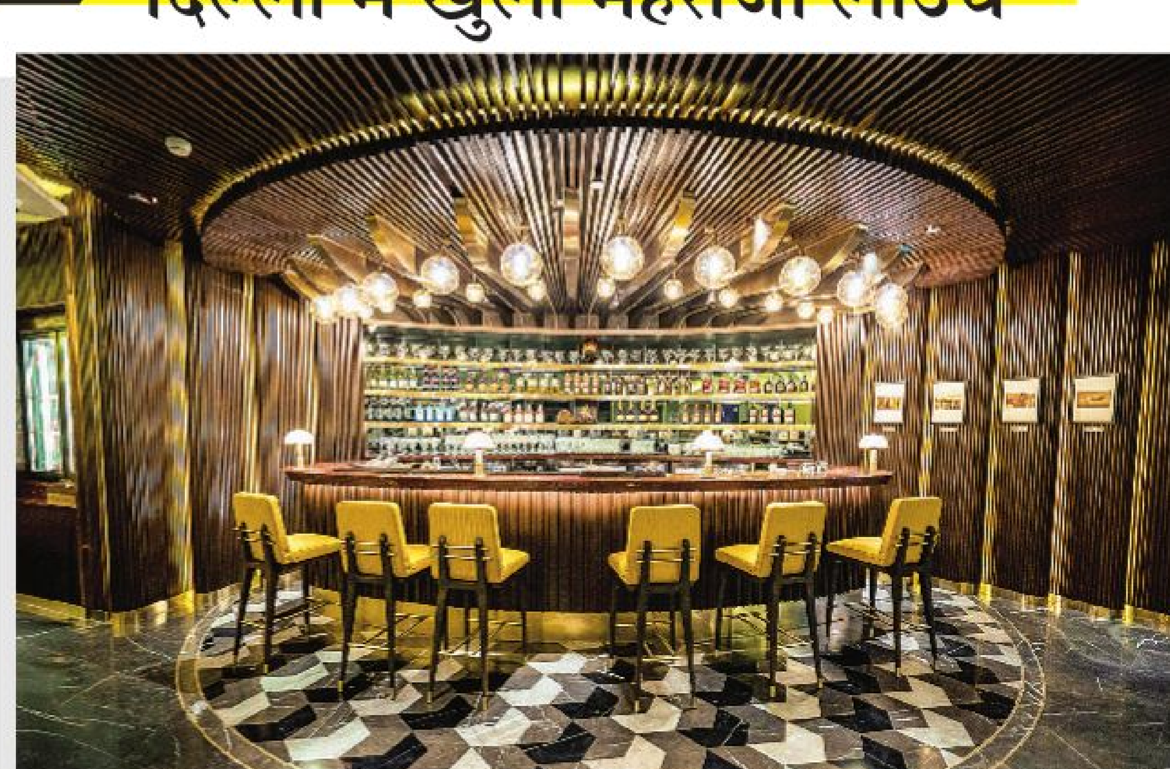

नई दिल्ली। दिल्ली हवाई अड्डे पर एयर इंडिया द्वारा खोला गया 'महाराजा लाउंज' का एक दृश्य।

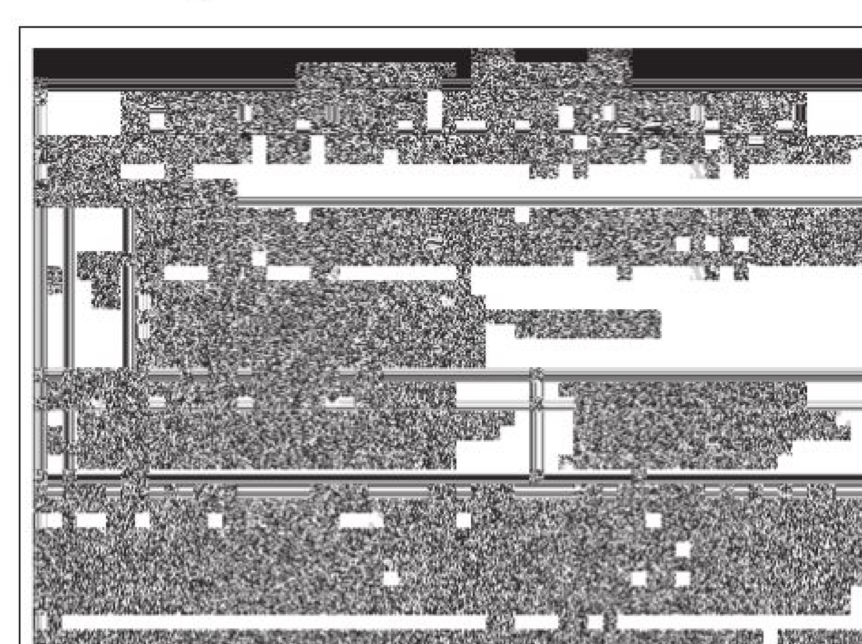

होली के निकट आने पर लोगों की आवाजाही बढ़ी

रेलवे चलाएगा 1410 स्पेशल ट्रेन, यूपी-बिहार होंगे लाभान्वित

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

होली का त्योहार नजदीक आते ही देशभर में यात्रियों की आवाजाही तेज होने लगी है। रंगों के इस पर्व को मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घरों की ओर रवाना होंगे। ऐसे में रेलवे ने स्टेशन पर बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने खास तैयारी की है। रेलवे ने ऐलान किया है कि होली 2026 के दौरान रिकॉर्ड 1410 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर इन ट्रेनों की संख्या 1500 तक बढ़ाई जा सकती है। रेलवे ने साल 2025 में होली के लिए कुल 1144 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया था। रेल मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय रेल हर बड़े त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सुचारू परिचालन के लिए लगातार प्रतिबद्ध है।

जरूरत पड़ने पर ट्रेनों की संख्या 1500 तक बढ़ाई जाएगी

पूर्व मध्य रेलवे 285 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा

रेल मंत्रालय ने जोन के हिसाब से होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन तय किया है। इसमें पूर्व मध्य रेलवे सबसे आगे है। यहां से 285 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। इसके बाद पश्चिम रेलवे पश्चिमी रूटों पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए 231 ट्रेन चलाए जाने की योजना है। मध्य रेलवे की ओर से 209 होली स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। दक्षिण मध्य रेलवे कुल 160 ट्रेनों का संचालन करेगा। उत्तर रेलवे 108 और उत्तर पश्चिम रेलवे 71 स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना पर काम कर रहा है।

बाकी जोन में भी बढ़ेंगी सुविधाएं

बाकी जोन के लिए भी स्पेशल ट्रेनों का प्लान तैयार किया है। दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा 47 ट्रेनें चलाई जाएंगी। पश्चिम मध्य रेलवे ने 43 ट्रेन चलाएगा।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा

सिलीगुड़ी रेलवे टनल होगी नॉर्थईस्ट कनेक्टिविटी के लिए वरदान

गुवाहाटी। असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर प्रस्तावित अंडरग्राउंड रेलवे टनल का स्वागत किया। उन्होंने इसे एक

गेम-चेंजिंग पहल बताते हुए कहा कि इससे नॉर्थईस्ट और देश के बाकी हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित होगी। यह रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूती देगा। यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भर रहा है।

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए U/s 84 BNSS

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त नाम **नाजिम पुत्रः** निज़ामुदीन **पताः** गली नंबर 12, बी ब्लॉक, कादी विहार, दिल्ली ने **e-FIR No. 749/2022 U/s 380/411 IPC स्वरूप नगर, दिल्ली,** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **नाजिम** मिल नहीं रहा हैं और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **नाजिम** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा हैं)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **e-FIR No. 749/2022 U/s 380/411 IPC थानाः स्वरूप नगर, दिल्ली,** के उक्त अभियुक्त **नाजिम** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **21.05.2026** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
श्रीमती ज्योति नैन
जेएमएफसी–02, कमरा नंबर–6
रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

DP/1599/ON/2026
(Court Matter)

प्रेरणा

हम बड़ी बातों और बड़े कार्यों से ही श्रेष्ठ बनते हैं।
-कन्फ्यूशियस

संपादकीय

नई ट्रेड डील्स के बाद अब हमारे सामने बड़े अवसर हैं

मात्र कुछ घंटों के अंतराल में ईयू और यूएस से नए ट्रेड-संबंध भारत को मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, बौद्धिक क्षमता और सामरिक सामर्थ्य के क्षेत्र में भी असाधारण आयाम देने वाले हैं। साथ ही भारत जरूरत से ज्यादा पैदा होने वाले अपने गेहूं, चावल और चीनी को इन दोनों ट्रेड ब्लॉक्स को निर्यात कर सकता है। हां, मैन्युफैक्चरिंग में वही उत्साह दिखाना होगा, जो चीन ने 1990-2020 तक के तीन दशकों में दिखाया था। उधर आईटी (सेवा और मैन्युफैक्चरिंग) के क्षेत्र में भी तमाम यूरोपीय व अमेरिकी कंपनियां भारत में दिलचस्पी लेने लगी हैं क्योंकि युवा इंजीनियर्स का बड़ा वर्ग उद्योग-सक्षम है और अपेक्षाकृत कम वेतन पर उपलब्ध है। लेकिन सेमी-कंडक्टर निर्माण के लिए बिजली और पानी की असाधारण जरूरत पूरी करनी होगी। इसके लिए एसएमआर (स्माल मॉड्यूलर रिएक्टर्स) लगाने के लिए कानून लाना अच्छी पहल है। यूएस से डील के बाद ऐसे रिएक्टर्स की जरूरत पूरी हो सकती है। सामरिक क्षेत्र में भी रूस के अलावा फ्रांस और जर्मनी नई हथियार-प्रणाली (लड़ाकू विमान और पनडुब्बियों के रूप में) दे सकते हैं और यह भी भारत के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के वादे के साथ। अगर रूस से तेल आयात कम भी करें तो हमारे रक्षा कवच निर्माण में उस देश की क्षमता अतुलनीय है। ऐसे अवसर किसी देश के विकास के इतिहास में कम ही आते हैं, जैसे आज हमारे समक्ष हैं।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

रामराज्य किस सुव्यवस्था का नाम था, यह मानस में दिखेगा

जिस रामराज्य को तुलसीदास जी ने आदर्श माना, आज वही व्यंग्य में अव्यवस्था का प्रतीक हो गया। अगर कहीं बिगड़ी हुई व्यवस्था हो तो लोग कहते हैं कि सब रामराज्य चल रहा है। लेकिन रामराज्य किस सुव्यवस्था का नाम था, यह रामचरितमानस में दिखेगा। जब पिछले दिनों दुबई में पारम्परिक रूप से मैंने भागवत कथा की तो चकित हुआ। तभी एक भारतीय भाई ने टिप्पणी की कि रामराज्य क्या है, यह देखना हो तो दुबई में देखो। मुझे बिलकुल सही लगा। हर बात कायदे में है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह सारे अवसर दे रहा है। पूरी दुनिया में युवाओं की मानसिक जीवनशैली बड़ी पेचीदा है, लेकिन उसे यहां कायदे में देखा जा सकता है। यहां का वातावरण ऐसा है कि मजे कर लो सारे, लेकिन बदतमीजी जरा भी नहीं चलेगी। हर व्यवस्था की हर कार्यवाई पैनिक गतिविधियों से गुजरती दिखती है। यहां कथा करने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि धर्म का दबाव तो यहां है, लेकिन आतंक नहीं है। यही तो रामराज्य की कल्पना है।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

दूरदृष्टि • धीरे-धीरे तानाशाही की ओर बढ़ रहा यूएस

अमेरिका को आखिर किस दिशा में लेकर जा रहे हैं ट्रम्प?

सत्तावाद

डेरोन एसमोगलु
अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता व एमआईटी में प्रोफेसर

ट्रम्प की रणनीतियों के चलते यह समझना मुश्किल है कि अधिनायकवाद की ओर अमेरिका की फिसलन में निर्णायक मोड़ कब आ सकता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि यही इस रणनीति का उद्देश्य है- लोगों के अधिकारों और संस्थागत नियंत्रण पर धीरे-धीरे अतिक्रमण कर लेना। लेकिन हम मान सकते हैं कि मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) एजेंटों द्वारा दो अमेरिकी नागरिकों की हत्या शायद वही निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है।

सत्तावादी सरकारों की एक प्रमुख पहचान यह होती है कि वे अपने विरोधियों के विरुद्ध अत्यधिक बलप्रयोग करने पर आमादा हो जाती हैं। यों तो तकरीबन हर सरकार पुलिसिंग के जरिए किसी न किसी रूप में दमन के उपाय अपनाती ही है, लेकिन इसकी स्पष्ट सीमाएं भी होती हैं। मसलन, ब्रिटेन की सरकार कुछ स्थानों से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए मामूली बलप्रयोग कर सकती है। लेकिन यह कल्पना करना भी असंभव है कि ब्रिटेन में पुलिस अंधाधुंध तरीके से प्रदर्शनकारियों की हत्या कर देगी, जैसा कि अमेरिका में हुआ है। अरब स्प्रिंग के दौरान जब विरोध-प्रदर्शन शुरू हुए थे, तब बशर अल-असद की हिंसक प्रतिक्रिया ने किसी को भी चकित नहीं किया। क्योंकि अधिकांश लोग यह जानते और समझते हैं कि अधिनायकवादी सरकारें विपक्ष, स्वतंत्र मीडिया और नागरिक समाज के अन्य स्तम्भों के विरुद्ध इसी तरह का बलप्रयोग करती हैं।

लोकतांत्रिक या व्यापक रूप से गैर-अधिनायकवादी समाजों में किसी भी प्रतिरोध के विरुद्ध इस प्रकार के हिंसात्मक दमन को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अव्वल तो खुद सरकार के दूसरे विभागों और सिविल सोसायटी की ओर से इसका कड़ा विरोध किया जा सकता है। दूसरे, सरकार यह भी सुनिश्चित नहीं कर सकती कि उसके सुरक्षा बल ऐसे आदेश का पालन करेंगे ही। मसलन, ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान ही अमेरिकी सैन्य नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया था कि वे ऐसे आदेशों को नहीं मानेंगे।

लेकिन आईसीई ने 2025 के दौरान अपने विस्तार को काफी बढ़ाया है और तमाम संकेतों से लगता है कि उसने ऐसे युवा कर्मियों को भर्ती किया है जो ट्रम्प के एजेंडे के प्रति सहानुभूति रखते हैं। उन्हें ऐसे तौर-तरीकों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है, जो पहले किसी संघीय एजेंसी के लिए असम्भव माने जाते थे। न्याय विभाग ने भी आईसीई की अवैध मानी जाने वाली कार्रवाइयों के लिए अटूट समर्थन दिखाया है, यहां तक कि उन्हें जांच के दायरे में लाने से भी इनकार किया है। मिनेसोटा में हुई घटनाओं का प्रतीकात्मक महत्व निर्विवाद है। आईसीई दो निर्दोष नागरिकों की हत्या कर चुका है : रेने गुड, तीन बच्चों की एक मां, जिन्हें अपने बेटे को स्कूल छोड़ आने के बाद गोली मार दी गई, और एलेक्स प्रेट्टी, एक गहन चिकित्सा नर्स, जो आईसीई के एक छापे की रिकॉर्डिंग कर रही थीं। ये संघीय एजेंट अकसर उनकी गतिविधियों को दर्ज करने वाले विरोधियों को धमकाते हैं और उनसे हिंसात्मक तरीकों से निपटते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रम्प प्रशासन ने आईसीई एजेंटों को व्यावहारिक रूप से प्रतिरक्षा प्रदान करके उन्हें अपनी हिंसात्मक रणनीतियां तेज करने की हरी झंडी दे दी है।

यदि इस हिंसा पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो यह वास्तव में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह उन अन्य सुरक्षा बलों के लिए एक नजीर कायम कर देगी, जो ट्रम्प के अधिक निकट हैं, ताकि वे किसी भी प्रकार के विरोध-प्रदर्शन के विरुद्ध निरंकुश बलप्रयोग कर सकें। ऐसी स्थिति में अधिनायकवादी शासन की ओर फिसलन को पलटना कठिन हो जाएगा, क्योंकि बढ़ते दमन के सामने नागरिक समाज निष्क्रिय होता जाएगा और लोकतांत्रिक मानदंड धीरे-धीरे क्षीण होते चले जाएंगे।

> **सत्तावादी सरकारों की एक प्रमुख पहचान यह है कि वे अपने विरोधियों के विरुद्ध अत्यधिक बलप्रयोग करने पर आमादा हो जाती हैं। विपक्ष, मीडिया और नागरिक समाज के अन्य स्तम्भों के विरुद्ध दमन की नीति अपनाई जाने लगती है।**

पहले ही, सरकार की वे दो शाखाएं जिन्हें राष्ट्रपति की शक्ति पर अंकुश लगाना चाहिए था- कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट- ट्रम्प के एजेंडे के प्रति असाधारण रूप से सहानुभूतिपूर्ण साबित हुई हैं। उतना ही महत्वपूर्ण यह है कि संस्थागत संतुलन भी कमजोर पड़ चुका है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति को अपने सहयोगियों और वफादारों को निर्णायक पदों पर नियुक्त करने की खुली छूट मिल गई है। ट्रम्प का उद्देश्य एक ऐसे निरंकुश, साम्राज्यवादी राष्ट्रपति पद का निर्माण करना है जिस पर प्रभावी नियंत्रण न हो- और यही वह रास्ता है जिसके जरिये अधिनायकवाद को संस्थागत रूप दिया जाता है। हंगरी से लेकर इक्वाडोर, मैक्सिको, निकारागुआ, तुर्की और वेनेजुएला तक के समकालीन उदाहरण इस प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं।

(@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)

मुद्दा • डेटा सुरक्षा कानून लागू नहीं हो पा रहा है

वॉट्सएप की डेटा चोरी पर हम कब सख्त रवैया अपनाएंगे?

डिजिटल

विराग गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट के वकील
viraggupta@hotmail.com

सीजेआई सूर्यकांत ने वॉट्सएप को फटकार लगाते हुए कहा है कि डेटा चोरी से ग्राहकों को टारगेट करके विज्ञापन भेजे जा रहे हैं। तीन जजों की पीठ ने कहा कि लोगों के निजी डेटा के व्यावसायिक इस्तेमाल को रोकने का जब तक हलफनामा नहीं मिलेगा, तब तक वॉट्सएप की अपील पर सुनवाई नहीं होगी। वॉट्सएप मामले पर सुनवाई और फैसला डिजिटल भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकता है। इससे जुड़े 6 पहलुओं को समझना हमारे लिए जरूरी है।

1\. भारत में मेटा की तीन कंपनियों फेसबुक के 58 करोड़, इंस्टाग्राम के 48 करोड़ और वॉट्सएप के लगभग 85 करोड़ ग्राहक हैं। देश में 92% कारोबारी और 89% स्मार्टफोन यूजर्स वॉट्सएप्प का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2016 के बाद मेटा की तीनों कंपनियां करोड़ों ग्राहकों के डेटा को परस्पर साझा करने के साथ व्यावसायिक इस्तेमाल से खासा मुनाफा कमा रही हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 2021-22 में दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दिया था कि वॉट्सएप मामले पर सुनवाई कॉम्पिटिशन कानून के अनुसार हो रही है, जिसका संविधान के अनुच्छेद 21 और निजता के अधिकार से कोई वास्ता नहीं है।

2\. सीसीआई और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि निःशुल्क सेवा देने वाले वॉट्सएप की कमाई विज्ञापन से होती है और यूजर्स ही उनका प्रोडक्ट हैं। अमेरिका में दायर क्लास एक्शन स्यूट मुकदमे के अनुसार वॉट्सएप में चैट और डेटा सुरक्षित नहीं होने की वजह से टारगेटेड विज्ञापन आते हैं। भारत का डेटा विदेश ले जाने की वजह से पब्जी और टिकटॉक जैसे कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा था। अमेरिकी टेक कंपनियां हमारे डेटा को खुलेआम देश-विदेश में बेच रही हैं, उसके बावजूद केंद्र सरकार संसद से 2023 में पारित डेटा सुरक्षा कानून को लागू नहीं कर रही।

3\. मेटा ने 2025 में दुनिया में 200 अरब डॉलर की आमदनी की थी। इसमें से लगभग 196 अरब डॉलर की आमदनी सिर्फ विज्ञापन से थी। मेटा की प्रति ग्राहक औसत आमदनी 57 डॉलर है। यूजर्स की संख्या के अनुसार वॉट्सएप को भारत से लगभग चार लाख करोड़ रु. की आमदनी होती है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बाजार भारत में मेटा इंडिया ने पिछले साल सिर्फ 3792 करोड़ की आमदनी दिखाई। भारत में लगभग 44 लाख करोड़ की आमदनी टैक्स से होती है, जो जीडीपी की 11.2% है। जबकि विकसित देशों के संगठन ओईसीडी में जीडीपी का 34% टैक्स आमदनी से आता है। मेटा से डेटा कारोबार पर जीएसटी और अन्य टैक्सों की वसूली हो तो बजट घाटा कम होने के साथ स्वदेशी अर्थव्यवस्था का विकास होगा।

4\. बेशुमार डेटा के दम पर मेटा व्यापार, डिजिटल विज्ञापन, यूपीआई, पेमेंट बैंकिंग और एआई के क्षेत्र में भी वर्चस्व स्थापित कर रही है। वॉट्सएप से 60 फीसदी से ज्यादा फ्री वॉइस कॉल की वजह से टेलीकॉम कंपनियों की माली हालत बिगड़ रही है। वॉट्सएप कॉल में केवाईसी नहीं होने से साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। लेकिन मोबाइल कंपनियों की अनेक मांगों और संसदीय समिति की रिपोर्ट के बावजूद वॉट्सएप को टेलीकॉम कानून 2023 के दायरे में नहीं लाया गया।

5\. मेटा की कंपनियों पर यूरोप में जीडीआर के सख्त डेटा सुरक्षा कानून के उल्लंघन पर 12000 करोड़, डिजिटल मार्केटिंग एक्ट के उल्लंघन पर 2000 करोड़ और नाबालिग बच्चों के डेटा के गलत इस्तेमाल पर 4000 करोड़ रु. का जुर्माना लगा था। अमेरिका में फेडरल ट्रेड कमीशन ने कैम्ब्रिज मामले में 2019 में मेटा पर 5 अरब डॉलर यानी 50 हजार करोड़ का जुर्माना लगाया था लेकिन भारत में सीसीआई ने मेटा पर 213 करोड़ का मामूली जुर्माना लगाया, जिसे वापस हासिल करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है।

> **जजों ने कहा है कि नियमों का पालन नहीं करने पर वॉट्सएप को भारत से चले जाना चाहिए। लेकिन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता के दावों के बावजूद जनता, कारोबार, अदालतें और सरकार वॉट्सएप पर निर्भर हैं।**

6\. जजों ने कहा है कि नियमों का पालन नहीं करने पर वॉट्सएप को भारत से चले जाना चाहिए। लेकिन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता के दावों के बावजूद जनता, कारोबार, अदालतें और सरकार पूरी तरह से वॉट्सएप पर निर्भर हैं। डेटा चोरी रोकने और कारोबार पर पूरा टैक्स वसूलने के लिए सुप्रीम कोर्ट से सख्त आदेश पारित हों तो संविधान के शासन की शान बढ़ने के साथ साइबर अपराधों में भारी कमी आएगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

7 फरवरी के अंक से विशेष अनुबंध के तहत सिर्फ दैनिक भास्कर में
इकोनॉमिस्ट ने कवर स्टोरी में दुनियाभर में प्रेस की फ्रीडम की स्थिति का विश्लेषण किया है। वहीं मैग्जीन ने गिरते डॉलर के कारणों व भविष्य पर भी प्रकाश डाला है।

The Economist

दैनिक भास्कर
अब आप इकोनॉमिस्ट के सभी आर्टिकल DB एप पर हर शनिवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

वर्ल्ड इन ब्रीफ

660 अरब डॉलर खर्च होंगे एआई पर इस साल

इस साल निवेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर करीब 660 अरब डॉलर खर्च करने जा रहे हैं। मार्केट को इस निवेश की खबर रास नहीं आई और निवेशकों की प्रतिक्रिया के चलते बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को बड़ी टेक कंपनियों वाला नैस्डैक इंडेक्स 1.59% गिर गया। वहीं एसएंडपी 500 में 1.23% की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर सॉफ्टवेयर शेयरों में गिरावट जारी रही, क्योंकि एंथ्रोपिक ने वित्तीय अनुसंधान करने के लिए डिजाइन किए गए अपने क्लाउड मॉडल का एक अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया।

नॉर्वे के पूर्व पीएम यागलैंड पर भ्रष्टाचार जांच शुरू

नॉर्वे की पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री और नोबेल समिति के पूर्व अध्यक्ष थोरब्योर्न यागलैंड के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी है। यह जांच जेफ्री एपस्टीन से उनके कथित संबंधों को लेकर की जा रही है। इस पर यागलैंड के वकील ने कहा है कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे। जांच के लिए पुलिस ने यह मांग की कि यागलैंड को एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के पूर्व प्रमुख के रूप में प्राप्त छूट को हटा दिया जाए, जिसे विदेश मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया। यौन अपराधों के मामलों में आरोपी ठहराए गए जेफ्री एपस्टीन की मौत के बाद उससे जुड़े दस्तावेज सामने आ रहे हैं।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

चिंता मीडिया को दबाने में सरकारें कानूनी और आर्थिक ताकतों का इस्तेमाल कर रहीं

50 फीसदी से ज्यादा देशों में प्रेस की आजादी खतरे में, अमेरिका ने रोकी स्वतंत्र विदेशी मीडिया की सब्सिडी

नवंबर 2024 में सर्बिया के एक रेलवे स्टेशन की कैनोपी गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई। इस घटना पर स्वतंत्र पत्रकारों ने रिपोर्टिंग की। लेकिन कुछ पत्रकारों को गुंडों ने पीटा, पुलिस खड़ी होकर देखती रही। सर्बिया के स्वतंत्र पत्रकार संघ के अनुसार 2025 में वहां पत्रकारों पर 91 शारीरिक हमले हुए। हमलावरों को सजा भी नहीं मिलती है।

सर्बिया ही नहीं दुनियाभर में मीडिया की आजादी घट रही है। रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट में प्रेस की स्वतंत्रता का वैश्विक औसत स्कोर 2025 में 55 से नीचे आ गया। 2014 में ये 100 में 67 पर था। दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में पत्रकारिता करने की स्थितियां कठिन या बहुत गंभीर हैं।

प्रेस फ्रीडम की इस गिरावट को गंभीरता से देखा जाना चाहिए, क्योंकि आलोचनात्मक पत्रकारिता (क्रिटिकल जर्नलिज्म) सत्ताधीशों की मनमानी पर नियंत्रण है। अगर ताकतवर लोगों को पता हो कि उनके गलत काम न तो उजागर होंगे और न ही प्रचारित, तो वे और ज्यादा करेंगे।

अमेरिकी सरकार पहले दुनियाभर में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खड़ी होती थी। वह अब ऐसा नहीं करती। ट्रम्प प्रशासन ने स्वतंत्र विदेशी मीडिया को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी। रेडियो फ्री एशिया जैसे सार्वजनिक आउटलेट्स बंद कर दिए हैं। ट्रम्प ने साफ कर दिया है कि वे सरकारों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर दबाव नहीं डालेंगे, जब तक वे वोक यूरोपीय न हों। अजरबैजान से एल साल्वाडोर तक मजबूत शासकों ने परेशान करने वाले पत्रकारों को जेल में डालने, डराने का मौका पकड़ लिया है, क्योंकि राजनयिक प्रतिक्रिया का डर नहीं रहा।

इकोनॉमिस्ट के 180 देशों के डेटा के विश्लेषण के मुताबिक मीडिया को दबाने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के बीच संबंध है। जनता को लूटने वाले राजनेता प्रेस को दबाते हैं, ताकि चोरी करना आसान हो जाए। विश्लेषण बताता है कि किसी देश में प्रेस की आजादी बहुत अच्छी स्थिति से गिरकर खराब स्थिति में आ जाए, तो वह ज्यादा भ्रष्ट बन सकता है। यह प्रक्रिया कई वर्षों में बढ़ती है, इसे मतदाता अगला चुनाव होने के बाद ही नोटिस कर पाते हैं। लोकलुभावन सरकारों में स्थिति और भी बदतर होती है। वे उन संस्थाओं को कुचलने की कोशिश करती हैं, जो उनके अधिकार सीमित करती हैं।

लोकतांत्रिक सरकारें पत्रकारिता को दबाने के लिए तीन तरह के हमले करती हैं- पहला, शाब्दिक हमला जिसमें पत्रकारों को देशद्रोही बताया जाता है। दूसरा, कानूनी, जिसमें मुकदमे, टैक्स रेड, गिरफ्तारी होती है। तीसरा, आर्थिक हमला जिसमें विज्ञापन और फंड रोककर मीडिया को कमजोर किया जाता है।

बड़ी गिरावट लोकतांत्रिक देशों में आ रही

मीडिया की आजादी में बड़ी गिरावट लोकतांत्रिक देशों में आ रही है। क्योंकि तानाशाही देशों में तो स्वतंत्र पत्रकारिता लगभग खत्म हो गई है। लोकतांत्रिक सरकारें आलोचना को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश नहीं करतीं। बल्कि वे खबर जुटाने वालों के लिए प्रोत्साहनों को इस तरह बिगाड़ देती हैं कि आम लोगों को सत्तारूढ़ पार्टी की भरपूर तारीफ सुनाई दे और असहमति की आवाज सिर्फ कभी-कभार की चीख जैसी रह जाए। मकसद है ताकतवरों को सत्ता में बनाए रखना और उनके दुरुपयोग की निगरानी कम करना।

महिला पत्रकारों पर भी हमले

जो लोग ताकतवरों को परेशान करते हैं, उनकी निजी जानकारी सार्वजनिक की जाती है, खासकर अगर वे महिलाएं हों। संयुक्त राष्ट्र के सर्वे में पाया गया कि 75% महिला रिपोर्टरों ने ऑनलाइन दुर्व्यवहार झेला और 42% को व्यक्तिगत रूप से परेशान किया गया या धमकी दी गई।

तुर्किये से तंजानिया तक में असर

सितंबर में तुर्किये सरकार ने कैन होल्डिंग नामक मीडिया समूह पर नियंत्रण कर लिया। तंजानिया में धांधली वाले चुनाव को कवर करने पर पत्रकारों को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं इंडोनेशिया में पत्रकारिता की गुणवत्ता पिछले पांच या छह वर्षों में आर्थिक दबाव के कारण गिर गई है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

मुद्रा आगे भी इसमें गिरावट के आसार

'डगमगाता डॉलर': प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले सालभर में 10% गिरा

पिछले 12 महीनों में अमेरिकी बाजारों ने मजबूती दिखाई है। एसएंडपी 500 इंडेक्स 14% बढ़ा है, क्योंकि निवेशक एआई में तेजी से पैसा लगा रहे हैं। अमेरिका की आर्थिक वृद्धि अब भी दुनिया में सबसे मजबूत मानी जा रही है। 10 साल की ट्रेजरी यील्ड 4.3% है, जो ट्रम्प के शपथ लेने के समय से भी कम है। लेकिन तस्वीर उतनी स्थिर नहीं है। जनवरी 2025 के बाद से डॉलर प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले 10% गिर चुका है। इसका असर यह हुआ कि विदेशी मुद्रा में अमेरिकी एसेट्स का प्रदर्शन कमजोर रहा। यूरो में देखें तो अमेरिकी शेयर पिछले एक साल में लगभग स्थिर रहे हैं।

डॉलर की गिरावट का एक कारण अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच ब्याज दरों का अंतर कम होना है। लेकिन चिंता की असली वजह अमेरिकी नीतियों की अनिश्चितता है। अप्रैल 2025 में ट्रम्प के लिबरेशन डे टैरिफ ऐलान के बाद बाजार में घबराहट फैली और निवेशक बॉन्ड, शेयर और डॉलर से पैसा निकालने लगे। ऐसी स्थिति पिछले 52 हफ्तों में सात बार बनी, जो पिछले दशक की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है। इससे संकेत मिलता है कि डॉलर आधारित एसेट्स की 'सेफ हेवन' छवि कमजोर हो रही है।

फेडरल रिजर्व के केविन वार्श ब्याज दरों में कटौती के पक्ष में एआई से उत्पादकता बढ़ने का तर्क दे रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि एआई बूम निवेश और खर्च बढ़ाकर महंगाई दबाव भी बढ़ा सकता है। अभी अमेरिका में मुद्रास्फीति 2.8% है, जो 2% लक्ष्य से ऊपर है। टैक्स कटौती और रिफंड से जीडीपी का 0.3% पैसा बाजार में आएगा। सुप्रीम कोर्ट टैरिफ अवैध ठहराता है तो जीडीपी के 0.5% तक रिफंड आ सकते हैं। इससे महंगाई तो बढ़ेगी ही डॉलर पर भी दबाव पड़ सकता है।

हालांकि डॉलर को सहारा ये है कि दुनिया में कोई मजबूत विकल्प नहीं है। ट्रेजरी या बॉन्ड जैसी लिक्विडिटी और सुरक्षा किसी अन्य बाजार में नहीं है। फिर भी विदेशी निवेशक अमेरिकी बॉन्ड से ज्यादा अमेरिकी शेयरों से दूरी बना सकते हैं। बिग मैक इंडेक्स के मुताबिक डॉलर अब भी कई मुद्राओं के मुकाबले अधिक मूल्यवान है, यानी गिरावट की गुंजाइश बनी हुई है।

विशेषज्ञों के अनुसार ट्रम्प की अस्थिर नीतियां डॉलर को दशकों बाद सबसे जोखिमपूर्ण दौर में ले जा रही हैं। यह चिंता सिर्फ अमेरिका की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की है, क्योंकि वैश्विक वित्त व्यवस्था अब भी काफी हद तक डॉलर पर टिकी है।

ट्रम्प के कदमों पर चढ़ता-उतरता है डॉलर

यह खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि डॉलर दुनिया की रिजर्व मुद्रा है और विदेशी निवेशकों के पास अमेरिका में संपत्ति अमेरिकी जीडीपी के 89% के बराबर है। इसी दौरान सोने की कीमत बढ़कर करीब 5,000 डॉलर प्रति औंस पहुंच गई है। ये एक साल में लगभग 75% की छलांग है। माना जा रहा है कि निवेशक डॉलर के अवमूल्यन और बड़े जोखिमों से बचने के लिए सोने की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रम्प ने 30 जनवरी को केविन वार्श को फेडरल रिजर्व का प्रमुख नामित किया। वार्श को अनुभवी और पहले सख्त मौद्रिक नीति समर्थक माना जाता है। उनके नाम से डॉलर में हल्की मजबूती आई और सोने में गिरावट दिखी, लेकिन राहत ज्यादा टिक नहीं सकी। पिछले महीने में ट्रम्प के ग्रीनलैंड को लेकर बयान के बाद डॉलर 1.5% गिरा और सोना 14% चढ़ गया।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

विज्ञान 30 अरब डॉलर की प्रस्तावित कटौती से नौकरियां, इकोनॉमी दांव पर थी

अमेरिकी कांग्रेस के दखल से रुकी साइंटिफिक बजट कटौती

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने 2025 में हजारों शोध अनुदान रद्द कर अरबों डॉलर की फंडिंग रोक दी थी। इससे कई प्रयोगशालाएं बंद हुईं, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने विदेश में अवसर तलाशने शुरू कर दिए। 2026 के बजट प्रस्ताव में प्रशासन ने फिर प्रमुख विज्ञान एजेंसियों के बजट को आधा करने की योजना रखी थी, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के फंड में 40% कटौती और उसके संस्थानों को 27 से घटाकर 8 करने का सुझाव शामिल था।

मगर कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सदस्यों ने मिलकर करीब 30 अरब डॉलर की प्रस्तावित कटौती खारिज कर दी। उन्होंने एनआईएच की संरचना बरकरार रखते हुए बजट 1% बढ़ा दिया। नेशनल साइंस फाउंडेशन, नासा तथा ऊर्जा विभाग के विज्ञान कार्यालय की फंडिंग भी पिछले स्तर पर ही रखी है।

कांग्रेस के सदस्यों के इन कदमों से लगता है कि उन्हें फंड में कटौती से होने वाले संभावित असर जैसे वैज्ञानिक और तकनीकी बढ़त कमजोर होना, नौकरियां खत्म होने के खतरे का अंदाजा हो गया है।

200 एजेंसियों में दखल

बीते एक साल में संघीय विज्ञान एजेंसियों में स्टाफ घटाया गया है। करीब 200 विशेषज्ञ समितियों को या तो बर्खास्त किया गया है या उनके काम में दखल दिया गया है। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के नियमित टीकाकरण की सिफारिश सूची को अचानक 13 से घटाकर 7 कर दिया है। इससे विवाद बढ़ा है। साइंटिफिक बजट को सीमित करने से स्थानीय स्तर पर अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

बदलाव

जापान में उभर रही हैं नई राजनीतिक पार्टियां

जापान में सत्ता लंबे समय से लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) के हाथ में रहती थी। विपक्षी राजनीति वामपंथ के इर्द-गिर्द घूमती थी। लेकिन अब देश का राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। 8 फरवरी को होने वाले निचले सदन के चुनाव मैदान में मौजूद 10 प्रमुख पार्टियों में से केवल तीन ही 2012 से पहले अस्तित्व में थीं, जबकि बाकी नई पार्टियां हैं या हाल में गठित हुई हैं। इन नई पार्टियों ने बदलाव को अपना मुख्य नारा बनाया है और वे सोशल मीडिया के जरिए तेजी से जनता तक पहुंच बना रही हैं।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

बिजनेस ब्रीफ

एमआरएफ का मुनाफा दोगुना बढ़ा, 692 करोड़

नई दिल्ली | टायर निर्माता एमआरएफ को दिसंबरी तिमाही में 692 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। यह 2024-25 की तीसरी तिमाही में 315 करोड़ के मुनाफे से 119% अधिक है। परिचालन आय 15% बढ़कर 8,050 करोड़ रु. हो गई। बीएसई पर शुक्रवार को एमआरएफ का शेयर 8.6% उछलकर 1.46 लाख रु. पार पहुंच गया। कंपनी ने प्रति शेयर 3 रुपए डिविडेंड की घोषणा की।

रुपए में 3 साल की सबसे बड़ी साप्ताहिक मजबूती

मुंबई | विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 31 पैसे कमजोर होकर 90.65 पर बंद हुआ। बावजूद इस पूरे हफ्ते में यह 128 पैसे (1.4%) मजबूत हुआ। यह जनवरी 2023 के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक रिकवरी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका से ट्रेड डील के ऐलान से रुपए पर छाए अनिश्चितता के बादल हटे हैं। आगे की चाल विदेशी निवेश पर निर्भर करेगी।

टाटा स्टील का लाभ 8 गुना बढ़ा, 2,688 करोड़

मुंबई | टाटा स्टील को 2025-26 की तीसरी तिमाही में 2,688.7 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। ये सालाना आधार पर 8 गुना से भी ज्यादा (723%) बढ़ोतरी है। 2024-25 की इसी अवधि में कंपनी का लाभ 326.64 करोड़ रु. था। लाभ में यह वृद्धि बेहतर मार्जिन के कारण आई, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही के 0.5% से 9 गुना बढ़कर 4.79% हो गया।

क्वीन के चित्र वाले सिक्के पर घिरा ऑस्ट्रेलियन मिंट

कैनबरा | रॉयल ऑस्ट्रेलियन मिंट ने ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के चित्र वाले सिक्के जारी किए। पर तस्वीर एलिजाबेथ से मेल नहीं खाने पर उसे आलोचना का शिकार होना पड़ा। ऑनलाइन नकारात्मक प्रतिक्रिया देने वाले एक व्यक्ति ने कहा, 'सिक्के पर छपी यह अब तक की सबसे खराब तस्वीर है।'

एनएसई बनाएगा देश का पहला कोल एक्सचेंज

मुंबई | नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के बोर्ड ने देश का पहला कोल एक्सचेंज बनाने की मंजूरी दे दी है। एनएसई इस पर 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यह एक्सचेंज कोल एक्सचेंज रूल्स 2025 के तहत बनेगा। अभी भारत का कोयला बाजार बिखरा है, जहां कीमतों का कोई तय मानक नहीं है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से कोयले की खरीद-बिक्री पारदर्शी होगी।

वीडीआईएस 2.0 • आयकर अधिनियम-25 में संशोधन, अघोषित आय पर बड़ी राहत

अघोषित आय घोषित करने पर 78% की जगह सिर्फ 39% टैक्स लगेगा

भास्कर एक्सपर्ट

सीए डॉ. अभय शर्मा
पार्टनर एबीएमएस एंड एसोसिएट्स

बजट 2026 के नए संशोधनों ने अघोषित आय को मुख्यधारा में लाने की प्रक्रिया को सरल और कम खर्चीला बना दिया है। केंद्र ने आयकर अधिनियम 2025 की धारा 195 में संशोधन करके अघोषित स्रोतों से होने वाली कमाई पर प्रभावी टैक्स 78% से घटाकर आधा यानी सिर्फ 39% कर दिया। इस संशोधन को एक तरह की 'स्थायी डिसक्लोजर स्कीम' माना जा रहा है। करदाता बिना किसी भारी जुर्माने के पुरानी अघोषित आय को उजागर करके भविष्य में संभावित आयकर विभाग की कार्रवाई से बच सकेंगे। अभी तक करदाता चाह कर भी ऐसी अघोषित आय अपने आयकर विवरणी में दर्शा नहीं पाता था। वजह यह थी कि आयकर अधिनियम की धारा 68 के तहत ऐसी अनएस्प्लेंड क्रेडिट यानी घोषित आय पर धारा 115बीबीई के तहत 78% की दर से टैक्स देय होता था। साथ ही, 271एएसी के तहत 10 फीसदी पेनल्टी भी लगती थी। इस बाधा को नए आयकर अधिनियम की धारा 195 में संशोधन करके दूर करने का प्रयास किया।

वो सबकुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है

मिस्टर लाल को कहीं से 10 करोड़ की नकद आय हुई। वह स्रोत का खुलासा नहीं करना चाहता है या स्रोत बताने में असफल

रहता है। बजट 2026 में हुए धारा 195 में संशोधन के बाद मिस्टर लाल ने इसमें से 5 करोड़ धनराशि को 1 अप्रैल 2026 को बैंक में जमा किया। वह टैक्स ईयर 2026-27 से संबंधित आईटीआर में इसे आयकर अधिनियम 2025 की धारा 104 के तहत अस्पष्टीकृत आय के रूप में पेश करता है।

इस पर उसे कितना कर देना होगा?

बजट में प्रस्तावित किया है कि ऐसी आय पर 30% टैक्स और 25% अधिभार लगेगा। यानी 7.5% और 4% का उपकर यानी 1.5% लगेगा। यानी कुल मिलाकर 39% टैक्स चुकाना होगा, जबकि इस संशोधन के पहले यह टैक्स दर 78% थी। यानी नए संशोधन के बाद लगभग आधे के आसपास ही टैक्स देनदारी बनेगी।

क्या इस कर के अतिरिक्त कोई पेनल्टी लग सकती है?

सीए कीर्ति जोशी कहते हैं कि अगर कोई शख्स ऐसी अघोषित आय को रिटर्न में नहीं दिखाता है और आयकर विभाग ऐसी अघोषित आय को पकड़ता है तो 200% पेनल्टी देनी होगी। सेस और सरचार्ज जोड़ लें तो यह राशि अघोषित आय से भी अधिक हो सकती है। साथ ही, अन्य कानूनी कार्रवाई भी चलेगी।

सरकार पहले वीडीआईएस स्कीम भी ला चुकी है

कई वर्षों पहले सरकार ने एक वॉलेंट्री डिसक्लोजर इनकम स्कीम शुरू की थी, जिसमें 30% टैक्स का भुगतान करके अघोषित आय को मुख्यधारा में बदलने का विकल्प दिया था। यह सिंगल ऑपर्च्युनिटी स्कीम थी। सरकार ने उस समय सुप्रीम कोर्ट में यह वचन भी दिया था कि ऐसी योजना कभी नहीं दोहराई जाएगी।

अपील के दौरान अब जुर्माने पर नहीं लगेगा ब्याज

- बजट में टैक्स से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं (पेनल्टी और मुकदमों) को सरल बनाने के लिए कई कदम हैं।

1. एक बार में समाधानः पहले टैक्स गणना का ऑर्डर आता था और फिर जुर्माने की कार्रवाई अलग से होती थी। करदाता को इन दोनों के खिलाफ अलग-अलग अपील करनी पड़ती थी, जिससे समय और पैसा दोनों बर्बाद होते थे। अब असेसमेंट और पेनल्टी की प्रक्रिया एक होगी।

2. जुर्माने के ब्याज से मुक्तिः अब जब तक आपकी अपील पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक जुर्माने की राशि पर ब्याज नहीं लगेगा। अपील खारिज हो जाती हैं, तब भी उस दौरान ब्याज माफ रहेगा। यह छूट सिर्फ जुर्माने के लिए है; जो मूल टैक्स है, उस पर ब्याज लगता रहेगा।

3. अपील करना सस्ताः पहले आप विभाग के फैसले के खिलाफ अपील करते थे तो कुल डिमांड का 20% हिस्सा जमा करके डिमांड पर स्टे लेना पड़ता था। अब 10% भी सिर्फ मूल टैक्स पर देना होगा। जुर्माने या ब्याज की रकम पर कोई स्टे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है।

प्रदूषण के मानदंड बदले

छोटी पेट्रोल कारों को अब नहीं मिलेगी छूट

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

केंद्र ने फ्यूल एफिशिएंसी और प्रदूषण के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब छोटी पेट्रोल कारों को दी जाने वाली प्रस्तावित छूट खत्म कर दी गई है। सितंबर 2025 के ड्राफ्ट में 909 किलो या उससे कम वजन वाली कारों को राहत देने का प्रस्ताव था। ज्यादातर कार कंपनियों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि इसका फायदा सिर्फ मारुति सुजुकी को मिलेगा, जिसकी देश के छोटी-कार बाजार में करीब 95% हिस्सेदारी है। इसके बाद ऊर्जा मंत्रालय ने नया ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें सभी कंपनियों के लिए नियम कड़े किए गए हैं। नए नियम अप्रैल 2027 से लागू होंगे और पांच साल तक प्रभावी रहेंगे। नए नियमों का पालन नहीं करने पर कंपनियों को प्रति कार करीब 50 हजार रुपए जुर्माना देना होगा।

2032 तक प्रदूषण 100 ग्राम प्रति किमी लाना लक्ष्यः सरकार ने अगले पांच साल में कार्बन उत्सर्जन को 114 ग्राम से घटाकर 100 ग्राम प्रति किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है। यदि मार्च 2032 तक इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 11% तक पहुंचती है, तो क्रेडिट सिस्टम की मदद से यह आंकड़ा 76 ग्राम तक आ सकता है।

ईवी, हाइब्रिड कारों पर क्रेडिटः कंपनियों को स्वच्छ ईंधन तकनीक अपनाने के लिए रिवॉर्ड और क्रेडिट सिस्टम लागू किया जाएगा। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, जो कंपनियां तय लक्ष्य से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेचेंगी, उन्हें 'क्रेडिट' मिलेगा।

मार्केट लीडर इंडिगो को दोहरा झटका...

मुनाफा 77% घटने के बीच जांच से 4% तक गिरे शेयर

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो) के शेयर इन दिनों बिकवाली के दबाव में हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन के शेयर शुक्रवार को 0.5% गिरकर 4,912 रुपए पर बंद हुए। गुरुवार को भी इसमें 3.6% तक गिरावट आई थी। दरअसल, प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 4 फरवरी को कंपनी के खिलाफ बिजनेस के गलत तरीके अपनाने के आरोप में जांच के आदेश दिए थे। सीसीआई ने प्रथम दृष्टया निष्कर्ष निकाला कि इंडिगो ने दबदबे का गलत इस्तेमाल किया है। यह सेवाओं की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने जैसा है, जो प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

भास्कर नॉलेज : आय, कमाई, यात्री बढ़े, पर 2,581 करोड़ रु. के अतिरिक्त खर्च से लाभ घटा

- अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में इंडिगो का मुनाफा सालाना आधार पर 77% घटकर 5,50 करोड़ रुपए रह गया। अक्टूबर-दिसंबर, 2024 में मुनाफा 2,449 करोड़ रुपए था। आय 6.2% बढ़कर 23,472 करोड़ रही।
- इस दौरान इंडिगो के यात्रियों की संख्या भी 2.8% बढ़कर 3.19 करोड़ रही।
- देश में नए श्रम कानूनों के लागू होने से कर्मचारियों पर खर्च बढ़ना, ऑपरेशनल बाधाएं और डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी इसकी वजह रही।

अतिरिक्त खर्च

रुपए की वैल्यू घटने से 1035 करोड़ का घाटा

969.3 करोड़ नए श्रम कानूनों के लागू होने खर्च बढ़ा
₹577.2 करोड़ ऑपरेशनल बाधाओं के चलते खर्च हुए
1,035 करोड़ रुपए की वैल्यू घटने से डॉलर में खर्च हुए,
यानी **2,581** करोड़ अतिरिक्त खर्च (स्रोतः कंपनी फाइलिंग)

जून-सितंबर 2025 में 2,582 करोड़ घाटे में थी कंपनी

तिमाही-दर-तिमाही आधार पर देखें तो इंडिगो के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। जून-सितंबर 25 में 2,582 करोड़ का घाटा था। इस हिसाब से कंपनी एक तिमाही में घाटे से मुनाफे में आ गई। इंडिगो के पास 51,607 करोड़ रु. की नकदी हैं। दिखाता है कि कंपनी पूंजी के मामले में मजबूत हुई है।

बुलियन • सोने-चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट

चांदीः 20 दिन की उछाल 7 दिन में ही खत्म, 2.5 लाख से भी नीचे आई कीमत

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला लगातार दूसरे दिन जारी रहा। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स (आईबीजेए) के आंकड़ों के मुताबिक, शुक्रवार को 24-कैरेट सोने की कीमत 424 रुपए घटकर 1,52,078 रुपए रह गई। चांदी में भी 9,410 रुपए की गिरावट आई और यह 2,44,929 रुपए प्रति किलो रह गई। इसके साथ ही सिर्फ 7 दिन में चांदी की कीमत 29 जनवरी के रिकॉर्ड ऊंचे स्तर से 35.5% घट चुकी है।

केडिया एडवाइजरी के विश्लेषकों के मुताबिक, चांदी की कीमतों में गिरावट का एक बड़ा कारण कीमती धातुओं और यहां तक कि क्रिप्टोकरेंसी जैसी एसेट क्लास के प्रति वैश्विक बाजारों में व्याप्त ऑफ-रिस्क (जोखिम-विरोधी) भावना है। इसका मतलब है कि निवेशकों के बीच जोखिम का डर कम हो गया है। हालांकि ये गिरावट मुनाफा वसूली का भी नतीजा है।

चांदीः 29 जनवरी को 3.8 लाख की थी

- चांदी इस साल 29 जनवरी को 3,79,988 रुपए किलो के अभ तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची थी। उससे पहले 9 जनवरी को यह 2,42,808 रुपए प्रति किलो थी।
- यानी 2.4 लाख से करीब ₹3.8 लाख पहुंचने में इसने 20 दिन लिए लेकिन 3.8 लाख से वापस 2.4 लाख के आसपास पहुंचने में महज 7 दिन लगे।

2 लाख से नीचे आकर स्थिर हो सकती है चांदी

- केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक, चांदी में फिलहाल जो गिरावट आई है वो ईटीएफ में मुनाफा वसूली का नतीजा है। इससे सराफा बाजार का रुझान कमजोर हुआ। चांदी काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। हमारा अनुमान है कि 1-2 महीने में यह 2 लाख रुपए से नीचे आ सकती है।
- चांदी 1.8-2 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास स्थिर हो सकती है। इस बीच निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए। बाजार में गिरावट पर प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। सोना-चांदी लंबी अवधि का निवेश है। फिलहाल एकमुश्त खरीदने के बजाय किस्तों में (एसआईपी) की तरह इसमें निवेश करना चाहिए।

- कमोडिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांदी की कमी, इंडस्ट्रियल इस्तेमाल बढ़ने जैसी वजहों से चांदी फिर तेजी पकड़ सकती है।

दिलचस्पः रंग बदलने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी की दस्तक

कोलंबिया | फॉक्सवैगन ग्रुप नई इलेक्ट्रिक एसयूवी 'पेसिफिक मिस्ट' ला रही है। यह रंग बदलती है। धूप में प्रशांत महासागर के रंग जैसी हल्की नीली दिखती है, पर बादल छाए रहने पर चांदी जैसी चमकती है। इसकी 1.5 लाख से ज्यादा बुकिंग हो चुकी हैं। सिंगल चार्ज में 800 किमी चलने वाली इस ईवी की कीमत 54 लाख रुपए हो सकती है।

ईपीएफओ रेलवे, डिफेंस में कर सकता है निवेश

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने निवेश पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। संगठन अब केवल सेंसेक्स और निफ्टी तक सीमित रहने के बजाय रेलवे, डिफेंस और रेयर अर्थ जैसे उभरते सेक्टर्स में पैसा लगा सकता है। ईपीएफओ की निवेश समिति 10 फरवरी को होने वाली बैठक में इन विकल्पों पर विचार करेगी। वर्तमान में समिति करीब 31 लाख करोड़ रुपए के विशाल फंड का प्रबंधन करती है। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, ईटीएफ से इतर सेक्टर और स्टाइल आधारित इंडेक्स में कदम रखने की व्यावहारिकता जांची जा रही है। इससे पहले दिसंबर 2025 की बैठक में क्रिसिल से ईएसजी मानकों के आधार पर निवेश का विश्लेषण मांगा गया था। 31 दिसंबर 2025 तक ईपीएफओ के कुल पोर्टफोलियो का 10.5% हिस्सा शेयर बाजार में है। ईपीएफओ को अपनी नई जमा राशि का 15% तक हिस्सा इक्विटी में लगाने की अनुमति है।

सफल चढ़ाई

दक्षिण अमेरिका की 6,961 मीटर ऊंची चोटी पर तिरंगा

नोएडा | वेक्टस पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी अतुल लड्ढा ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अकोंकागुआ पर सफल चढ़ाई की है। 6,961 मीटर (22,838 फीट) ऊंचे इस पर्वत को फतह करने वाले वे सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। लड्ढा ने महज सात दिन में यह अभियान पूरा कर नया इतिहास रचा। अर्जेंटीना में एंडीज पर्वतमाला के बीच स्थित अकोंकागुआ एशिया के बाहर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। खराब मौसम और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद लड्ढा ने इसे फतह कर कंपनी के कर्मचारियों और पार्टनर्स को चुनौतियों से न डरने का संदेश दिया।

तैयारी • बार-बार निकासी आवेदन से मुक्ति!

म्यूचुअल फंडः सेबी ने दिया ऑटो-विड्रॉल का प्रस्ताव

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक नया प्रस्ताव पेश किया है। डीमैट अकाउंट में रखे म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की सुविधा देने की तैयारी है। यदि यह लागू होता है, तो निवेशकों को हर महीने पैसा निकालने (एसडब्ल्यूपी) या ट्रांसफर (एसटीपी) करने के लिए बार-बार रिक्वेस्ट नहीं देनी होगी। निवेशक एक बार आदेश सेट कर देंगे और तय तारीख पर पैसा अपने आप बैंक खाते में आता रहेगा। वर्तमान में यह सुविधा केवल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट (एसओए) मोड वाले निवेशकों को मिलती है। डीमैट होल्डर्स के लिए अभी यह प्रक्रिया काफी जटिल है। यदि आप डीमैट के जरिए म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपको हर महीने अपने ब्रोकर एप या पोर्टल पर जाकर हर ट्रांजैक्शन के लिए मैन्युअल रूप से 'रिडेम्पशन रिक्वेस्ट' डालनी पड़ती है। नई व्यवस्था सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) की तरह ऑटोमैटिक हो जाएगा। सेबी का मकसद डीमैट और पारंपरिक निवेश के अंतर को खत्म करना है।

सुविधाः बुजुर्गों, नियमित आय चाहने वालों को राहत

नया सिस्टम उन बुजुर्गों के लिए मददगार साबित हो सकता है जो पेंशन की तरह सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिये नियमित आय चाहते हैं। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान (एसटीपी) के जरिये निवेशक एक फंड से दूसरे फंड में पैसा भी आसानी से शिफ्ट कर पाएंगे।

किसानों के लिए राहत

फॉस्फेट, पोटाश खाद का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

देश में फॉस्फेटिक और पोटैशिक (पीएंडके) खाद का घरेलू उत्पादन जनवरी में 15.76 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इनमें डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और कॉम्प्लेक्स एनपीके शामिल हैं। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में ये दावा किया गया। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में भारत ने एक वर्ष पहले की तुलना में 85% ज्यादा यूरिया, 46% अधिक डीएपी और 122% अधिक एनपीके उर्वरक आयात किए। इस बीच उत्पादन बढ़ने से खाद की आपूर्ति बढ़ेगी।

भास्कर एनालिसिस • एआई टूल्स से आईटी सर्विसेज कंपनियों की आय घटने का अंदेशा

बड़ी आईटी कंपनियों ने 5 वर्ष से रिटर्न नहीं दिया

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

सालाना कम्पाउंडेड रेट के हिसाब से देश की बड़ी आईटी कंपनियों के 5 साल के रिटर्न में भारी गिरावट आई है। टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो जैसी आईटी कंपनियां फ्लैट या नेगेटिव रिटर्न दे रही हैं। विश्लेषकों के मुताबिक निवेशकों को लगता है कि एंथ्रॉपिक जैसे नए ऑटोमेशन एआई टूल्स भारतीय आईटी कंपनियों के पारंपरिक बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एनएसई और प्राइम डेटाबेस के आंकड़ों के मुताबिक, टीसीएस ने बीते 5 वर्षों में -1.22% सीएजीआर रिटर्न दिया। यानी 5 साल पहले लगाए गए 100 रुपए अब 94 रुपए रह गए हैं। इस दौरान इंफोसिस का सीएजीआर 3.7% और विप्रो का 1.6% पॉजिटिव रहा। कुछ छोटी कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन के चलते निफ्टी आईटी इंडेक्स का 5 साल का सीएजीआर 7.1% ही रहा। मोतीलाल ओसवाल के विश्लेषकों का अनुमान है कि एआई-ड्रिवन सहूलियतों के चलते आईटी सर्विसेज से 30-40% आय जोखिम में हैं। नए ऑटोमेशन एआई टूल्स की वजह से आईटी सर्विसेज से जुड़े छोटे-मोटे काम 30-50% प्रभावित हो सकते हैं। नतीजतन 3-4 साल में 9-12% आय का जरिया खत्म हो सकता है। इससे आईटी कंपनियों की सालाना ग्रोथ 2% घट सकता है।

घरेलू बाजार शेष दुनिया के बाजारों से किफायती

भारतीय शेयर बाजार का मूल्यांकन सामान्य स्तर पर लौट आए हैं, जबकि वैश्विक इक्विटी बाजार अब भी महंगे बने हुए हैं। सेंसेक्स-निफ्टी का एक साल का फॉरवर्ड पीई क्रमशः 20.5 और 20.1 गुना है। 10 साल का औसत भी यही है।

टॉप बाजार	फॉरवर्ड पीई*	औसत*
सेंसेक्स	20.5	19.8
निक्केई	23.5	18.7
एसएंडपी 500	21.6	19.2
डाऊ जोन्स	21.6	18.3

(स्रोतः ब्लूमबर्ग) *1 साल का फॉरवर्ड पीई | औसत* 10 साल का

बिजनेस एंकर 39% विमान हादसे प्राइवेट जेट के चलते, फिर भी 3 साल में 25% बढ़े, चीन में घटे

लग्जरी सिंबल रहे प्राइवेट जेट अब आम जरूरत का हिस्सा

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

देश में प्राइवेट जेट यानी नॉन-शेड्यूल्ड उड़ानें का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्राइवेट जेट के इस्तेमाल का दायरा बढ़ गया है। पहले प्राइवेट जेट सिर्फ अमीरों की लग्जरी थी। लेकिन अब बिजनेस, लीजर ट्रैवल और एयर एंबुलेंस जैसी सेवाओं में इनका इस्तेमाल आम होता जा रहा है। देश में अभी 133 नॉन-शेड्यूल्ड ऑपरेटर हैं, जो चार्टर्ड पैसेंजर, कार्गो और एयर एंबुलेंस चलाते हैं। विमानन नियामक डीजीसीए के मुताबिक, फिलहाल 445 विमान और हेलिकॉप्टर (214 एयरप्लेन + 220 हेलीकॉप्टर) सेवा में हैं। इनकी मांग का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2021 से लेकर 2024 तक इनकी फ्लीट में 25 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है। भारत के उलट चीन में प्राइवेट जेट की मांग में गिरावट आई है। भारत में प्राइवेट जेट की मासिक उड़ानें तीन गुना बढ़कर 2,400 से ज्यादा हो गईं हैं। एशियन स्काई ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत एशिया का सबसे तेजी से बढ़ता प्राइवेट जेट मार्केट है, चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद तीसरे नंबर पर। सरकार की एजेंसी इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएल) के मुताबिक, भारत में प्राइवेट जेट की बढ़ती मांग की कई वजहें हैं। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था (जीडीपी), हाई-नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी धनाढ्य लोगों और बेहतर एयर इंफ्रास्ट्रक्चर इनमें शामिल हैं। केयर एज रिसर्च की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत का प्राइवेट जेट सेक्टर अभी करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए का है। 2023 से लेकर 2029 तक यह सालाना 7-9% कम्पाउंडेड रेट (सीएजीआर) से बढ़कर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। हाल ही में 28 जनवरी को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की लर्नजेट 45 क्रैश में मौत ने प्राइवेट जेट्स के सुरक्षित होने पर सवाल उठाए हैं। बढ़ती दुर्घटनाओं से डीजीसीए की निगरानी सख्त हो रही है। संसदीय समिति ने अगस्त 2025 में कहा कि विमानों की संख्या एयरपोर्ट इंफ्रा से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स कहते हैं, 'ग्रोथ जारी रहेगी, लेकिन सुरक्षा, इंफ्रा और रेगुलेशंस मजबूत करने की जरूरत है। भारत जल्द ही प्राइवेट एविएशन में ग्लोबल पावर बन सकता है।'

विमान दुर्घटनाओं में प्राइवेट जेट की हिस्सेदारी ज्यादा

डीजीसीए के आंकड़ों के मुताबिक, 2014 से अब तक देश में 90 विमान दुर्घटनाएं हुई हैं। 2014 से लेकर 2020 के बीच हुए 56 हादसों में प्राइवेट जेट्स की सबसे ज्यादा 39.3 फीसदी हिस्सेदारी थी। इन हादसो के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी 28.6 फीसदी और शेड्यूल्ड विमानों की हिस्सेदारी 23.2 फीसदी थी। 2021 और 2024 के बीच 34 दुर्घटनाओं में प्राइवेट जेट 32.3 फीसदी हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रहे।

आरबीआई • अच्छे बैंकों के लिए बचत की नई राह खुलने जा रही

बैंकों के लिए नया नियमः सबसे सुरक्षित बैंक की डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम 33% घटेगी

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल, 2026 से बैंकों के लिए 'रिस्क-बेस्ड प्रीमियम' (आरबीपी) फ्रेमवर्क लागू किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत, बैंकों को अब उनकी वित्तीय स्थिति और जोखिम के आधार पर 8 से 12 पैसे के बीच प्रीमियम देना होगा, जिससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैंकों को वित्तीय लाभ मिलेगा। बैंकों को चार श्रेणियों ए, बी, सी और डी में वर्गीकृत किया जाएगा। ए श्रेणी सबसे कम जोखिम दर्शाने वाली है। नया ढांचा 1962 से लागू फ्लैट-रेट प्रीमियम प्रणाली का स्थान लेगा। इसमें सभी बैंकों को उनकी जमा राशि पर 12 पैसे प्रति 100 की समान दर से प्रीमियम देना होता है। बता दें कि बैंक अपने प्रत्येक जमाकर्ता के 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट का इंश्योरेंस करवाते हैं। इन श्रेणियों के आधार पर प्रीमियम दरें प्रति 100 रुपए पर 8 पैसे से 12 पैसे तक होंगी। सबसे मजबूत बैंकों को 33.35% तक की छूट मिलेगी। इससे जोखिम प्रबंधन में मजबूती आएगी। सुरक्षित बैंकों का इंश्योरेंस प्रीमियम खर्च बचेगा। ग्राहक को भी फायदा होगा।

भास्कर नॉलेज

ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा, जमा-पूंजी ज्यादा सुरक्षित

प्रीमियम में पैसा बचाने वाले बैंक ग्राहकों को ज्यादा सुविधाएं या ब्याज दरों में रियायत की पेशकश कर सकते हैं। ज्यादा जोखिम वाले बैंकों पर अधिक प्रीमियम लगने से, बैंक ग्राहकों की जमा रकम की सुरक्षा को लेकर ज्यादा उपाय करेंगे। इससे ग्राहकों की जमा पूंजी ज्यादा सुरक्षित होगी। इससे स्वस्थ बैंकिंग को प्रोत्साहन मिलेगा और बैंकिंग क्षेत्र के प्रति जनता का विश्वास बढ़ेगा।

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। **–वाल्तेयर**

'भारत टैक्सी' ने दिखाई सहकारिता में नई किरण

भारत में सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा की शुरुआत दुनिया के लिए एक ऐसी क्रांतिकारी गूंज है, जिसकी अनुगूंज अन्य क्षेत्रों में सुनाई पड़ सकती है। निश्चित ही यह 'ओला' और 'उबर' जैसी निजी स्वामित्व में चलने वाली ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को चुनौती देगी। अच्छी बात यह है कि सहकार से संचालित होने के कारण 'भारत टैक्सी' सेवा में बिचौलिया कंपनियों का मुनाफा शामिल नहीं होगा, जिससे यात्रियों और टैक्सी ड्राइवरों दोनों को फायदा होगा। इससे सेवा सस्ती तो होगी ही, करीब-करीब पूरा किराया चालकों की जेब में जाएगा जबकि, निजी कंपनियां 30-40 फीसदी किराया अपने पास रखती हैं। भारत टैक्सी का संचालन 'सहकार टैक्सी को-ऑपरेटिव लिमिटेड'(एसटीसीएल) नामक बहुराज्यीय सहकारी संगठन करेगी, जिसमें टैक्सी चालक शेयर होल्डर होंगे। इस ऐप से जुड़ते ही चालक को कम से कम पांच शेयर मिलेंगे, जिनकी कीमत मात्र 500 रुपए होगी। कार चालकों को प्रतिदिन मात्र 30 रुपए और ऑटोरिक्शा चालकों को 18 रुपए का सब्सक्रिप्शन चार्ज देना होगा। सरकार ने वर्ष 2029 तक देशभर में 'भारत टैक्सी' सेवा शुरू करने का संकल्प जताया है।

'भारत टैक्सी' की सफलता इस पर निर्भर होगी कि संचालन कितनी बखूबी और पेशेवर तरीके से किया जा रहा है। सहकारी संगठनों के सामने ऐतिहासिक रूप से प्रबंधन और पारदर्शिता की चुनौतियां रही हैं। लेकिन आज हमारे पास 'ब्लॉकचेन' और 'रियल-टाइम डेटा एनालिटिक्स' जैसी तकनीकें हैं। 'भारत टैक्सी' की सफलता इस बात पर भी टिकी है कि उसका ऐप उतना ही सुचारू हो जितना किसी निजी कंपनी का। यदि हम तकनीक का इस्तेमाल लोकतांत्रिक तरीके से करें तो सहकारिता का प्रबंधन भ्रष्टाचार मुक्त और कुशल हो सकता है। देश में सहकारिता का इतिहास दूध व पापड़ उद्योग में सफलता की कहानियों से भरा पड़ा है। यह भी सच है कि देश में सहकारिता कमोबेश कृषि और डेयरी क्षेत्रों तक सीमित रही है जबकि, इसके विस्तार की काफी गुंजाइश है। मोदी सरकार ने पहली बार अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन व उसकी जिम्मेदारी अमित शाह जैसे कद्दावर नेता को देकर अपने इरादे जरूर जाहिर किए थे।

वस्तुतः कई क्षेत्र हैं जहां सहकारिता मॉडल न केवल संभव है, बल्कि बेहतर हो सकता है। वर्तमान में ई-कॉमर्स बाजार पर कुछ वैश्विक कंपनियों का एकाधिकार है। यदि एमएसएमई का अपना एक सहकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, तो वे विज्ञापनों और कमीशन के बोझ से मुक्त होकर उपभोक्ताओं को सस्ता सामान उपलब्ध करा सकेंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के इस दौर में, समुदाय-आधारित सौर ऊर्जा सहकारी समितियां क्रांतिकारी कदम हो सकती हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी या पूरा गांव मिलकर सौर पैनल लगा सकता है और उत्पादित बिजली का उपयोग करने के बाद अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर सामूहिक आय अर्जित कर सकता है।

दाम्पत्य भाव चूंकि आत्मा का क्षेत्र है, अतः शरीर-मन-बुद्धि उसके उपकरण रूप अपरा प्रकृति के ही भाग रहते हैं। उनका आदान-प्रदान तो आत्मा से ही होता है। ये माया का भी क्षेत्र है।

दाम्पत्य और माया

गुलाब कोठारी
प्रधान संपादक
पत्रिका समूह
@patrika.com

शरीर ही ब्रह्माण्ड

रस-बल ही कामना का वास्तविक रूप हैं। रस और बल दोनों ही केन्द्र में हैं, दोनों ही परिधि में हैं। ये दो तत्त्व ही हृदय के स्वरूप का निर्माण करते हैं। इसी में तीनों अक्षर प्राणों के अलावा दो अन्य कलाएं भी होती हैं–अग्नि और सोम। सम्पूर्ण पदार्थ अग्नि-सोम के तारतम्य से ही उत्पन्न होते हैं।

प्रकृति की प्रबन्धन शक्ति विस्मयकारी है और त्रिकालदर्शी भी। सभी प्राणी अर्द्धनारीश्वर रूप में तीन-तीन स्तरों पर कार्य करते हैं। अव्यय, अक्षर और क्षर पुरुष रूप में तथा माया, परा और अपरा प्रकृति रूप में। अहंकृति के अनुरूप ही आकृति और प्रकृति होती है। तीनों के धरातल भिन्न-भिन्न होते हैं। इनके कार्य स्वतंत्र भी होते हैं, मिश्रित भी। वैसे कर्ता भाव अव्यय और अक्षर में होता नहीं है, किन्तु सूक्ष्म स्तर की गतिविधियां ही स्थूल कर्मों की निमित्त बनती हैं। यह भी स्पष्ट है कि कर्म में ब्रह्म और माया साथ नजर आते हैं। अक्षर पुरुष के स्तर पर परा प्रकृति गतिमान रहती है। शरीर के स्थूल स्तर पर अष्टधा प्रकृति-शरीर-मन-बुद्धि-अहंकार ही स्थूल कर्मों के उपकरण बनते हैं।

उपकरण निर्जीव अथवा सुप्त चेतना वाले होते हैं। जैसे पृथ्वी लक्ष्मी तो है किन्तु जो कुछ इसमें पैदा होता है (धरती को माता कहते हैं), सभी तो सुप्त चैतन्य पदार्थ हैं–चाहे अन्न हो, सम्पदा हो (स्वर्णादि, खनिज)। अन्न से शरीर बनता है। माता के शरीर से सन्तान का शरीर बनता है। शरीर स्वतः कार्य नहीं कर सकता। यह मन की इच्छा और प्राणों की गति से चलायमान नजर आता है। जैसे कार को ड्राइवर चलाता है।

शरीर आकृति का नाम है। इसको अहंकृति और प्रकृति चलाते हैं। अहंकृति सूर्य से तथा प्रकृति चन्द्रमा से निष्पन्न होती है। दोनों ही चैतन्य से संचालित रहते हैं। सूर्य तो जगत का आत्मा ही है। चन्द्रमा का पति रूप है। चन्द्रमा मन का अधिष्ठाता है। अहंकृति-प्रकृति दोनों ही सूक्ष्म भाव में कार्य करते हैं। आकृति में स्वतंत्र चिन्तन नहीं है। भूगोल आकृति को प्रभावित करता है। स्थानीय अन्न से ही शरीर का निर्माण होता है। अतः शरीर अन्न की सन्तान ही है।

जहां तक शरीर का सम्बन्ध है, वहां तक मानव अचेतन-जड़ भूतों की श्रेणी में आता है। जहां तक मन का सम्बन्ध है, वहां तक मानव चेतन-सेन्द्रिय-मन सहित सामान्य पशु आदि की श्रेणी में आता है। जहां तक बुद्धि का सम्बन्ध है, वहां तक चेतन-मन-बुद्धि युक्त विशेष पशु आदि की श्रेणी में आता है। आत्मस्वरूप की पूर्ण अभिव्यक्ति वाला मानव ही पूर्णता का अधिकारी है–

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूँ स्वाम् ॥ (कठो. 1.2.22)

मानव के आत्म स्वरूप से सम्बन्ध रखने वाले बौद्धिक-मानसिक-शारीरिक भाव जब जहां जैसी आवश्यकता हो वैसे परिवर्तनशील बने रहते हैं। इन तीनों आचरणों का- आत्मा से जुड़ा स्वरूप ही मानवता है। इन्हीं के लिए पुरुषार्थों की व्यवस्था की है। शरीर से अर्थ का, मन से काम का, बुद्धि से धर्म का तथा मोक्ष से आत्मा का सम्बन्ध है। आज के युग में- 'अर्थ खा गया धर्म को, काम खा गया मोक्ष को।'

सूक्ष्म शरीर का केन्द्र हृदय होता है। तीन अक्षर प्राणों से निर्मित हृदय–ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्र प्राण- सभी प्राणियों में समान रूप से कार्य करता है। अव्यय (कारण शरीर) में संचित कर्म रहते हैं, सूक्ष्म शरीर प्रारब्ध कर्म पर कार्य संचालन करता है। सूक्ष्म शरीर एक ओर कारण से तथा दूसरी ओर स्थूल से जुड़ा रहता है। श्रुति कहती है–

न सती सा नासती सा नोभयात्मा विरोधतः।
काचिद्विलक्षणा माया वस्तुभूता सनातनी।

पुरुष के हृदय में प्रतिष्ठित रसबलात्मक तत्त्व 'मन' कहलाया–**ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।** मनोमय पुरुष के अर्क रूप रश्मि भाव ही 'काम' कहलाते हैं। ये ही 'एकोहं बहुस्याम्' रूप में सृष्टि बीज बने। कामना मन का रेत है। इसी कारण पुरुष 'कामरेत' है। रस-बल ही कामना का वास्तविक रूप हैं। रस और बल दोनों ही केन्द्र में हैं, दोनों ही परिधि में हैं। ये दो तत्त्व ही हृदय के स्वरूप का निर्माण करते हैं। इसी में तीनों अक्षर प्राणों के अलावा दो अन्य कलाएं भी होती हैं–अग्नि और सोम। सम्पूर्ण पदार्थ अग्नि-सोम के तारतम्य से ही उत्पन्न होते हैं। स्पर्शरूप सोम से तथा उष्मारूप अग्नि से ही वर्ण और अक्षरों का भी उद्‌भव होता है।

सूर्य-चन्द्रमा का दाम्पत्य भाव ही सृष्टि का उपादान कारण है। आधे आकाश में सूर्य-दिन के स्वामी हैं। आधे आकाश में चन्द्रमा रात के स्वामी हैं। इनको ही मनु-श्रद्धा कहा जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं- जैसे विधि और निषेध। दोनों से आध्यात्मिक संवत्सर यज्ञ पूर्ण होता है। अक्षर द्वारा क्षर का विस्तार ही (जानना) विज्ञान कहलाता है।

पृथ्वी, सूर्य की परिक्रमा क्रान्तिवृत्त पर करती है। यही संवत्सर कहलाता है। इसमें सूर्य विष्वद्‌वृत्त वृत्त के दोनों ओर 24 अंश तक उपलब्ध रहता है। जिस ओर दिन रहता (सूर्य) है उस आधे सौर आकाश से पुरुष का तथा दूसरे चन्द्र शासित (रात्रि) आधे सौम्याकाश से स्त्री के स्वरूप का विकास होता है। इसी दाम्पत्य भाव से सृष्टि होती है। **पुरुषो वै यज्ञः** कहा है।

अध्यात्म संस्था में संवत्सर का विष्वद् वृत्त ही मेरुदण्ड बनता है। पति-पत्नी जब आमने-सामने खड़े होते हैं तो, तब रीढ़ की हड्डी पूर्ण वृत्त बना देती है। दोनों की 24-24 पसलियां ही क्रान्तिवृत्त का 48 अंश का स्वरूप बनाते हैं। संवत्सर यज्ञ से प्रजा पैदा होती है। इस यज्ञ को इष्ट कामधुक् कहते हैं। गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि प्रजापति ने प्रजाओं को कहा कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यज्ञ तुम्हें इच्छित भोग देने वाला हो–

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्।। (3.10)

सूक्ष्म शरीर ही जीवन की गतिविधियों का मूल स्थान है। हृदय ही कामना का, ब्रह्म का, देव प्राणों का स्थान है। मन ही मूल अव्यय मन के आश्रय में सृष्टि की ओर अथवा मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। इसी में ईश्वर इच्छा एवं जीव की इच्छा पैदा होती है। दाम्पत्य भाव का केन्द्र सूक्ष्म शरीर ही है। स्थूल शरीर उपकरण रूप साधन होता है। पुरुष जीव के साथ पित्रांश भी रहता है। स्त्री का पित्रांश भी इसी के साथ रहता है। इसी से स्त्री का सम्बन्ध सात जन्मों का हो जाता है।

दाम्पत्य भाव चूंकि आत्मा का क्षेत्र है, अतः शरीर-मन-बुद्धि उसके उपकरण रूप अपरा प्रकृति के ही भाग रहते हैं। उनका आदान-प्रदान तो आत्मा से ही होता है। ये माया का भी क्षेत्र है। दाम्पत्य भाव जब सृष्टि साक्षी रहता है, तब शरीर, मन और बुद्धि से सम्बद्ध रहता है। क्षरण की दिशा में अग्रसर होता है। आत्म तत्त्व से रहित कर्म पशु के समान ही माना जाएगा। आत्मभाव से युक्त मानव अतिक्रमण नहीं करता। बुद्धि आग्नेयी है, मन सौम्य है। आग्नेयता पौरुष भाव तथा सौम्यता स्त्रैण भाव है। सोममयी श्रद्धा शक्तितत्त्व है। अग्निमय रुद्र-शिवतत्त्व है। जब दोनों अलग रहते हैं, तब दोनों ही अतिक्रमण करते हैं। अतः शक्ति व शक्तिमान का साहचर्य ही सृष्टि में कल्याणकारी माना गया है। 'सहधर्मं चरताम्' ही दाम्पत्य का आदर्श स्वरूप है।

दाम्पत्य भाव अक्षर सृष्टि में ही निष्पन्न होता है। इसके स्थूल कर्म शरीर में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन प्रजा वृद्धि का मूल तो ब्रह्म है जो अव्यय में प्रतिष्ठित रहता है। यज्ञ के मध्य माया ही ब्रह्म को अक्षर से युक्त करती है। इसके अभाव में सृष्टि नहीं होती है। दम्पति इस ब्रह्म के लिए आश्रय (शरीर) का निर्माण करते हैं। **-क्रमशः**

gulabkothari@epatrika.com

क्यूआर कोड को स्कैन कर आप आलेख सुन भी सकते हैं।

बुक इनसाइट

आइलैंड एट द एज ऑफ द वर्ल्ड

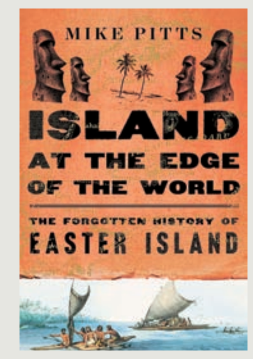

लेखक माइक पिट्स की पुस्तक 'आइलैंड एट द एज ऑफ द वर्ल्ड' ईस्टर द्वीप (रापा नुई) के रहस्यमय इतिहास को सरल, रोचक और शोध-आधारित ढंग से सामने रखती है। किताब का केंद्र वे विशाल पत्थर की मूर्तियां 'मोआइ' हैं, जिन्हें देखकर दुनिया आज भी अचंभित होती है। लेकिन यह सिर्फ मूर्तियों की कहानी नहीं, बल्कि उस सभ्यता की यात्रा है, जिसने समुद्र के बीच बसे एक छोटे से द्वीप पर अपना जीवन, संस्कृति और पहचान रची। लेखक प्रशांत महासागर की लहरों के पार ले जाकर बताते हैं कि कैसे पोलिनेशियन नाविक सदियों पहले यहां पहुंचे, कैसे समाज विकसित हुआ और फिर समय के साथ किन चुनौतियों से जूझना पड़ा। संसाधनों की कमी, आपसी संघर्ष और बाहरी संपर्क को पिट्स संतुलित ढंग से रखते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि ईस्टर द्वीप का इतिहास सिर्फ 'पतन की कहानी' नहीं है, यह मानव जिजीविषा और पुनर्निर्माण का उदाहरण भी है।

आर्ट एंड कल्चर

उस्ताद अलाउद्दीन खां: विशिष्ट संगीत यात्रा

बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब के सौवें जन्मदिन का समारोह 6 अक्टूबर 1962 दुर्गाष्टमी के दिन मध्य प्रदेश के मैहर में मनाया जा रहा था। वह संगीतकारों और संगीत प्रेमियों के लिए एक तीर्थस्थल में परिवर्तन हो चुका था। उसी दौरान पंडित रविशंकर जो उनके शिष्य और दामाद दोनों थे, ने कहा था 'महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने अपने जीवन काल में जितना अर्जित किया है, अन्य लोग 300 सालों में भी नहीं कर सकते।' बाबा का पूरा जीवन सिर्फ संगीत को ही समर्पित रहा। उन्होंने 110 वर्षों का सुदीर्घ जीवन पाया था।

चिन्मय मिश्र
वरिष्ठ संस्कृतिकर्मी
@patrika.com

उन्होंने वैसे तो शुरुआती दौर में गायन को ही अपना माध्यम बनाया था। परंतु अपने गुरु की असमय मृत्यु ने उन्हें इतना व्यथित कर दिया कि उनकी मृत्यु का समाचार सुनते ही उन्होंने तय कर लिया वे अपनी गायकी को गुरु के साथ ही दफन कर देंगे और भविष्य में पूरी तरह से वाद्य संगीत को ही समर्पित रहेंगे। ऐसा उन्होंने पूरे जीवन किया भी। वे अनेक वाद्यों को बजाने में माहिर थे। परंतु गायकी उन्हें कोलकाता खींच ले गई। वहां गुरु नुलो गोपाल ने उनकी प्रतिभा को पहचाना।

संयोग से एक दिन उन्हें उस्ताद अहमद अली खान का सरोद वादन सुनने का मौका मिला। वे राजा जगत किशोर द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा समारोह में वादन के लिए आए थे। अलाउद्दीन सरोद सुनकर अभिभूत हो गए और इसके बाद वे उस्ताद के पैरों पर गिर पड़े और तब तक नहीं उठे जब तक कि दयालु राजा ने उस्ताद को मना नहीं लिया कि वे इस मेधावी युवा को अपना शिष्य बना लें। अहमद अली अपने संरक्षक की अपील को ठुकरा नहीं पाए। परंतु उनकी कतई इच्छा नहीं थी कि वे अपनी इस अनूठी और सबसे छिपाई कला की हिस्सेदारी किसी और के साथ करे। अलाउद्दीन खां कमोबेश उनकी गुलामी करते रहे, लेकिन 'गुरु' इतने कठोर थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं सिखाया। परंतु बेहद समझदार शिष्य ने सिर्फ सुनकर सरोद की सारी बारीकियां सीख और समझ लीं। दुर्भाग्य या सौभाग्य से एक दिन गुरु ने उनका वादन सुन लिया। वे अपनी शैली की इतनी बारीक नकल से हतप्रभ रह गए और बेहद नाराज भी हो गए। वे समझ गए कि उनका कथित शिष्य शीघ्र ही उन्हें पीछे छोड़ देगा। अहमद अली ने उसी क्षण उनसे वहां से चले जाने को यह कहते हुए कहा कि अब तुम अपनी रियाज खुद करो। इसके बाद जो हुआ वह तो इतिहास ही है। उनके कुछ प्रमुख शिष्य हैं- अली अकबर खां (सरोद), उनकी बेटी अन्नपूर्णा (सितार), गुरु पन्नालाल घोष (बांसुरी) आदि। बाबा अपने शिष्यों से कहते थे कि शास्त्रीय संगीत में महारत हासिल करना दोहरा आशीर्वाद पाने जैसा है। परंतु इसे प्राप्त करना एक कठोर और दीर्घ तपस्या जैसा है। यदि तुम में लंबा प्रशिक्षण लेने का साहस हो तो ही मेरे पास रुकना, वरना वापस चले जाओ। परंतु जो भी बाबा के पास आया वह पूर्ण पारंगत हुए बिना शायद ही वापस लौटा होगा।

दृष्टिकोण गाजियाबाद में तीन नाबालिग बहनों के सुसाइड से जुड़े अनछुए पहलू

वयस्कों की व्यस्त दुनिया में कुर्बान होती बच्चों की जिंदगी

पूजा दास
स्वतंत्र लेखिका एवं स्तंभकार
@patrika.com

गाजियाबाद में देर रात नौवें माले के अपने घर की खिड़की से कूदकर जान देने वाली तीन नाबालिग बहनों का मामला उतना सीधा-सपाट नहीं है जितना दिखता है। पड़ताल इस बात की भी होनी चाहिए कि किसी परिवार के हालात कैसे दमघोंटू अंधी सुरंग की तरह होते चले गए कि तीन लड़कियों ने अपनी जान दे दी। हंसने-खेलने, पढ़ने-लिखने और भविष्य के लिए नींव तैयार करने की किशोर उम्र में 16, 14 और 12 साल की तीन बहनों ने रूह कंपा देने वाले तरीके से आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले में कुछ तथ्यों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए वरना कोई हैरानी नहीं होगी कि ऐसे मामले हमारे सामने बार-बार आते रहेंगे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बच्चियों के पिता का कहना है, बेटियों ने ऑनलाइन गेम से जुड़े टास्क पूरे करने के लिए यह कदम उठाया। अपने बच्चों को इन गेम्स से बचाओ। जबकि बेटियों के 8 पन्नों के सुसाइड नोट में यह भी लिखा है, 'क्या हमें इस दुनिया में इसलिए जीना चाहिए कि तुम हमें पीटो? नहीं, मौत बेहतर होगी।' बच्चियां कोरियन कल्चर की दीवानी बताई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि पैरेंट्स ने उनके ऑनलाइन गेमिंग पर हाल ही कठोर आपत्ति जताई थी और फोन छीन लिया था। अब तक की पड़ताल में परत दर परत सामने आते जा रहे बयान और तथ्य दर्शाते हैं कि अब समय आ चुका है जब बतौर अभिभावक और परिवार हम मोबाइल नामक अपेक्षाकृत नए पारिवारिक सदस्य को लेकर बेहद सतर्कता और समझदारी से पेश आएं। साथ ही, बड़े लोग भी अपने भीतर झांके और बच्चों के प्रति अपनी भूमिका पर गौर करें। तमाम मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बच्चों को अनुशासन के जरिए साधने की कोशिश करना मारपीट से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। इस दुर्भाग्यपूर्ण मामले में जान गंवाने वाली तीनों लड़कियां कोविड के समय से मोबाइल की लत की शिकार थीं। वे करीब छह साल से ऑनलाइन गेमिंग में डूबी चली जा रही थीं। वे दो साल से स्कूल भी नहीं जा रही थीं। किशोरवय की बच्चियां सालों से घर पर बैठी थीं और खाना-पीना, सोना, यहां तक कि नहाना-धोना भी एक साथ करती थीं। इस तरह के व्यवहार कहीं न कहीं पेरेंटिंग में गंभीर गैप की ओर इशारा करते हैं जिसका नतीजा अंततः अति हो सकता है। बच्चा जब स्कूल जाने में लगातार आनाकानी करे, उसकी स्कूल में परफॉर्मेंस प्रभावित हो रही हो, व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन आने लगे, यह सब देखना और भांपना मुख्यतः परिवार की जिम्मेदारी होती है। समय रहते स्कूल में सहपाठियों, टीचर, दोस्तों, दोस्तों के माता-पिता से बात से संपर्क में रहा जाए। किसी भी प्रकार की लत दिखे जिसे खुद से हैंडल न किया जा पा रहा हो तो मनोवैज्ञानिक या डॉक्टरी सलाह से परहेज क्यों करना? अनलिमिटेड डाटा के साथ जब हम मोबाइल बच्चों को पकड़ा देते हैं, तब जाने अनजाने एक दोधारी तलवार उन्हें सौंप देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सुरक्षा और कई बार शिक्षा के लिहाज से मोबाइल फोन जरूरी हैं, पर वे इसका क्या, कैसे व कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखने की जिम्मेदारी बड़ों की ही होगी।

संयुक्त पारिवारिक प्रणाली या यों कहें कि दादा-दादी या नाना-नानी का साथ बच्चों की परवरिश के लिए बेहद अहम साबित होता है। जहां एकल परिवार हैं, वहां यह जिम्मेदारी तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी मां और पिता की ही बनती है। जहां तक मोबाइल एडिक्शन और गेमिंग कल्चर की बात है तो अति हर चीज की बुरी होती है। किसी भी लत को छुड़ाने के लिए एक परिपक्व समझदार इंसान को भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार डॉक्टरी मदद भी लेनी पड़ती है। लोग व्यसनों की जद में भी फंसे रहते हैं। फिर किशोर बच्चों को डांट देंगे और वे मान लेंगे, यह अपने आप में ही बेमानी उम्मीद है।

बर्फीले संसार में प्रकृति की कारीगरी
अंटार्कटिका की आंख

अंटार्कटिका की बर्फीली दुनिया में स्थित प्लेन्नो बे प्रकृति के अद्‌भुत शिल्प का उदाहरण है। यहां तैरता हुआ बर्फ का यह विशाल टुकड़ा, जिसे 'अंटार्कटिका की आंख' कहा जा रहा है, यह समय और तापमान के खेल को दर्शाता है। हिमखंड के केंद्र में बना गोलाकार छेद किसी आंख की पुतली जैसा प्रतीत होता है, मानो प्रकृति स्वयं हमें निहार रही हो। यह समुद्री धाराओं, तापमान में हल्के बदलाव और लगातार होती पिघलन की प्रक्रिया का परिणाम है।

चिकित्सा शिक्षा अगले पांच वर्षों में 75 हजार मेडिकल सीटों की होगी बढ़ोतरी, चिकित्सा सेवा का स्तर बनाए रखना चुनौती

बेतहाशा मेडिकल सीटों के लिए गुणवत्ता से न हो समझौता

डॉ. शुभकाम आर्य
वरिष्ठ चिकित्सक
@patrika.com

इस साल के केंद्रीय बजट में सरकार ने अगले पांच वर्षों में 75 हजार नई मेडिकल सीटें जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से लगभग 10 हजार नई सीटें तो इसी शैक्षणिक वर्ष (2026-27) में बढ़ाने की योजना है। विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा की गुणवत्ता, प्रशिक्षित फैकल्टी और तकनीकी संसाधनों का समुचित विकास सुनिश्चित करने पर ही यह वृद्धि अधिक सार्थक होगी।

वैसे भी भारत में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में हाल के वर्षों में आई संख्यात्मक छलांग ने अब एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, जहां एक ओर आंकड़ों की चमक तो है, लेकिन धरातल पर गिरती शैक्षणिक गुणवत्ता और भारी-भरकम फीस के बावजूद भविष्य के रोजगार का गहराता संकट चिंताएं खड़ी कर रहा है। देश में अभी मेडिकल कॉलेज 820 से अधिक हो चुके हैं। एमबीबीएस सीटें लगभग 1 लाख 30 हजार हो चुकी हैं। हर जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना ने इस विस्तार को गति दी है।

रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में प्रति 811 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है (पंजीकृत एलोपैथिक और आयुष चिकित्सकों की 80 फीसदी उपलब्धता मानते हुए)। यह अनुपात आदर्श माने जाने वाले मानक एक हजार लोगों पर एक डॉक्टर से बेहतर है। कई नए कॉलेज, बुनियादी आवश्यकताओं जैसे पर्याप्त रोगी भार, अत्याधुनिक उपकरण और सबसे महत्वपूर्ण योग्य फैकल्टी को पूरा नहीं करते। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि जब चिकित्सकों की संख्या पहले ही पर्याप्त है, तो इस बेतहाशा वृद्धि के लिए गुणवत्ता से समझौता करने का औचित्य क्या है? गुणवत्ता से समझौते का सबसे चिंताजनक उदाहरण हाल ही नीट-पीजी 2025 के संदर्भ में सामने आया है, जहां पीजी की खाली सीटों को भरने के दबाव में कट-ऑफ को इस हद तक गिरा दिया गया कि माइनस 40 अंक लाने वाले अभ्यर्थी भी अब विशेषज्ञ डॉक्टर बनने के योग्य हो गए हैं! मेरिट में चयन के आधार में इस तरह की मजबूरी आखिर क्यों? यह तो सीधे तौर पर भविष्य के विशेषज्ञ चिकित्सकों की दक्षता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। ऐसा समझौता जन-स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ही साबित होगा। आंकड़े बताते हैं कि कई सरकारी मेडिकल कॉलेज 30 प्रतिशत तक रिक्त फैकल्टी पदों के साथ काम कर रहे हैं। कई प्राइवेट कॉलेज में केवल कागजों पर शिक्षकों का नाम चल रहा है।

अपर्याप्त शिक्षण और सीमित रोगी भार वाले संस्थानों से निकलने वाले चिकित्सकों को वह गहन और व्यावहारिक प्रशिक्षण नहीं मिल पाता जो इस पेशे की रीढ़ है। मानक से ज्यादा चिकित्सक तैयार करना, खासकर जब यह शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता करके हो, तो आने वाले समय में नौकरी की अनिश्चितता मुश्किल खड़ी कर सकती है। फिर निजी कॉलेजों और सरकारी कॉलेजों के मैनेजमेंट कोटे में एमबीबीएस कोर्स की फीस 50 लाख से 1.25 करोड़ रुपए तक पहुंच रही है। आज सिर्फ एमबीबीएस से काम नहीं चलता। पीजी में मैनेजमेंट कोटे की बात करें तो फीस सीधे करोड़ों में है।

हमें संख्याबल नहीं, बल्कि दक्षता की सुनिश्चितता चाहिए। चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता से समझौता, आगे चलकर समाज के स्वास्थ्य के साथ समझौता है। यदि उच्च गुणवत्ता के तय मानकों को जमीनी स्तर पर सही ढंग से लागू नहीं किया गया और केवल संख्या बढ़ाने पर ही जोर रहा, तो हमारे डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात में सुधार होने के बावजूद चिकित्सा सेवा का स्तर गिरना तय है, जिसकी कीमत हम सबको चुकानी पड़ेगी।

आपकी बात

विकास के नाम पर वृक्ष काटना गलत

एक ओर सरकार पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित करती है, वहीं दूसरी ओर सरकार सोलर एनर्जी उत्पादन के लिए बडी संख्या में प्लांट लगाने के लिए वनों में खेजड़ी जैसे वृक्षों को भी काटने से नहीं चूक रही है। खेजड़ी वृक्ष की सुरक्षा के लिए एक्ट लागू किया जाना चाहिए। पर्यावरण जीवित रहेगा तो भावी पीढ़ियों की कल्पना की जा सकती है। - **अजीतसिंह सिसोदिया,** खारा-बीकानेर

युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृति

आजकल के युवाओं में आत्महत्या की प्रवृति बढ़ रही है, जो सामाजिक दृष्टिकोण से घातक होने जा रही है। आज युवा सहनशीलता के अभाव, नशा खोरी, ऑनलाइन गेमिंग, अवसाद आदि के कारण अपने अमूल्य जीवन से हाथ धो बैठता है। हमारे युवा वर्ग को जीवन का मूल्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाने की सख्त आवश्यकता है। - **कैलाश चंद्र मोदी,** सादुलपुर

अपने बच्चों के साथ समय बिताएं

अब बच्चों को मोबाइल की इतनी लत गई है कि उनको न खाने का पता है, न पढ़ने का और न ही सोने का। बच्चे मोबाइल में कौनसी ऐप्लीकेशन उपयोग कर रहे हैं और कौन-सा गेम खेल रहे हैं, माता-पिता को पता नहीं होता। उन्हें समय निकालकर अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए।उनके साथ गेम खेलना चाहिए। उनकी बातों को समझना चाहिए। - **प्रवेश भूतड़ा,** सूरत

आज का सवाल

गांव-कस्बों में खेल शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

मार्केट हमेशा सही नहीं होता, लेकिन वह आपको गलत जरूर साबित कर सकता है। बाजार में भावनाएं कीमत तय करती हैं, लेकिन अंत में फैक्ट्स जीतते हैं। **कार्ल इकान** अमरीकी बिजनेसमैन

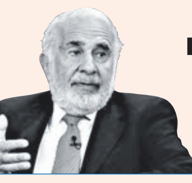

पत्रिका फाइनेंस

@बिजनेस & वेल्थ

रेवेन्यू मीटर...
ये कंपनियां नकदी की राजा, इनके पास सबसे ज्यादा कैश

(सालाना फ्री कैश-फ्लो (नकदी) करोड़ रुपए में)

भारती एयरटेल	ओएनजीसी	टीसीएस	रिलायंस	इंफोसिस
58,990	50,154	45,000	41,000	33,457

वित्तीय सुरक्षा... @पत्रिका इंफोग्राफिक्स

सोने की मांग की तस्वीर बदली

सोना अब सिर्फ शौक नहीं, निवेश विकल्प बना

जयपुर@पत्रिका. सोने की मांग और आपूर्ति की तस्वीर अब लगातार बदल रही है। 2025 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में उत्पादित और रीसायकल किए गए सोने का सबसे बड़ा हिस्सा अब निवेश के रूप में उपयोग हो रहा है। कुल सोना मांग में निवेश की हिस्सेदारी 43.5% है, जो यह संकेत देती है कि सोना आभूषण से अधिक एक सुरक्षित वित्तीय संपत्ति के रूप में देखा जा रहा है। इसके बाद 32.7% हिस्से के साथ ज्वैलरी सेक्टर आता है, जहां उपभोक्ता मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है।

आखिर कहां जा रहा है दुनिया का सोना?

	हिस्सेदारी	खरीद
निवेश	43.5%	2,175.3
ज्वैलरी	32.7%	1,638.0
केंद्रीय बैंक	17.2%	863.3
तकनीकी उपयोग	6.6%	325.7

सोने की खरीद टन में

सोने की कुल आपूर्ति

खदान उत्पादन	71.93%	3,598.0
रीसायकल सोना	28.07%	1,403.0

निवेश में सोने का उपयोग

1374 फिजिकल गोल्ड (बार, सिक्के, मेडल)
801.2 पेपर गोल्ड (ईटीएफ व शेयर बाजार आधारित)

नोट: आंकड़े वर्ष 2025 के वैश्विक सोना मांग-आपूर्ति के हैं।
स्रोत: वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल

सोने-चांदी की कीमत में गिरावट जारी

नई दिल्ली @ पत्रिका. सोने-चांदी की कीमतों में शुक्रवार को भी गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आइबीजेए) के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत 425 रुपए कम होकर 1,52,075 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं चांदी 9400 रुपए कम होकर 2,44,950 रुपए प्रति किलो रही। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी में मिलाजुला कारोबार हुआ है।

रेपो रेट 5.25% पर स्थिर ग्रोथ आउटलुक पर आरबीआइ का भरोसा कायम...

ब्याज दरों में राहत नहीं, लेकिन बचत और निवेश के मौके बरकरार

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौद्रिक नीति की समीक्षा में ब्याज दरों को यथावत रखते हुए रेपो रेट 5.25 प्रतिशत पर बनाए रखा है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक को देश की आर्थिक वृद्धि पर भरोसा है। आरबीआइ ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है, जो घरेलू मांग, निजी उपभोग, स्थिर पूंजी निवेश और सेवा क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन के संकेत देता है। हालांकि वैश्विक मोर्चे पर चुनौतियां बनी हुई हैं और नेट एक्सपोर्ट पर दबाव नजर आ रहा है। इसके बावजूद हाल में हुए व्यापार समझौते बाजारों के विस्तार और निर्यात के विविधीकरण में सहायक साबित हो सकते हैं।

बचत करने वालों पर असर

महंगाई के अनुमान कम हुए हैं, लेकिन ब्याज दरों में नई कटौती नहीं हुई। इसलिए अगले कुछ समय में एफडी की ब्याज दरें और अच्छे बॉन्ड की यील्ड बहुत ज्यादा गिरने की संभावना कम है। यह समय फिक्स्ड इनकम में जरूरत के हिसाब से अच्छी यील्ड लॉक करने का हो सकता है।

लोन री-फाइनेंस का मौका...
ब्याज दर न घटने से कर्ज की ईएमआइ में तुरंत नई राहत नहीं मिलेगी। लेकिन पहले जो कटौती हुई है, उसका फायदा धीरे-धीरे मिलता रहेगा। अच्छे क्रेडिट वाले लोगों के लिए लोन री-फाइनेंस या बेहतर दर पाने के मौके अब भी बने रहेंगे।

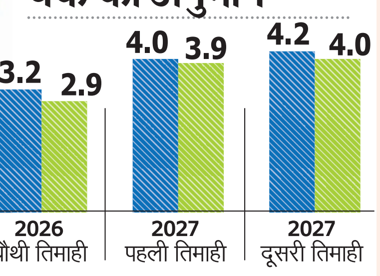

एसडीएफ दर भी **5.00% पर** रही

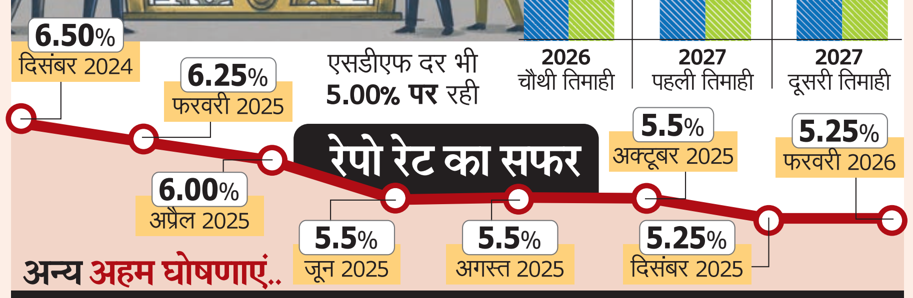

अन्य अहम घोषणाएं..

- **चालू वित्त वर्ष में रिटेल महंगाई 2.1% रहने का अनुमान।**
- **एमएसएमई के लिए बिना गारंटी लोन की सीमा 20 लाख हुई।**
- **अगली एमपीसी बैठक 6-8 अप्रैल 2026 को**

कृषि उत्पादन में सुधार

गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि आने वाले समय में देश की महंगाई और आर्थिक वृद्धि (ग्रोथ) का आउटलुक सकारात्मक बना हुआ है। घरेलू मांग में लगातार हो रही बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था को मजबूत सहारा मिल रहा है। उनका कहना है कि रबी फसलों की बेहतर बुआई से कृषि उत्पादन में सुधार संभव है, जो ग्रामीण मांग और समग्र अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है।

एनबीएफसी के लिए ढील: जो नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां पब्लिक फंड नहीं लेतीं और ग्राहकों से सीधा संपर्क नहीं रखतीं, अगर उनकी एसेट्स 1,000 करोड़ से कम हैं, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा, कुछ एनबीएफसी को 1,000 से ज्यादा ब्रांच खोलने के लिए पहले से अप्रूवल नहीं लेना होगा।

अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों को ताकत: शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए चार कदम उठाए जा रहे हैं। पहले दो अनसिक्योर्ड लोन और नॉमिनल मेंबर्स को लोन की लिमिट बढ़ाने पर। इसके अलावा, टियर-3 और टियर-4 यूसीबी के लिए हाउसिंग लोन में टेनर और मोरेटोरियम की शर्तें हटा दी जाएंगी।

रियल एस्टेट को ज्यादा कर्ज छोटे और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को राहत देते हुए आरबीआइ ने बिना गारंटी वाले लोन की सीमा दोगुनी करने का प्रस्ताव रखा। अभी 10 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के मिलता है, अब इसे 20 लाख तक बढ़ाया जाएगा। इससे छोटे दुकानदारों और फैक्टरियों को आसानी से पैसे मिलेंगे। उधर रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट देने के लिए बैंकों को रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट्स को लोन देने की इजाजत दी जाएगी।

स्टॉक मार्केट कोविड के बाद बदला ट्रेंड

कॉर्पोरेट टैक्स भरने में लिस्टेड आगे, अनलिस्टेड कंपनियां पीछे छूटीं

6,90,984 करोड़ रहा 2025 में कॉर्पोरेट टैक्स संग्रह

ऐसे बढ़ी हिस्सेदारी

वित्त वर्ष	अनलिस्टेड	लिस्टेड
2019	55.6%	44.4%
2021	45%	22%
2025	47%	53%

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

मुंबई. स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां टैक्स कलेक्शन में अनलिस्टेड कंपनियों को पीछे छोड़ रही हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में अनलिस्टेड कंपनियों का कुल कॉर्पोरेट टैक्स में हिस्सा घटकर 47% रह गया। यह हिस्सा 2019 में 55.6% था। कोविड-19 महामारी के समय लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियों के बीच कर भुगतान में बड़ा अंतर आया। 2021 में लिस्टेड कंपनियों ने टैक्स भुगतान में 22% की बढ़ोतरी की, जबकि अनलिस्टेड कंपनियों का टैक्स कलेक्शन 45% घट गया। इस कारण लिस्टेड कंपनियों का कुल कॉर्पोरेट टैक्स में हिस्सा 60.6% तक पहुंच गया, यह 18 साल का हाई था।

अनलिस्टेड कंपनियां फिर से मजबूत

जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था खुली, अनलिस्टेड कंपनियों ने तेजी से वापसी की। 2025 में उनका योगदान बढ़कर 47% हो गया, हालांकि यह महामारी से पहले 2019 के स्तर 55.6% से अभी भी कम है। ग्रांट थॉर्नटन भारत की पार्टनर रिचा साहनी का कहना है कि लिस्टेड कंपनियों को पूंजी जुटाने के बेहतर साधन मिलते हैं। अनलिस्टेड कंपनियां आमतौर पर छोटी होती हैं और अधिकतर बैंक लोन पर निर्भर रहती हैं। वहीं, लिस्टेड कंपनियों के पास बॉन्ड और इक्विटी मार्केट तक पहुंच होती है, जिससे वे निवेश बढ़ा सकती हैं, तकनीक में सुधार कर सकती हैं और लागत नियंत्रण कर सकती हैं।

आगे क्या?: विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आइपीओ गतिविधियां तेज रहीं, तो आने वाले वर्षों में लिस्टेड कंपनियों की टैक्स हिस्सेदारी और बढ़ सकती है। एमएसएमई और अनलिस्टेड सेक्टर के लिए सस्ती फंडिंग और क्रेडिट सपोर्ट अहम रहेगा।

रेकॉर्ड एयूएम चुनिंदा शेयरों की तेजी ने बढ़ाया जोखिम

म्यूचुअल फंड में जमकर आया पैसा, पर निवेशकों के रिटर्न में बड़ा अंतर

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. 2025 में भारत का म्यूचुअल फंड उद्योग का एयूएम बढ़कर रिकॉर्ड 81 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। मजबूत रिटेल भागीदारी और लगातार एसआइपी के चलते सालभर में करीब 14 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश आया, जिसमें लगभग 3 लाख करोड़ रुपए केवल एसआइपी के जरिए जुड़े। एम्फी के नवंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार 3.36 करोड़ नए निवेशकों ने म्यूचुअल फंड बाजार में प्रवेश किया, जिससे बाजार-आधारित निवेश उत्पादों की पहुंच भारतीय घरों तक और गहरी हुई। हालांकि इन मजबूत आंकड़ों के पीछे निवेशकों का अनुभव एक जैसा नहीं रहा। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार रेकॉर्ड एयूएम का मतलब यह नहीं है कि हर निवेशक को समान या सकारात्मक रिटर्न मिला हो। 2025 में निवेशकों के रिटर्न में बड़ा अंतर देखने को मिला है।

14 लाख करोड़ रुपए आए 2025 में...

03 लाख करोड़ रुपए एसआइपी के जरिए

70% शेयर 52-सप्ताह के निचले स्तर पर

ऊंचे वैल्यूएशन की मार कई निवेशक 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में तब बाजार में आए, जब वैल्यूएशन पहले से ऊंचे स्तर पर थे। ऐसे में, भले ही किसी फंड का एयूएम सालभर में 20 प्रतिशत बढ़ा हो, लेकिन ऊपरी स्तर पर निवेश करने वाले निवेशकों को साल के अंत तक सीमित या नकारात्मक रिटर्न भी देखने पड़े, जबकि लंबे समय से निवेशित लोग पूरे ग्रोथ साइकल का लाभ उठा सके।

तेजी केवल कुछ सेक्टर तक सीमित ...

2025 की सबसे बड़ी विशेषता सेक्टर और मार्केट कैप के आधार पर रिटर्न में भारी अंतर रहा। निफ्टी 50 भले ही नए रेकॉर्ड स्तर पर पहुंचे, लेकिन बाजार की तेजी कुछ चुनिंदा बड़े शेयरों तक सीमित रही।

एलोकेशन का महत्व...

2025 में फंड या शेयर चयन से ज्यादा अहम भूमिका एसेट एलोकेशन की रही। इक्विटी, डेट और गोल्ड का संतुलित मिश्रण रखने वाले निवेशकों को अपेक्षाकृत स्थिर और बेहतर रिटर्न मिला। गोल्ड ने अस्थिर बाजार में पोर्टफोलियो को सहारा दिया।

आरएंडडी शोधकर्ताओं की हायरिंग में आई तेजी...

आइआइटी के पीएचडी रिसर्चर अब ग्लोबल कंपनियों की रडार पर

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आइआइटी) से पीएचडी कर चुके शोधकर्ताओं की मांग अब तेजी से कॉरपोरेट सेक्टर में बढ़ रही है। कंपनियां अब केवल मैनेजमेंट या सामान्य इंजीनियरिंग भूमिकाओं तक सीमित नहीं रहना चाहतीं, बल्कि हाई-एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्रोडक्ट इनोवेशन के लिए शीर्ष शोध प्रतिभाओं को सीधे अपने साथ जोड़ रही हैं। यह बदलाव संस्थानों और उद्योगों, दोनों के भीतर इन-हाउस आरएंडडी को मजबूत करने की रणनीति का नतीजा माना जा रहा है। आइआइटी खड़गपुर, कानपुर, गुवाहाटी, रुड़की और बीएचयू जैसे संस्थानों में यह ट्रेंड साफ नजर आने लगा है। प्रोफेसरों और प्लेसमेंट सेल के अनुसार, पहले जहां पीएचडी छात्रों का मुख्य रुझान शिक्षण और अकादमिक करियर की ओर होता था, वहीं अब बड़ी संख्या में छात्र कॉरपोरेट ऑफर्स स्वीकार कर रहे हैं।

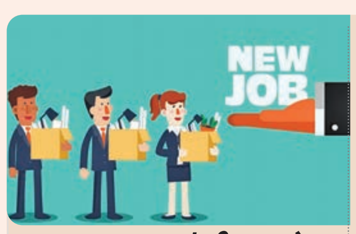

इन-हाउस आरएंडडी पर जोर: ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर की कंपनियां अपने इन-हाउस आरएंडडी को मजबूत कर रही हैं।

इन कंपनियों ने बढ़ाई हायरिंग
टाटा स्टील, एएमडी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, सीडीएसी, सीमेंस, एलएंडटी

करोड़ों रुपए के सालाना पैकेज

खास बात यह है कि कई मामलों में पीएचडी छात्रों को करोड़ों रुपए के सालाना पैकेज तक ऑफर किए जा रहे हैं। आइआइटी खड़गपुर में पहली बार दो पीएचडी छात्रों को कॉरपोरेट सेक्टर से सीधे जॉब ऑफर मिले हैं, वह भी जापान की कंपनी की ओर से। यह इस बात का संकेत है कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भी भारतीय शोध प्रतिभाओं को गंभीरता से देख रही हैं।

प्लेसमेंट ट्रेंड में बदलाव प्लेसमेंट कंपनियों के अनुसार इस साल कंपनियां खास तौर पर रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोफाइल के लिए पीएचडी छात्रों को टारगेट कर रही हैं। पीएचडी छात्रों को स्पेशलाइज्ड एरिया में हाई-एंड आरएंडडी जॉब्स मिल रही हैं, कई बार यह प्लेसमेंट सुपरवाइजर के जरिए या लेटरल रूट से हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ट्रेंड भारतीय उच्च शिक्षा और उद्योग जगत के लिए सकारात्मक संकेत है।

बाजार 8500 करोड़ जुटाने की तैयारी

आइपीओ बाजार गर्म, सेबी ने 6 कंपनियों को दी हरी झंडी

सेबी से मंजूरी पाने वाली कंपनियां

कंपनी	मंजूरी की तारीख	आइपीओ राशि
लेजर पावर	2 फरवरी	1200
आर्डी इंडस्ट्रीज	3 फरवरी	320
आरवी इंजीनियरिंग	4 फरवरी	202.5
एलिवेट कैंपसेज	5 फरवरी	2550
इनक्रेड होल्डिंग्स	5 फरवरी	4000
अर्मी इन्फोटेक	6 फरवरी	300

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

मुंबई. पूंजी बाजार नियामक सेबी (सेबी) ने फरवरी के पहले सप्ताह में कई कंपनियों के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस पर अलग-अलग तारीखों में अपनी मंजूरी जारी की है। सेबी की यह मंजूरी मिलने के बाद अब ये कंपनियां रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) दाखिल कर अपना आइपीओ लाने की प्रि या शुरू कर सकती हैं। सेबी ने 2 फरवरी को लेजर पावर एंड इंफ्रा, 3 फरवरी को आर्डी इंडस्ट्रीज, 4 फरवरी को आरवी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स, 5 फरवरी को एलिवेट कैंपसेज और इनक्रेड होल्डिंग्स के ड्राफ्ट दस्तावेज मंजूर कर दिए हैं।

आइपीओ लॉन्च के लिए तय समय-सीमा

सेबी के नियमों के अनुसार, सामान्य प्रक्रिया से डीआरएचपी दाखिल करने वाली कंपनियों को एक वर्ष के भीतर अपना आइपीओ लाना होता है। वहीं, कॉन्फिडेंशियल रूट से दस्तावेज दाखिल करने वाली कंपनियों को 18 महीने के भीतर पब्लिक इश्यू लॉन्च करने की अनुमति मिलती है।

परिणाम

एनएसई का मुनाफा 37 प्रतिशत गिरा

मुंबई@ पत्रिका. आइपीओ लाने की तैयारी कर रही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए, जिसमें कंपनी ने कहा कि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 37 प्रतिशत कम होकर 2,408 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 25 की समान अवधि में 3,834 करोड़ रुपए था। तिमाही-दर-तिमाही कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 15 प्रतिशत बढ़ा है।

कमोडिटी भारत के सबसे बड़े खरीदार ने बदला रुख

गेहूं पर राजनीति: अमरीका-बांग्लादेश समझौते से भारत के एक्सपोर्ट पर दबाव

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. बांग्लादेश ने अमरीका से गेहूं की खरीद शुरू कर दी है। 5 फरवरी को गेहूं की एक बड़ी खेप अमरीका से चटगांव पोर्ट पहुंची। हजारों क्विंटल गेहूं से लदा अमरीकी जहाज जैसे ही बांग्लादेश पहुंचा, वैसे ही चर्चा ये शुरू हो गई कि अब भारत के गेहूं का क्या होगा। बांग्लादेश, भारत के गेहूं का बड़ा खरीदार रहा है। 2022 में पूरी दुनिया में भारत ने जितना गेहूं निर्यात किया, उसका 50% हिस्सा बांग्लादेश को भेजा गया।

भारत के एक्सपोर्ट का बुरा हाल: 2020-21 में, भारत ने बांग्लादेश को 1,157,399 टन गेहूं एक्सपोर्ट किया था। 2022 में बैन के बाद भी एक्सपोर्ट की इजाजत दी, जिसमें 1.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं शामिल था। अब स्थिति गंभीर हो सकती है।

अमरीका से हुआ करार

गेहूं खरीद के लिए अमरीका और बांग्लादेश के बीच एक एमओयू किया गया है, जिसमें बांग्लादेश ने पांच सालों तक हर साल 700,000 मीट्रिक टन (25.7 मिलियन बुशेल) अमरीकी गेहूं खरीदने का वादा किया है। इसी के साथ बांग्लादेश अमरीकी गेहूं के लिए आठवां सबसे बड़ा बाजार बन गया है। 22 जनवरी, 2026 तक, बांग्लादेश ने लगभग 675,000 मीट्रिक टन (24.8 मिलियन बुशेल) अमरीकी गेहूं खरीदा है।

रिजर्व बैंक

विदेशी मुद्रा भंडार ऑल-टाइम हाई पर

मुंबई@ पत्रिका. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 30 जनवरी को समाप्त हुए हफ्ते में 14.361 अरब डॉलर बढ़कर ऑल-टाइम हाई 723.774 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। यह जानकारी शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए डेटा में दी गई। इससे पहले के हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार में 8.053 अरब डॉलर की बढ़त देखी गई थी। विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी की वजह सोने की कीमतों में तेजी आना है। 30 जनवरी को समाप्त हुए हफ्ते में मुद्रा भंडार के अहम घटक गोल्ड रिजर्व की वैल्यू 14.595 अरब डॉलर बढ़कर 137.683 अरब हो गई है।

रूस: ठंड से जमी नदी तो आइस हॉकी की जमकर प्रैक्टिस

सेंट पीटर्सबर्ग. रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में कड़ाके की ठंड के बीच महिलाओं की एक आइस हॉकी टीम ने शुक्रवार को जमी हुई फॉनटांका नदी पर अभ्यास किया। खिलाड़ी स्केट्स पहनकर ट्रेनिंग करती नजर आईं।

डिजिटल दौर तीन अंकों का स्कोर आपकी वित्तीय पहचान, भुगतान की आदतें तय करेंगी आपके मौके

बीमा से भर्ती तक: हर जगह असर दिखाने लगा क्रेडिट स्कोर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मुंबई. अब क्रेडिट स्कोर केवल लोन लेने या क्रेडिट कार्ड की मंजूरी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह बीमा, भर्ती, स्टॉक ब्रोकिंग और टेलीकॉम सेवाओं जैसे कई अहम क्षेत्रों में फैसलों का आधार बनता जा रहा है। तीन अंकों का यह स्कोर अब किसी व्यक्ति की वित्तीय अनुशासन, भुगतान क्षमता और जोखिम प्रोफाइल का संकेतक माना जाने लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था और डेटा एनालिटिक्स के दौर में क्रेडिट स्कोर की भूमिका लगातार व्यापक होती जा रही है।

कम शर्त पर पॉलिसी

बीमा कंपनियां अब बेहतर क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को कम प्रीमियम और बेहतर शर्तों पर पॉलिसी ऑफर कर रही हैं। माना जा रहा है कि मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल वाले ग्राहक दावे कम करते हैं और भुगतान में अनुशासित रहते हैं।

ब्रोकिंग में अहमियत

स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियां क्रेडिट स्कोर के आधार पर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की पात्रता तय कर रही हैं। अच्छे स्कोर वाले निवेशकों को ज्यादा क्रेडिट लिमिट और बेहतर शर्तें मिल सकती हैं।

बैंक और एनबीएफसी का भरोसा बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां पहले से ही क्रेडिट स्कोर को लोन अप्रूवल का आधार मानती हैं, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ गया है। बेहतर स्कोर का मतलब है कम ब्याज दर, ज्यादा लोन राशि और तेज मंजूरी। वहीं, कमजोर स्कोर वाले उधारकर्ताओं को सख्त शर्तों का सामना करना पड़ता है।

क्रेडिट स्कोर क्यों हो रहा है इतना अहम

विशेषज्ञों के अनुसार, क्रेडिट ब्यूरो की कवरेज बढ़ने और डिजिटल लेनदेन के विस्तार से स्कोर अधिक भरोसेमंद बन गया है। यह किसी व्यक्ति के वित्तीय व्यवहार का संक्षिप्त लेकिन प्रभावी प्रतिबिंब देता है, जिसे संस्थाएं जोखिम आकलन के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं।

स्कोर सुधारने के आसान उपाय: वित्तीय सलाहकारों का कहना है कि क्रेडिट स्कोर बनाए रखने के लिए कुछ बुनियादी बातों का ध्यान जरूरी है। क्रेडिट लिमिट का 40% से कम उपयोग, समय पर ईएमआई और बिल भुगतान, बार-बार अनावश्यक लोन या कार्ड के लिए आवेदन से बचना और समय-समय पर अपना क्रेडिट स्कोर जांचना।

जिम्मेदारी भी बढ़ी: हालांकि, क्रेडिट स्कोर का बढ़ता इस्तेमाल कुछ सवाल भी खड़े करता है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि स्कोर का अंधाधुंध उपयोग भेदभाव को जन्म दे सकता है। इसलिए जरूरी है कि संस्थाएं पारदर्शिता और उचित नियमों के तहत इसका इस्तेमाल करें। कुल मिलाकर, बदलते दौर में क्रेडिट स्कोर एक तरह से व्यक्ति की च्वित्तीय पहचानज् बनता जा रहा है।

पेज एक का शेष...

सोशल मीडिया ...

जानकार सूत्रों ने बताया कि आर्थिक सर्वे में बच्चों पर डिजिटल प्रदूषण पर चिंता जताए जाने के बाद से यह मुद्दा विचारणीय था लेकिन गाजियाबाद में सोशल मीडिया लत व ऑनलाइन गेमिंग के कारण तीन सगी बहनों की आत्महत्या को देश के नीति निर्माताओं की चर्चा का ट्रिगर पॉइंट माना जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण-26 में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते प्रभाव और युवाओं की मानसिक सेहत पर उसके असर को लेकर चिंता जताते हुए बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की दिशा में ठोस नीति बनाने का सुझाव दिया गया था।
आगे क्या हो सकता है?: सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार आयु सत्यापन, पैरेंटल कंट्रोल, और प्लेटफॉर्म की जवाबदेही जैसे विकल्पों पर विचार कर रही है। बड़ा सवाल यह भी है कि कोई नियंत्रण नीति बनाने से पहले उस पर अमल सुनिश्चित करने के लिए फूल प्रूफ तकनीकी जरूरी होगी। बच्चों के सोशल मीडिया पर पूर्णतः बैन पर हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन संकेत साफ हैं कि बच्चों की डिजिटल सुरक्षा अब नीति-निर्माण का बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है।
गोवा-आंध्र प्रदेश कर रहे अध्ययन: देश में गोवा और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए पहले कदम के रूप में समितियां गठित की हैं जो ऑस्ट्रेलिया के कानून का अध्ययन कर रही हैं। सरकारों ने माता-पिता की बच्चों के सोशल मीडिया में व्यस्त रहने की शिकायतों के लगातार वृद्धि के बाद कदम उठाया गया है।

डिजिटल लेन...

उन्होंने कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी में 50 हजार रुपए तक की राशि वाले मामले 65% होते हैं। मल्होत्रा ने कहा कि लोन रिकवरी एजेंटों के खिलाफ शिकायतों को देखते हुए आरबीआइ जल्द मॉडल गाइडलाइन बनाएगा।

नोएडा के...

उसका फोन बंद मिला। करण ने आरोप लगाया कि परिजन रात भर उसकी तलाश में कई थानों के चक्कर काटते रहे, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की। इसके बाद सुबह करीब 7 बजे पुलिस ने फोन कर शव मिलने की सूचना दी।